चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

30 मार्च –05 अप्रैल 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

बिहार विधानसभा चुनाव पर चौथी दुनिया का पहला सर्वे

नीतीश सबसे आगे

सभी फोटो– *प्रभात पाण्डेय*

[बिहार विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है. इस वजह से यहां चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. राज्य में पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी. लेकिन इस बार नीतीश का सीधा मुकाबला भाजपा से ही है. मतलब कल के दोस्त आज राजनीतिक दुश्मन हो गए हैं और कल के दुश्मन आज के राजनीतिक हमसफर. सही कहा जाता है कि राजनीति में कभी भी कोई रिश्ता स्थाई नहीं होता. इसका जीता-जागता उदाहरण बिहार की मौजूदा परिस्थिति के रूप में सभी के सामने है, जहां लालू और नीतीश ने भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए राजनीतिक बिसात बिछा ली है, लेकिन जनता-जनार्दन का फैसला सर्वोपरी होता है. ऐसे में चौथी दुनिया ने जनता के रुख को भांपने की कोशिश की, जहां नीतीश शुरुआती बढ़त लेते दखाई दे रहे हैं.]

चौथी दुनिया ब्यूरो

बिहार का आगामी विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है. यह जटिलतम के साथ-साथ भविष्य की राजनीति का रास्ता निर्धारित करने वाला साबित होगा. विजेता कौन होगा, यह तो नतीजा आने के बाद ही पता चल पाता है, लेकिन हर कोई यही जानने के लिए उत्सुक है कि चुनाव का नतीजा आख़िर होगा क्या? बिहार में पिछले दो-तीन सालों में काफी राजनीतिक उठापटक हुई है. भाजपा-जदयू का गठबंधन टूटा, नीतीश और मोदी का राजनीतिक द्वंद्व हुआ, लालू यादव को सजा हो गई और वह फिलहाल चुनावी राजनीति से बाहर हो गए. लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया. जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया. फिर मांझी बेलगाम हो गए. जब भी वह बोलते, पार्टी और सरकार की किरकिरी होती. काफी जद्दोजहद के बाद मांझी को हटाया गया. नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने. इस बीच भारतीय जनता पार्टी की चुनौती से निपटने के लिए नीतीश कुमार और लालू यादव ने एकजुट होने का फ़ैसला किया है. विलय की प्रक्रिया जारी है. इतना उलटफेर किसी दूसरे राज्य की राजनीति में नहीं हुआ. इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव सबसे दिलचस्प हो जाता है. बिहार में जनता का मूड क्या है? मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे कौन है? क्या भाजपा चुनाव जीत पाएगी? क्या बिहार का चुनाव भी दिल्ली की तरह होने वाला है? मांझी फैक्टर का क्या असर होगा? यदि लालू और नीतीश कुमार एक साथ चुनाव लड़ते हैं, तो क्या होगा? दोनों अलग-अलग लड़ते हैं, तो क्या होगा? बिहार में इस बार चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या होगा? ऐसे कई सवाल हैं, जिन पर जनता की राय जानने के लिए चौथी दुनिया ने बिहार में एक सर्वे किया.

चौथी दुनिया का यह सर्वे 14 से 17 मार्च, 2015 के बीच किया गया. इस दौरान हमारी टीम राज्य के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं से मिली और उनसे विभिन्न मुद्दों से जुड़े सवाल-जवाब किए. मतदाताओं के जवाबों को ही हमने अपने सर्वे के आधारभूत आंकड़ों के रूप में इस्तेमाल किया. इसके अलावा पिछले चुनावों में मतदाताओं के वोटिंग पैटर्न और चुनाव आयोग के आंकड़ों की भी मदद ली गई. सर्वे में सैंपल के लिए हमने मल्टीस्टेज स्ट्रेटीफाइड रैंडम सैंपलिंग तकनीक की मदद ली. सर्वे के दौरान हमने इस बात का खास ध्यान रखा कि राज्य के सभी हिस्सों के मतदाताओं के मिजाज को अहमियत मिले. इनमें महिलाएं, युवा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और सवर्ण आदि सभी शामिल थे. इस सर्वे में हमने 122 विधानसभा क्षेत्रों में 12,200 लोगों से सवाल पूछे. सैंपल का साइज और तकनीक देखते हुए कहा जा सकता है कि यह सर्वे आम चुनावी सर्वे से ज़्यादा विश्वसनीय और तार्किक है. हमने काफी गहन विचार करने के बाद तय किया कि इस सर्वे में यह बताना उचित नहीं होगा कि किस पार्टी या गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी. इसकी वजह यह है कि चुनाव में अभी काफी वक्त बचा है. इस सर्वे के पीछे हमारा मकसद था, बिहार की जनता का मिजाज यानी मूड का आकलन करने की कोशिश. इस सर्वे के ज़रिये हमने यह पता करने की कोशिश की है कि मूल राजनीतिक सवालों पर बिहार की जनता क्या सोच रही है. इस सर्वे में यह समझने की कोशिश की गई है कि पिछले दो सालों में हुई राजनीतिक उठापटक का जनता पर क्या असर हुआ है. यह सर्वे बिहार की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति और वर्तमान में घट रही घटनाओं पर बिहार की जनता की समग्र राय प्रस्तुत करती है.

चौथी दुनिया के इस सर्वे के मुताबिक, नीतीश कुमार बिहार के बेताज बादशाह हैं और उनकी किसी भी दूसरे नेता के साथ कोई प्रतियोगिता नहीं है. लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बावजूद बिहार की जनता आज भी नीतीश कुमार पर भरोसा करती है. इस सर्वे से यह साफ़-साफ पता चलता है कि बिहार के मतदाता काफी सोच-समझ कर वोट करते हैं. जनता के मूड से पता चलता है कि बिहार की हालत भी दिल्ली की तरह है. जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट दिया था, वे भी बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार को सौंपना चाहते हैं. बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यह है कि

(शेष पृष्ठ 2 पर)

मुख्यमंत्री पद के लिए आपकी पहली पसंद कौन?

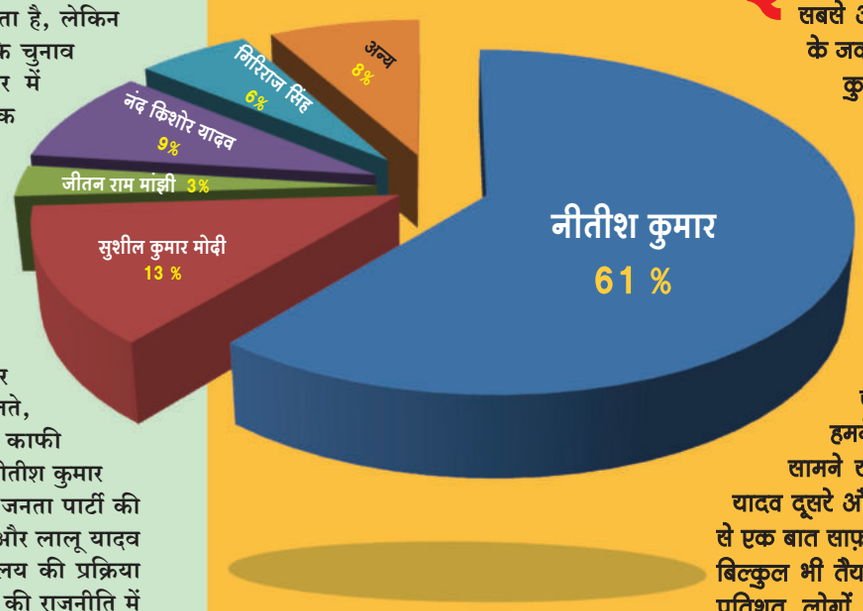

इस सवाल के जवाब में नीतीश कुमार पहले नंबर पर रहे. जबकि भारतीय जनता पार्टी के तीन नेताओं में सबसे अधिक वोट सुशील मोदी को मिले. इस तरह के जवाब इसलिए भी सामने आते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से राजनीतिक दल अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार पहले ही घोषित कर देती हैं. दिल्ली विधानसभा चुनाव इसका उदाहरण है. बिहार में नीतीश कुमार पहले भी मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार रहे हैं. इसका फ़ायदा उन्हें इस सर्वे में भी मिलता दिख रहा है. चूंकि भाजपा ने अभी तक अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, इस वजह से लोगों के सामने कोई ठोस विकल्प नहीं है. हमने इस सर्वे में भाजपा की ओर से जो तीन नाम सामने रखे, उनमें सुशील मोदी पहले, नंद किशोर यादव दूसरे और गिरिराज सिंह तीसरे नंबर पर रहे. इस सर्वे से एक बात साफ़ हुई कि जनता जीतन राम मांझी के नाम पर बिल्कुल भी तैयार नहीं दिख रही. अन्य, जिनके लिए आठ प्रतिशत लोगों ने अपना मत दिया, उनमें राबड़ी देवी, शाहनवाज हुसैन एवं राम विलास पासवान आदि शामिल हैं. ■

अराजकता और अनियमितता का अड्डा
पेज-05

कहीं खुशी कहीं गम
पेज-07

साई की महिमा
पेज-12

रिकॉर्ड्स का विश्वकप
पेज-15

बिहार विधानसभा चुनाव पर चौथी दुनिया का पहला सर्वे

नीतीश सबसे आगे

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

पृष्ठ एक का शेष

क्या नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद त्याग कर ग़लती की? क्या जनता इसके लिए नीतीश कुमार को सजा देगी? क्या मांझी सरकार की ग़लतियों का खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा? चौथी दुनिया के सर्वे के मुताबिक़, नीतीश कुमार के इस्तीफ़े को बिहार की जनता ग़लत मानती है. अगर नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री न बनते, तो शायद उन्हें चुनाव में जनता के क्रोध का सामना करना पड़ता. इस सर्वे से ऐसा प्रतीत होता है कि जनता ने नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने के फ़ैसले का स्वागत किया है. वजह, इससे जनता को खासी राहत मिली है, क्योंकि यह सर्वे बताता है कि आज भी बिहार में क़ानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है. लोगों की आशा बंधी हुई है कि नीतीश कुमार बिहार में सुशासन कायम कर सकते हैं. यही भरोसा नीतीश कुमार को किसी भी दूसरे नेता से आगे खड़ा करता है.

चौथी दुनिया के सर्वे के मुताबिक, अगर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक हो जाते हैं यानी जनता परिवार का प्रयोग सफल हो जाता है और दोनों एक साथ, एक सिम्बल पर चुनाव लड़ते हैं, तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोका जा सकता है. इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक सबक है. भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद को लेकर भ्रम की स्थिति (कन्फ्यूजन) बरकरार है. पार्टी में मुख्यमंत्री पद के कई उम्मीदवार हैं. सुशील कुमार मोदी, नवल किशोर यादव, गिरिराज सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा, शाहनवाज हुसैन जैसे कई नेता हैं, जिनके नाम पर लोगों के बीच चर्चा होती है. इसी तरह के कन्फ्यूजन के चलते भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव हार गई. अरविंद केजरीवाल जैसे एक दमदार उम्मीदवार के सामने आख़िरी वक्त पर किरण बेदी को लाना भाजपा को महंगा पड़ा. अगर वैसी भ्रम की स्थिति बिहार में हुई, तो चुनाव नतीजे दिल्ली से अलग नहीं होने वाले हैं. चुनाव के वक्त जैसी लोकप्रियता केजरीवाल की दिल्ली में थी, उससे कहीं ज़्यादा नीतीश कुमार बिहार में लोकप्रिय दिखाई दे रहे हैं. इस सर्वे में हमने मतदाताओं से कुल 11 सवाल पूछे. ऐसे सवाल, जिनका सीधा असर मतदान पर होता है. चौथी दुनिया के शुरुआती सर्वे का नतीजा आपके सामने है. कुछ दिनों के बाद इन नतीजों में क्या बदलाव होता है, उसके बारे में भी हम आपको अपडेट करेंगे. अगले सर्वे में लोगों की राय के साथ–साथ किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे और कितनी सीटें मिलेंगी, हम यह भी बताएंगे.

अगर नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री न बनते, तो शायद उन्हें चुनाव में जनता के क्रोध का सामना करना पड़ता. इस सर्वे से ऐसा प्रतीत होता है कि जनता ने नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने के फ़ैसले का स्वागत किया है. वजह, इससे जनता को खासी राहत मिली है, क्योंकि यह सर्वे बताता है कि आज भी बिहार में क़ानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है. लोगों की आशा बंधी हुई है कि नीतीश कुमार बिहार में सुशासन कायम कर सकते हैं. यही भरोसा नीतीश कुमार को किसी भी दूसरे नेता से आगे खड़ा करता है.

इस चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या है?

इस सवाल के बदले मिले जवाब बताते हैं कि बिहार की जनता के लिए क़ानून व्यवस्था अभी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है. लालू यादव के जमाने में क़ानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई थी. जंगलराज की बात हाईकोर्ट तक ने कही थी. अपहरण यहां का उद्योग बन गया था, जिससे आम जनता बहुत परेशान थी. नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद इसमें सुधार होता दिखा. लोगों की जेब से पैसे बाहर निकलने लगे थे. छोटी संख्या में ही सही, लेकिन लघु उद्योग, खासकर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगने लगे. लेकिन, जीतन राम मांझी के नौ महीने के कार्यकाल में क़ानून व्यवस्था की हालत फिर से गड़बड़ाने लगी. लोगों को फिर से भय सताने लगा. इस सर्वे में जिन लोगों ने भी जवाब दिया, उनका स्पष्ट मानना था कि बिहार का विकास तभी संभव है, जबकि यहां क़ानून व्यवस्था दुरुस्त रहे. लोगों ने माना कि पिछले कुछ समय से आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं और एक बार फिर से रात में आवागमन मुश्किल हो गया. विकास भी यहां एक बड़ा मुद्दा है. सर्वे के दौरान लोगों ने माना कि नीतीश कुमार के शासनकाल में विकास की गति अच्छी थी, लेकिन पिछले कुछ समय से यह गति धीमी पड़ गई है. आश्चर्यजनक रूप से सबसे कम मत भ्रष्टाचार को मिले यानी महज 09 प्रतिशत. ■

आप वोट देते समय इनमें से किसे प्राथमिकता देंगे?

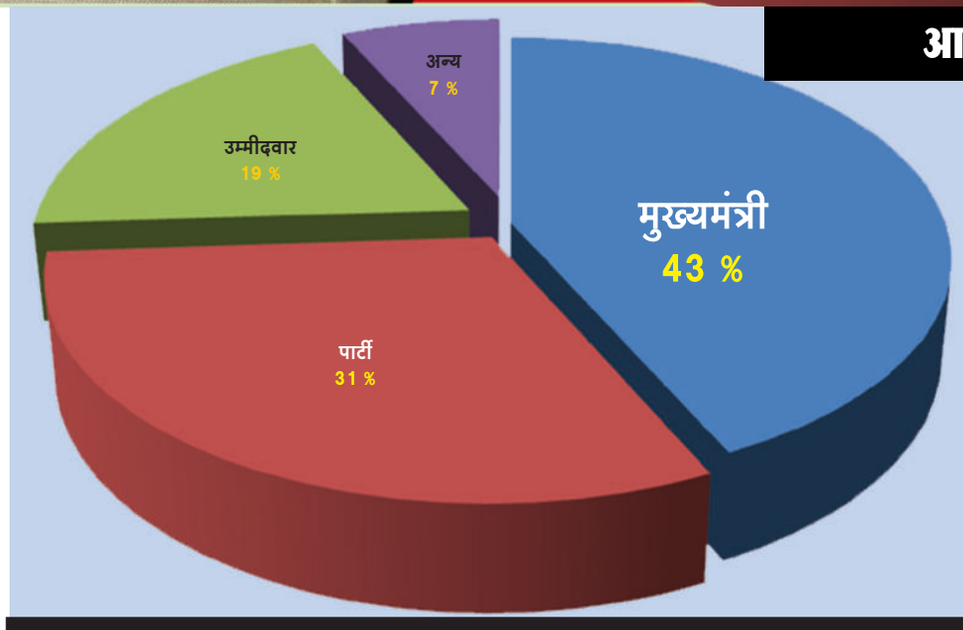

इस सवाल के जवाब में 43 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार देखकर अपना मतदान करेंगे. ऐसे लोगों का कहना था कि उनके पास ताजा उदाहरण हैं, नीतीश और मांझी. दोनों ही जदयू के थे, लेकिन नीतीश का कार्यकाल विकास के लिए जाना जाता है और मांझी का कार्यकाल केवल ग़लत बयानबाजी के लिए. मुख्यमंत्री अच्छा होगा, तो विकास भी होगा. 31 प्रतिशत लोगों का कहना था कि वे पार्टी को वोट करेंगे. अगर पार्टी भ्रष्ट होगी, तो फिर मुख्यमंत्री कोई भी हो, कुछ फ़र्क़ नहीं पड़ता. 19 प्रतिशत लोगों का कहना था कि वे उम्मीदवार देखकर मतदान करेंगे, क्योंकि वे किसी काम के लिए मुख्यमंत्री के पास तो जाएंगे नहीं. यदि उम्मीदवार सही होगा, तो उनके काम आसानी से हो जाएंगे. 07 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे अन्य मुद्दों पर मतदान करेंगे. इस सवाल के बदले मिले जवाब बताते हैं कि आज भी लोग मुद्दों से कहीं ज़्यादा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को तरजीह देते हैं और उनका मानना है कि अगर मुख्यमंत्री सही होगा, तो राज्य का विकास अवश्य होगा. ■

(शेष पृष्ठ 3 पर)

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 07 अंक 04
दिल्ली, 30 मार्च –05 अप्रैल 2015
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060, +91–8451050786, +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

दबाव में बिहार सरकार

आईएएस अधिकारी डीके रवि की संदिग्ध मौत पर बेंगलुरु में लोगों का प्रदर्शन किया. उनकी मौत को कर्नाटक में भू–माफियाओं के खिलाफ उनके द्वारा की गई कार्रवाई से भी जोड़ कर देखा जा रहा है. दूसरी तरफ केंद्र ने 2005 के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी कुलदीप नारायण का बिल्डरों और भू–माफियाओं के इशारे पर निलंबन पर बिहार सरकार से रिपोर्ट मांगी है. यह दूसरी बार है, जब केंद्र ने इस मसले पर रिपोर्ट मांगी है. हालांकि इस मामले में राज्य सरकार के जवाब से केंद्र संतुष्ट नहीं है. नारायण पटना नगर निगम के सीईओ और आयुक्त के पद पर रहते हुए राजधानी पटना में बिल्डरों और अवैध भवन निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे. इसी वजह से सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिसंबर में स्थानान्तरण कर दिया था. हालांकि उनके ट्रांसफर के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी. हालांकि सरकार ने उनके स्थानान्तरण की हर संभव कोशिश करती रही, लेकिन आखिरकार कोर्ट ने उनकी मंशा पर पानी फेर दिया. अब कार्मिक मंत्रालय भी कुलदीप के मुद्दे पर राज्य सरकार पर दबाव बढ़ा रहा है, जिसका हल ढूंढना नीतीश सरकार के लिए आसान नहीं है. ■

राजनीतिक ठिकरा नौकरशाही पर

आमतौर पर राजनीतिक निर्णयों का ठिकरा नौकरशाहों के सिर फोड़ा जाता है. जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा हुर्रियत के अलगाववादी नेता मशरत आलम को जेल से छोड़े जाने के निर्णय के लिए जम्मू सरकार ने गृह सचिव सुरेश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है. सरकार का कहना है कि प्रशासकीय लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है. मशरत की रिहाई के लिए सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था. हालांकि सुरेश कुमार के तबादले को 60 अन्य वरिष्ठ नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के तबादले से जोड़ कर देखा जा रहा है, ताकि सरकार के इस कदम पर कोई सवाल खड़ा न हो और राज्य की प्रशासनिक महकमे की नई तस्वीर प्रस्तुत की जा सके. कुमार को आईएमपीए का निदेशक बना दिया गया है और राज्य में उनके बदले किसी और अधिकारी को नहीं भेजा गया. हालांकि सूत्रों का कहना है कि राज्य की योजना और विकास सचिव बी आर शर्मा को गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. इस बात के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि अस्थाई रूप से गृह विभाग का संचालन कब तक जारी रहेगा. ■

JAMMU & KASHMIR

बिहार विधानसभा चुनाव पर चौथी दुनिया का पहला सर्वे

नीतीश सबसे आगे

फोटो–प्रभात पाण्डेय

क्या आप जाति, धर्म, समुदाय, भाषा और क्षेत्र के नाम पर वोट डालेंगे?

इस सवाल के जवाब में 16 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्हें अपनी जाति या धर्म से इतना अधिक लगाव है कि वे चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाते. दूसरी बात यह कि नेता भी अपनी जाति या समुदाय के लोगों की ज़्यादा सुनते हैं. 75 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे उम्मीदवार देखकर वोट देंगे, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से क्यों न हो. ऐसे लोगों का मानना था कि उन्हें अपने क्षेत्र का विकास चाहिए. जब अच्छी छवि का उम्मीदवार जीतकर आएगा, तो वह उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा. वहीं 09 प्रतिशत लोगों ने कहा कि इस बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, इसलिए वे इस सवाल पर चुप रहना पसंद करेंगे. ■

क्या लालू और नीतीश एक साथ मिलकर भाजपा का विजय रथ रोक पाएंगे?

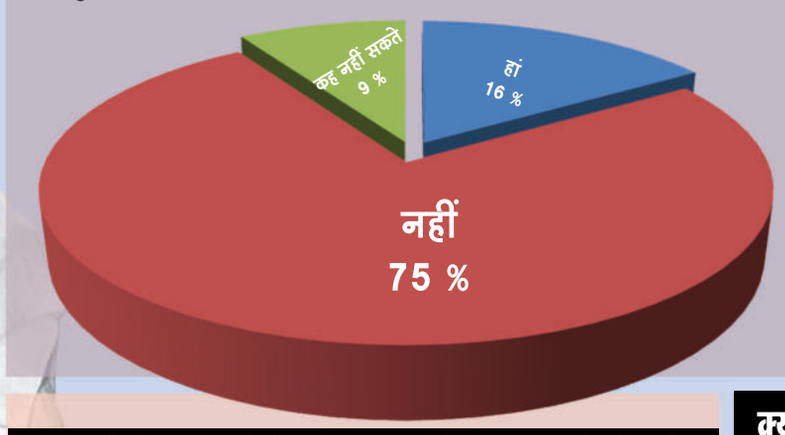

इस सवाल के जवाब में 47 प्रतिशत लोगों का कहना था कि जिस तरह विधानसभा की 10 सीटों के उपचुनाव में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी थी, वैसा ही हश्र उसका आगामी विधानसभा चुनाव में होगा. जिन 29 प्रतिशत लोगों ने भाजपा का विजय रथ न रुकने की बात कही, उनमें से अधिकांश पढ़े-लिखे, शहरी, मध्यम वर्ग और ऊंची जाति के थे या फिर ऐसे लोग थे, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट दिया था. 24 प्रतिशत लोग कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे. उनका मानना था कि यह तो समय बताएगा. उनके अनुसार, मुकाबला कांटे का है, क्योंकि भाजपा की स्थिति बिहार में पहले से ही बेहतर है. ■

क्या नीतीश ने मांझी को सत्ता सौंपकर ग़लती की थी?

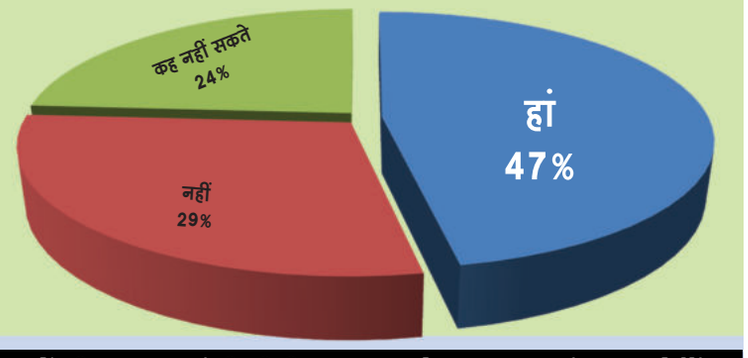

जब हमने यह सवाल किया, तो 71 प्रतिशत लोगों ने कहा कि मांझी को मुख्यमंत्री बनाना नीतीश कुमार की बहुत बड़ी भूल थी. उनकी इस ग़लती की वजह से बिहार की क़ानून व्यवस्था पटरी से उतर गई. उन्हें जनता के फ़ैसले का सम्मान करना चाहिए था. नीतीश ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, लेकिन अब उन्होंने अपनी भूल सुधार ली है. ज़्यादातर लोगों का मानना था कि नीतीश के दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही बदलाव दिखाई पड़ने लगा है. वहीं 11 प्रतिशत लोगों ने उनके मांझी को मुख्यमंत्री बनाने के फ़ैसले को सही ठहराया. 18 प्रतिशत लोगों की इस सवाल पर कोई राय नहीं थी. ■

क्या चुनाव में जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को नुक़सान पहुंचा सकते हैं?

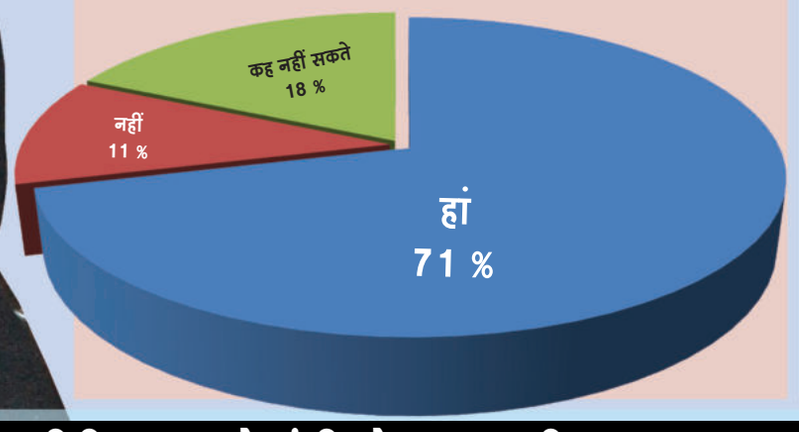

इस सवाल के जवाब में 73 प्रतिशत लोगों ने कहा कि बिल्कुल नहीं. उनका मानना था कि नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार की ज़िम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दिया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मांझी मुख्यमंत्री के तौर पर विफल रहे. मांझी सरकार के दौरान बिहार में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था. मांझी केवल बेतुके बयान देते फिर रहे थे. नीतीश कुमार द्वारा किए गए कार्यों पर भी उन्होंने पानी फेर दिया. मांझी से लोग पहले से ही नाराज हैं. वह नीतीश कुमार को चुनाव में कोई नुक़सान नहीं पहुंचा सकते. 13 प्रतिशत लोगों का कहना था कि मांझी नीतीश को थोड़ा-बहुत नुक़सान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि दलित समुदाय के लोग नीतीश से नाराज हैं और उनके वोटों का बंटवारा हो सकता है. 07 प्रतिशत लोगों का कहना था कि मांझी नीतीश को बहुत नुक़सान पहुंचा सकते हैं. ऐसे लोगों का मानना था कि नीतीश कुमार द्वारा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देना केवल एक दिखावा था और दलित कार्ड खेलने के लिए ही उन्होंने मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था. मांझी को बेइज्जत करके मुख्यमंत्री पद से हटाने से लोगों में नाराजगी है कि नीतीश ने ऐसा जानबूझ कर किया. 07 प्रतिशत लोगों ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया. कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकलता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को जीतन राम मांझी से फिलहाल कोई ख़तरा नहीं है. ■

क्या नीतीश कुमार ने मांझी को हटाकर सही क़दम उठाया?

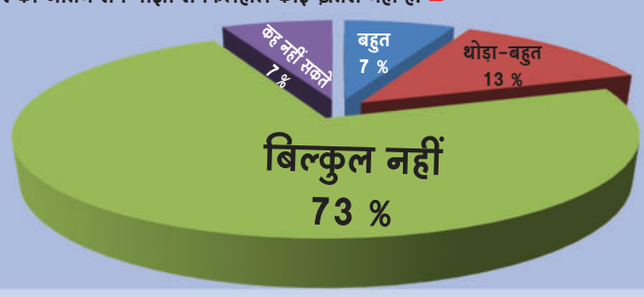

इस सवाल का जवाब देना लोगों के लिए शायद सबसे आसान था. तभी इसका नतीजा ऐसा रहा. 76 प्रतिशत लोगों, जिनमें तक़रीबन सभी तबके यानी शहर-गांव, शिक्षित-अशिक्षित, अमीर-ग़रीब शामिल थे, का मानना था कि नीतीश कुमार को जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाना ही नहीं चाहिए था. जिन 11 प्रतिशत लोगों ने नहीं में जवाब दिया, उनका मानना था कि भले ही मांझी सरकार का प्रदर्शन बेहतर नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उन्हें हटा दिया गया, उससे मतदाताओं के एक खास वर्ग के बीच ग़लत संदेश गया और राजनीतिक रूप से यह नीतीश कुमार के लिए शायद नुक़सानदायक साबित हो. ■

मांझी सरकार का कार्यकाल कैसा रहा?

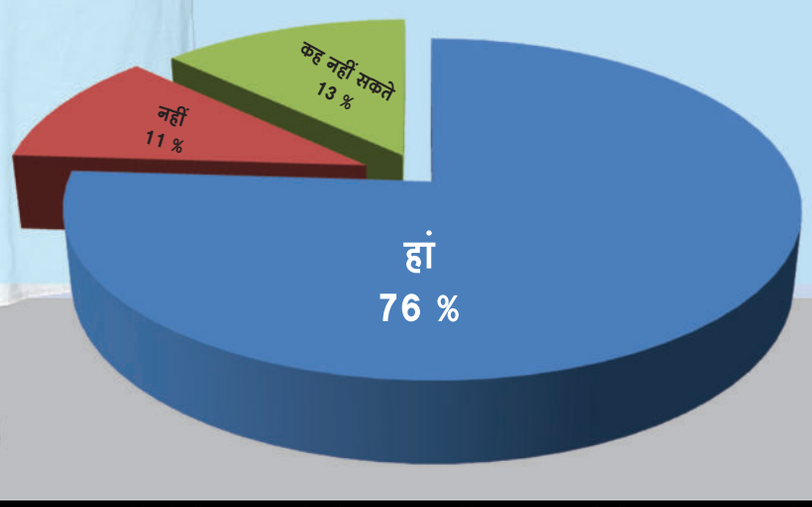

बिहार में आठ सालों तक लगातार राज करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले लोकसभा चुनाव के बाद अपनी कुर्सी जीतन राम मांझी को सौंप दी थी. बीते फरवरी माह में नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए. जीतन राम मांझी ने अपने आठ महीने के कार्यकाल के दौरान कैसा काम किया, यह सवाल हमारे जेहन में था. जब इसे लेकर हमने जनता से सवाल किया, तो 58 प्रतिशत लोगों का मानना था कि जीतन राम मांझी का कार्यकाल बुरा था. 24 प्रतिशत लोगों का मानना था कि उनका शासनकाल औसत था, 06 प्रतिशत लोगों ने उसे अच्छा बताया और 12 प्रतिशत लोग कुछ कह सकने की स्थिति में नहीं थे. ज़्यादातर लोगों का मानना था कि जीतन राम मांझी शासन को उस तरीके से नहीं चला सके, जैसे नीतीश कुमार चला रहे थे और जदयू का सुशासन का नारा मांझी सरकार के दौरान कमजोर हुआ. ■

क्या इस चुनाव में मांझी सरकार के क्रियाकलापों का असर नीतीश कुमार पर पड़ेगा?

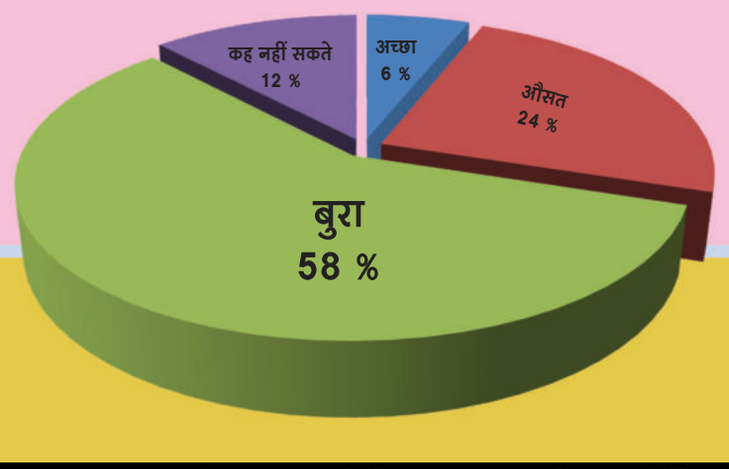

पिछले सवाल से हमारे दिमाग में एक और सवाल उपजा कि अगर आधी से ज़्यादा जनता की राय में मांझी सरकार का कार्यकाल ठीक नहीं था, तो क्या इसका असर आगामी विधासभा चुनाव में महा-गठबंधन या नीतीश कुमार पर पड़ सकता है? इस सवाल के जवाब में 40 प्रतिशत लोगों ने नीतीश कुमार में अपना विश्वास जताते हुए कहा कि मांझी के कार्यकाल का कोई भी असर आगामी विधानसभा चुनाव में नहीं पड़ेगा. 34 प्रतिशत लोगों ने कहा कि असर स्पष्ट रूप से पड़ेगा, वहीं 26 प्रतिशत लोग अनिर्णय की स्थिति में दिखे. दरअसल, जनता में इस सवाल को लेकर स्पष्टता नहीं दिखाई दी, बावजूद इसके ज़्यादातर लोगों की नज़र में नीतीश कुमार भरोसेमंद पाए गए. ■

क्या भाजपा नीतीश कुमार से बेहतर सरकार दे सकती है?

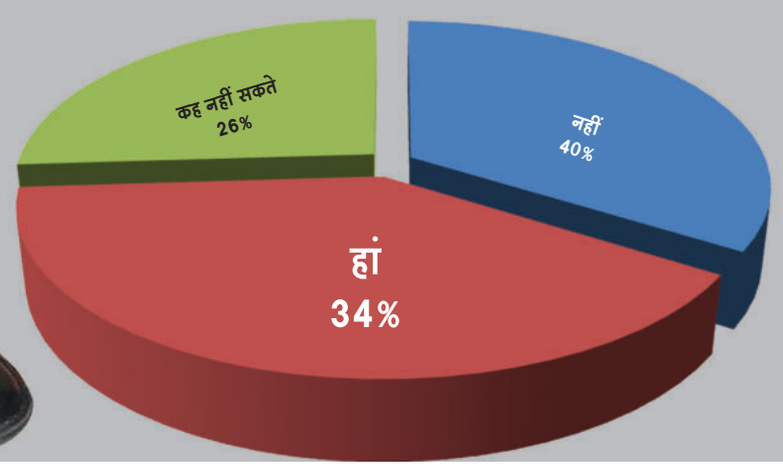

जब हमने इस बारे में मतदाताओं की राय जाननी चाही, तो 29 प्रतिशत लोगों का कहना था कि नहीं. वे कहते हैं कि नीतीश राज्य में भाजपा के साथ अपना 17 साल पुराना गठबंधन टूटने और मोदी लहर से इतने डरे हुए हैं कि वह कभी मांझी जैसे अपरिपक्व नेता को बिहार का मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो कभी लालू के साथ गठबंधन करके बिहार को फिर से जंगलराज की तरफ़ धकेलने की कोशिश करते हैं. यही कारण है कि उन पर अब विश्वास नहीं रहा और लोग भाजपा को नीतीश से अच्छा मानने लगे हैं. 49 प्रतिशत लोगों का कहना है कि केंद्र में मोदी सरकार तो ठीक है, लेकिन राज्य में भाजपा के बीच जबरदस्त कलह देखने को मिलेगी, जो बिहार के विकास में बाधक है. जबकि जनता ने नीतीश के कार्यकाल में विकास का स्वाद चखा है. लोगों का मानना है कि राजद से गठबंधन के बावजूद नीतीश बिहार के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे, जैसे कि उन्होंने मांझी को हटाकर साबित कर दिया. 22 प्रतिशत लोग इस सवाल पर कुछ न कह पाने की स्थिति में रहे. ■

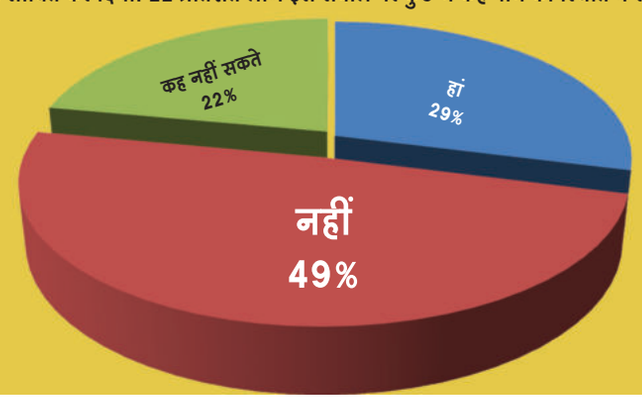

निशाने पर देसी गायें

चमड़ा-गोमांस के धंधेबाजों से जुड़ी हैं नामचीन हस्तियां

धर्मेंद्र सिंह सिसौदिया

महाराष्ट्र और हरियाणा में गोमांस के धंधे पर रोक लगाने को मानवाधिकार हनन का मुद्दा बनाया जा रहा है. इसमें बॉलीवुड से लेकर दुनिया की कई नामचीन हस्तियां शामिल हैं और उन्हें ताकत दे रहा है देश में संगठित रूप से काम करने वाला चमड़ा सिंडिकेट. महाराष्ट्र में गोमांस पर पूर्ण प्रतिबंध लगते ही मुंबई के ताकतवर चमड़ा सिंडिकेट में हाहाकार मच गया है. इस सिंडिकेट को केवल पैसे की चिंता है, देश के पशुधन और पर्यावरण से उसे क्या लेना-देना! प्रतिबंध लगते ही सिंडिकेट ने फिल्मी हस्तियों और अन्य प्रभावशाली लोगों को सामने लाकर गोमांस पर प्रतिबंध का विरोध शुरू करा दिया, जबकि उसका मुख्य लक्ष्य इस बहाने चमड़े के धंधे को निर्बाध गति से चलाते रहना है. महाराष्ट्र में गोमांस पर पाबंदी लगने के बाद यहां चमड़े के दाम बढ़ गए हैं. गोमांस डीलर्स एसोसिएशन के मुखिया मोहम्मद अली कुरैशी का बयान है कि कोलकाता और चेन्नई की चमड़ा फैक्ट्रियों में जानवरों की खाल आपूर्ति करने में महाराष्ट्र सबसे आगे रहा है, लेकिन पाबंदी लगने के बाद देवनार स्थित बूचड़खाना मुंबई में रोज़ाना सिर्फ़ 450 जानवरों की खालें ही आपूर्ति कर पा रहा है, इनमें से भी ज़्यादातर भैंस की खालें होती हैं. इसके पहले खाल 1,500 रुपये प्रति पीस की दर से खरीदी जाती थी, लेकिन पाबंदी के बाद कम से कम दो हज़ार रुपये प्रति पीस की दर से खाल खरीदनी पड़ रही है. 2012 में चमड़ा 45 रुपये प्रति फुट की दर पर खरीदा जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इसकी क़ीमत 100 रुपये प्रति फुट तक पहुंच चुकी है.

गोमांस का व्यापार तो दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर है चमड़े का धंधा, जिसका अंधाधुंध निर्यात विदेशों में हो रहा है और उससे अकूत कमाई की जा रही है. चमड़ा सिंडिकेट भारत और बांग्लादेश में संगठित रूप से काम कर रहा है और मांस की कमाई चमड़ा सिंडिकेट से जुड़े लोग खा रहे हैं. गोमांस की कमाई खाने वालों में मुसलमान, हिंदू एवं ईसाई यानी सब शामिल हैं, साथ ही कई नामचीन हस्तियां भी. चमड़ा सिंडिकेट से मिलीभगत करके यही लोग गायों की बेतहाशा तस्करी करा रहे हैं.

बांग्लादेश सीमा पर गो तस्करी रोकने के लिए होने वाली मुठभेड़ों पर भी मानवाधिकार संगठन बीएसएफ पर सवाल उठाते रहते हैं. इन सवालों से अब आम नागरिकों में भी यह मत बन रहा है कि मानवाधिकार संगठन अपराधियों, माफियाओं, तस्करों एवं राष्ट्रद्रोहियों के प्रवक्ता बनकर रह गए हैं. गायों को बर्बर तरीके से ट्रकों में ठूंसकर ले जाने के आम दृश्यों पर ये मानवाधिकारवादी कभी विरोध दर्ज नहीं कराते. पशुप्रेमी भी इस मसले पर आपराधिक चुप्पी साधे रहते हैं.

उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडीशा एवं पश्चिम बंगाल गायों की तस्करी का कॉरीडोर बन चुका है और बांग्लादेश इसका हब है. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह बीएसएफ से बार-बार कह रहे हैं कि गायों की तस्करी रोकने के लिए बांग्लादेश सीमा पर पुख्ता इंतजाम किए जाएं, लेकिन चमड़ा सिंडिकेट की सामर्थ्य के आगे केंद्रीय गृहमंत्री का आदेश बेमानी साबित हो रहा है. सिंडिकेट की कमाई का जूठन सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और स्थानीय पुलिस के पास बाकायदा पहुंच रहा है, इसलिए गायों की तस्करी रोकने के सारे फॉर्मूले नाकाम साबित हो रहे हैं. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि गोहत्या पर रोक के बावजूद बीफ की रोज़ाना खपत 61 लाख किलो है. मध्य प्रदेश, जो गायों की तस्करी के मुख्य नक्शे में नहीं है, वहां कुछ अर्से में ही सवा लाख से अधिक गायें पशु तस्करों के चंगुल से छुड़ाई गईं. यह ख़बर बताती है कि देश का पशुधन किस तरह के पैशाचिक संकट से गुज़र रहा है.

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अकेले झारखंड में हज़ारों गायें रोज़ाना कटती हैं. महाराष्ट्र और हरियाणा में लगे प्रतिबंध को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है. यह मुद्दा नहीं, बल्कि एक साजिश है. 20 साल की लंबी लड़ाई के बाद महाराष्ट्र सरकार गो-हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने में कामयाब हुई. वैसे तो महाराष्ट्र में गो-हत्या 1976 से ही प्रतिबंधित है. अब बैल-बछड़े की हत्या भी इस दायरे में आ गई है. देश के 24 राज्यों में गो-हत्या पर प्रतिबंध है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है. झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में प्रतिबंध के बावजूद गायों की अंधाधुंध हत्या हो रही है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात एवं राजस्थान में गायों की हत्या के मामले उतने नहीं सुनने को मिलते, लेकिन इन राज्यों से गो-तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है. बिहार में गायें बेतहाशा काटी जा रही हैं और गो-मांस का धंधा वीभत्स तरीके से फल-फूल रहा है. गायों की तस्करी का भी बिहार देश का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है. बिहार के ग़ैर-लाइसेंसी बूचड़खानों में बड़ी तादाद में गायें कट रही हैं. सरकार को सब कुछ पता है, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं होती. हालत यह है कि भारत में बीफ की खपत में क़रीब 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. 2011 में बीफ की खपत 20.4 लाख टन थी, जो 2014 में बढ़कर 22.5 लाख टन हो गई. पशुगणना के अनुसार, देश में गोवंश की संख्या में 2007 के मुकाबले 2012 में 4.1 प्रतिशत की कमी आई. इसमें भी देसी गो-वंश की संख्या में क़रीब नौ प्रतिशत की कमी आई है. इस दौरान नर भैंसों की संख्या में 18 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. भारत ने पिछले वर्ष 19.5 लाख टन बीफ का निर्यात किया. भारत बीफ निर्यात में विश्व में दूसरे स्थान पर है. पिछले छह महीनों में ही बीफ निर्यात में 15.58 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. विडंबना तो यह है कि बीफ निर्यातकों को सरकार की तरफ़ से 13 तरह की सब्सिडी भी मिलती है.

तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में भी गो-हत्या प्रतिबंधित है. तेलंगाना के मेडक के अल्लाना में हर साल दो लाख से ज़्यादा पशु काटे जाते हैं. वहीं मांस निर्यातक अल-कबीर में एक लाख से ज़्यादा पशुओं की हत्या की जाती है. कर्नाटक में 3,100 अवैध स्लॉटर हाउस हैं. एक स्लॉटर हाउस से रोज़ाना 7 से 8.25 टन कचरा (वेस्ट) निकलता है. केरल में गो-हत्या पर कोई क़ानूनी प्रतिबंध नहीं है. यह भारतवर्ष के क़ानून का मखौल ही है कि महाराष्ट्र में गोमांस पर प्रतिबंध के ख़िलाफ़ केरल में बीफ फेस्टिवल मनाया जाता है और इसे पूरे देश में ले जाने की तैयारी की जाती है. हरियाणा के मेवात और दिल्ली के जाफराबाद एवं मुस्तफाबाद गो-हत्या के लिए कुख्यात हैं. यहां के श्री व्हीलर गैंग गायों की हत्या करके रात में ही होटलों तक गोमांस पहुंचा देते हैं. यहां इसका कोड वर्ड सफेदा है. पांच सितारा होटलों में बीफ टेंडरलायन, फिलेट मिगनॉन वगैरह नामों से परोसा जाता है. देश में सरकारी लाइसेंस वाले 62 स्लॉटर हाउस हैं. इनमें से सबसे ज़्यादा 38 बूचड़खाने उत्तर प्रदेश में हैं. इसके अलावा अनगिनत अवैध बूचड़खाने हैं, जिनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं अन्य राज्यों से रोज़ाना पांच सौ से हज़ार गायें काटने के लिए लाई जाती हैं. मध्य प्रदेश जैसे राज्य में कुछ अर्से में 1.20 लाख गायें तस्करों के चंगुल से छुड़ाई गईं. राजस्थान में अलवर से सर्वाधिक गो-तस्करी की ख़बरें आती हैं. छत्तीसगढ़ में पिछले एक-दो साल के भीतर 5,508 गायों और 8,689 बैलों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया. गुजरात में भी गायों की तस्करी के 10 मामले दर्ज हुए. पंजाब में एक साल में गोहत्या-तस्करी के 312 मामले दर्ज हुए और पांच हज़ार गायें छुड़ाई गईं. बिहार-झारखंड, बिहार-नेपाल और बिहार-बंगाल की सीमा पर हर साल 10 हज़ार से अधिक गोवंशीय पशु पकड़े जाते हैं. बांग्लादेश सीमा पर हर वर्ष कम से कम 50 हज़ार गोवंशीय पशुओं की तस्करी होती है.

बांग्लादेश सीमा पर गो तस्करी रोकने के लिए होने वाली मुठभेड़ों पर भी मानवाधिकार संगठन बीएसएफ पर सवाल उठाते रहते हैं. इन सवालों से अब आम नागरिकों में भी यह मत बन रहा है कि मानवाधिकार संगठन अपराधियों, माफियाओं, तस्करों एवं राष्ट्रद्रोहियों के प्रवक्ता बनकर रह गए हैं. गायों को बर्बर तरीके से ट्रकों में ठूंसकर ले जाने के आम दृश्यों पर ये मानवाधिकारवादी कभी विरोध दर्ज नहीं कराते. पशुप्रेमी भी इस मसले पर आपराधिक चुप्पी साधे रहते हैं. पिछले कुछ वर्षों में बीएसएफ ने 261 बांग्लादेशी तस्करों को मार गिराया, लेकिन इसके लिए बीएसएफ की काफी आलोचना की गई. बांग्लादेश की एक करोड़ साठ लाख आबादी के 90 प्रतिशत से ज़्यादा लोग मांस खाते हैं और यह आधिकारिक सूचना है कि अधिकतर गायें भारत से ही आती हैं. भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले इस अवैध व्यापार की कमाई अरबों में है. राजस्थान, हरियाणा एवं पंजाब से गायें पश्चिम बंगाल के पशु बाज़ारों में लाई जाती हैं और ये सारे बाज़ार बांग्लादेशी सीमा पर स्थित हैं. संगठित गैंग इन गायों को बाज़ारों से खरीदते हैं और 2,400 किलोमीटर की सीमा पर अलग-अलग जगहों से उनकी तस्करी करते हैं. गायों की तस्करी करने वाले गिरोह भारतीय पुलिस, बीएसएफ और कस्टम अधिकारियों को अपने काम के लिए रिश्वत देते हैं. गायों की तस्करी के धंधे से जुड़े लोगों का कहना है कि बीएसएफ के जवानों के साथ मुठभेड़ तस्करी रोकने के सवाल पर नहीं, बल्कि रिश्वत के बंटवारे के मामले में होती है. तस्करी के लिए कुछ नेताओं को भी उनका हिस्सा मिलता है.

गायों की तस्करी रोकने के लिए कई नियोजित नौटंकियां भी हुईं. मसलन, गायों के लिए पहचान-पत्र जारी करने तक के चुटकुलेबाज तरीके ढूंढे गए. बांग्लादेश की सीमा से सटे पश्चिम बंगाल में बीएसएफ के जवान गायों की फोटो खींचते हुए भी देखे गए, ताकि उनके पहचान-पत्र बन सकें. बीएसएफ ने आधिकारिक तौर पर भी कहा कि गायों की तस्करी रोकने के लिए उनका पहचान-पत्र जारी करने का अभियान चलाया जा रहा है. सीमावर्ती मुर्शिदाबाद ज़िले में गांव वालों को अपने पशुओं के पहचान-पत्र बनवाने के लिए फोटो स्टूडियो के बाहर कतारों में लगे देखा गया. भारत और बांग्लादेश के बीच 4,096 किलोमीटर की विस्तृत सीमा है. सीमा के एक हिस्से पर तारबंदी की गई है, लेकिन उसका अधिकांश हिस्सा टूटा-फूटा है. पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच 2,000 किलोमीटर से ज़्यादा की सीमा में क़रीब 500 किलोमीटर क्षेत्र को नदियों ने आड़ा-तिरछा कर रखा है. तस्कर अपने काम के लिए नदियों का भी इस्तेमाल करते हैं. संगठित तस्कर गिरोह सीमा पर लगे तार काट डालते हैं और अच्छा-खासा गैप बनाकर उसमें से गायें ले जाते हैं. बीएसएफ का एक बड़ा काम तो अब यह भी हो गया है कि वह तार काटने वाले स्थान चिन्हित करे और वहां दोबारा तारबंदी की जाए. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2011 में 279, 2012 में 561, 2013 में 412 और 2014 में 510 स्थानों पर तार काटे गए. इस वर्ष जनवरी तक कुल 25 स्थानों पर तार काटे गए. वर्ष 2014 में गो-तस्करों से मुठभेड़ में बीएसएफ के 99 जवान घायल हुए थे. इस वर्ष अब तक बीएसएफ के 20 जवान घायल हो चुके हैं और एक जवान शहीद हुआ. वहीं तीन बांग्लादेशी तस्कर मार गिराए गए. ■

मुगल शासकों ने लगाया था गो-हत्या पर प्रतिबंध

बाबर ने अपनी वसीयत तूजुक-ए-बाबरी में अपने बेटे हुमायूं से कहा था कि मुगल साम्राज्य में न गायों की बलि हो और न गायों को मारा जाए. अकबर, जहांगीर एवं अहमद शाह जैसे मुगल शासकों ने गो-हत्या पर प्रतिबंध लगा रखा था. मैसूर रियासत के हैदर अली और टीपू सुल्तान ने भी गो-हत्या एवं गो-मांस भक्षण को संज्ञेय अपराध करार दिया था. हुक्म था कि यदि कोई गो-हत्या में लिप्त पाया गया या गोमांस बेचता या खाता हुआ पाया गया, तो उसे सख्त सजा मिलेगी और उसके दोनों हाथ काट लिए जाएंगे.

गोमांस उत्पादन

2013-14	कुल उत्पादन 20 करोड़ टन
2021-22	तक का लक्ष्य 13.75 करोड़ टन

feedback@chauthiduniya.com

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू-अरबी-फारसी विश्वविद्यालय

अराजकता और अनियमितता का अड्डा

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार पर मुस्लिम तुष्टिकरण के चाहे जितने आरोप लगें, लेकिन असलियत यह है कि अखिलेश सरकार उर्दू, अरबी एवं फारसी भाषाओं की जड़ें मजबूत नहीं होने दे रही है. वह पूर्ववर्ती मुलायम सिंह सरकार की जड़ें काट रही है. उर्दू को रोज़गारपरक और मुख्य धारा की भाषा बनाने की घोषणाएं तो खूब की जाती रही हैं, वोट भी बटोरे जाते रहे हैं, लेकिन हक़ीक़त में उक्त सारे फ़ैसले निहायत खोखले साबित हुए हैं. अल्पसंख्यक विभाग की इस्लामिक शोध से जुड़ी संस्था की ज़मीन और इमारत आजम खान की निजी संस्था को कौड़ियों के मोल लीज पर दिए जाने की ख़बरें हाल ही सुर्खियों में रही हैं. यह विवाद अभी चल ही रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार के उर्दू विरोधी रवैये का आधिकारिक खुलासा हुआ. अखिलेश सरकार के उर्दू के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैये का शिकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू-अरबी-फारसी विश्वविद्यालय हो रहा है. राज्य में दूसरी राजभाषा के रूप में स्थापित उर्दू को अधिक से अधिक विकसित करने के उद्देश्य से लखनऊ में उर्दू-अरबी-फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, लेकिन यहां उन्हीं भाषाओं की प्राथमिकता समाप्त कर दी गई है. यह विश्वविद्यालय आज अराजकता और विरोधाभास का अड्डा बन गया है. इसका अब उर्दू, अरबी एवं फारसी भाषाओं के विकास से कोई लेना-देना नहीं रहा, इसका अस्तित्व गड्ड-मड्ड कर दिया गया है.

उर्दू, अरबी एवं फारसी के विकास और अकादमिक शोध के लिए जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, उसका दिलचस्प पहलू यह है कि विश्वविद्यालय के सारे शीर्ष पदों पर विराजमान हस्तियां उर्दू, अरबी या फारसी भाषा की शैक्षिक योग्यता नहीं रखतीं. विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर खान मसूद अहमद जामिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं. रजिस्ट्रार नाजिम हुसैन अल जाफरी के क्या कहने! उर्दू तो छोड़िए, इनका अकादमिक करियर से ही कोई लेना-देना नहीं रहा. यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बाबू (लिपिक) थे और प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव एवं मौजूदा मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी की एएमयू में पदस्थापित रहीं बहन के मातहत काम कर चुके हैं. जानकार बताते हैं कि उसी के पुरस्कार स्वरूप एएमयू के इस बाबू को यहां रजिस्ट्रार का पद दे दिया गया. सरकार ने इस नियुक्ति में वह नियम खुद ताख पर रख दिया, जिसमें रजिस्ट्रार को कम से कम पीसीएस संवर्ग का अधिकारी होना अनिवार्य बताया गया है. मजे की बात यह कि नाजिम हुसैन अल जाफरी ही विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक (एक्जामिनेशन कंट्रोलर) भी हैं. इसी तरह प्रॉक्टर डॉ. नीरज कुमार शुक्ला का उर्दू भाषा से कोई लेना-देना नहीं. यह लखनऊ के एक कॉलेज में कॉमर्स के अस्थायी लेक्चरर थे. लाइब्रेरियन दुआ नकवी की लाइब्रेरी साइंस में पढ़ाई-लिखाई नहीं हुई है, जबकि इस पद के लिए लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होती है. डिप्टी प्रॉक्टर डॉ. सबीना बानो भी उर्दू या अरबी-फारसी भाषा से जुड़ी शैक्षणिक योग्यता नहीं रखतीं. यह भूगोल विषय से जुड़ी हैं. विश्वविद्यालय के ओएसडी डॉ. जीआर यादव कॉमर्स फैकल्टी के हैं और इस्टेट अफसर प्रोफेसर माहरुख मिर्जा भी कॉमर्स फैकल्टी से जुड़े रहे हैं.

यानी जिस विश्वविद्यालय की स्थापना उर्दू, अरबी एवं फारसी भाषा के विकास के लिए हुई, वहीं इन भाषाओं के विद्वानों और जानकारों को किसी भी शीर्ष पद पर नियुक्त नहीं किया गया. शीर्ष अधिकारियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछे जाने पर विश्वविद्यालय प्रशासन कहता है कि मांगी गई सूचना व्यक्तिगत है. उल्लेखनीय है कि 21 सितंबर, 2012 को विश्वविद्यालय की एक्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में उर्दू के साथ अरबी एवं फारसी की शिक्षा, शोध और रोज़गारपरक विकास के विभिन्न मुद्दे तय किए गए थे. बैठक में यह तय हुआ था कि विश्वविद्यालय में होने वाली नियुक्तियों में उर्दू, अरबी एवं फारसी के जानकारों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन नतीजा सबके सामने है. विश्वविद्यालय का नाम पहले उत्तर प्रदेश उर्दू-अरबी-फारसी विश्वविद्यालय रखा गया था, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने इसका नाम बदल कर मान्यवर कांशीराम उर्दू-अरबी-फारसी विश्वविद्यालय कर दिया. जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तो इसका नाम बदल कर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू-अरबी-फारसी विश्वविद्यालय कर दिया गया. हालांकि, अजमेर शरीफ दरगाह के सज्जादनशीन सैयद जैनुल आबेदीन अली खान ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी. उनका कहना था कि महान सूफी संतों को सियासत से दूर रखा जाना चाहिए. अगर सरकार को ख्वाजा साहब में गहरी आस्था है, तो वह ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती के नाम पर किसी नए संस्थान की बुनियाद डाले, लेकिन किसी संस्थान का नाम बदल कर राजनीतिक विवाद में संत का नाम घसीटने की कोशिश से परहेज किया जाना चाहिए. मायावती ने भी नाम-बदल पर तीखी प्रतिक्रिया जताई थी.

उत्तर प्रदेश उर्दू-अरबी-फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद प्रदेश के वरिष्ठ नौकरशाह रहे और उर्दू साहित्य के विद्वान डॉ. अनीस अंसारी को कुलपति नियुक्त किया गया था. डॉ. अंसारी के कार्यकाल में विश्वविद्यालय उर्दू भाषा के विकास की दिशा में आगे बढ़ता रहा, लेकिन अखिलेश सरकार ने उन्हें हटाकर जामिया मिलिया के प्रोफेसर खान मसूद अहमद को जून 2014 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू-अरबी-फारसी विश्वविद्यालय का वीसी बना दिया. प्रोफेसर अहमद ने 10 जुलाई, 2014 को यह घोषणा कर दी कि विश्वविद्यालय में उर्दू अनिवार्य भाषा नहीं रही. वीसी और रजिस्ट्रार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिये घोषणा की कि उर्दू, अरबी या फारसी भाषा वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी और उनके अंक रिजल्ट के पूर्णांक (एग्रीगेट) में नहीं जोड़े जाएंगे. इस तरह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू-अरबी-फारसी विश्वविद्यालय का औचित्य नष्ट कर इसके मूल अस्तित्व को नकार दिया गया. स्वाभाविक है कि ऐसा राज्य सरकार की सहमति या इशारे के बगैर नहीं हुआ होगा. आरटीआई एक्टिविस्ट सलीम बेग ने राज्यपाल को पत्र लिखकर इन करतूतों का विरोध किया और उर्दू के विकास के लिए पूर्व के निर्णय बहाल कराने की मांग की. राज्यपाल ही प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, लेकिन उनकी तरफ़ से भी कोई जवाब नहीं आया. उर्दू के साथ हो रहे खिलवाड़ और विश्वविद्यालय द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं के मसले में राज्य सरकार और विश्वविद्यालय ने घालमेल का जो खेल रचा, वह सुनियोजित धोखाधड़ी का नायाब नमूना है. सूचना के अधिकार के तहत सलीम बेग ने इस बारे में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव-उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय के कुलपति से औपचारिक सूचना मांगी. बेग ने उर्दू, अरबी एवं फारसी भाषा के शैक्षणिक विकास की गति के ख़िलाफ़ काम करने वाले और अनियमितताओं में लिप्त अधिकारियों-कर्मचारियों के ख़िलाफ़ जांच कर कार्रवाई की मांग उठाई थी, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया. केवल मुख्य सचिव के यहां से बताया गया कि उनका पत्र उच्च शिक्षा विभाग को अग्रसारित कर दिया गया है. मुख्य सचिव का पत्र संलग्न करते हुए सलीम बेग ने फिर उच्च शिक्षा विभाग से इसका जवाब मांगा, तो कहा गया कि उनका पत्र आवश्यक कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालय के कुलसचिव (रजिस्ट्रार) को भेज दिया गया है. उच्च शिक्षा विभाग ने एक तरफ़ लिखा कि कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालय को पत्र भेज दिया गया है और दूसरी तरफ़ यह भी लिख दिया कि इस मामले में कोई दोषी नहीं है. बेग का पत्र जब विश्वविद्यालय प्रशासन को भेजना था, तो बिना किसी जांच के उच्च शिक्षा विभाग ने यह कैसे तय कर लिया कि कोई दोषी नहीं है?

राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव तक ने विश्श्वविद्यालय प्रशासन को मामले की जांच तथा आवश्यक कार्रवाई का आदेश जारी करने का साझा प्रहसन खेला. जब जांच व कार्रवाई के बारे में विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछा गया तो, जवाब मिला कि इस मामले में न कोई जांच कमेटी गठित हुई और न कोई जांच कराई गई. विश्वविद्यालय प्रशासन ने मांगी गई अन्य सूचनाओं का जवाब भी गड्ड-मड्ड कर दिया. राज्यपाल सचिवालय की अनु सचिव मधुबाला सहगल ने विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश भेजा था कि राज्यपाल ने मामले की जांच एवं आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है. प्रदेश सरकार ने भी अनु सचिव वीरेंद्र नाथ के ज़रिये विश्वविद्यालय प्रशासन को मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा, जांच नहीं कराई. ऐसा जवाब देते हुए उसे शर्म नहीं आई. सलीम बेग ने विश्वविद्यालय से कुलपति, रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर एवं अन्य शीर्ष अधिकारियों के उर्दू-अरबी ज्ञान के बारे में पूछा, तो आधिकारिक जवाब मिला कि पूछी गई सूचना व्यक्तिगत है. उर्दू के विकास के बारे में एक्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में लिए गए फ़ैसलों की जानकारी चाही गई, तो कहा गया कि दफ्तर आकर संबंधित पत्रावली देख लें. ताकि, आरटीआई कार्यकर्ता की पहचान हो जाए और उसका जीवन मुश्किलों से भर जाए. ऐसे जवाब देकर विश्वविद्यालय ने आरटीआई एक्ट के प्रावधानों की धज्जियां उड़ा दीं. जबकि क़ानून आरटीआई एक्टिविस्ट की हिफाजत के लिए उसकी पहचान गोपनीय रखने की हिदायत देता है.

उर्दू, अरबी एवं फारसी की प्राथमिकता समाप्त करने और इनमें प्राप्त अंक परीक्षाफल में न जोड़ने के अहमकी फ़ैसले के बारे में जानकारी मांगने पर विश्वविद्यालय ने कहा कि यह फ़ैसला प्रोफेसरों की एक कमेटी ने किया है, फिर कहा कि कमेटी के पास यह मसला विचाराधीन है. जबकि उसके पहले वीसी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा कर दी थी. सवाल यह है कि सरकार के नीतिगत फ़ैसले को प्रोफेसरों की कमेटी ताख पर कैसे रख सकती है? विश्वविद्यालय प्रशासन के जवाब काफी विरोधाभासी हैं. एक तरफ़ वह कहता है कि छात्रों के लिए उर्दू, अरबी या फारसी पढ़ना अनिवार्य है, दूसरी तरफ़ कहता है कि इन विषयों के अंक परीक्षाफल में जोड़े नहीं जाएंगे. जब अंक जोड़े नहीं जाएंगे, तो छात्र पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय क्यों आएंगे? विश्वविद्यालय प्रशासन ने उर्दू की अनिवार्यता के बारे में जारी अधिसूचना से वह हिस्सा ही हटा दिया है. विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप है कि वह ज़मीनों पर कब्जा कर रहा है. अपने लिखित जवाब में विश्वविद्यालय कहता है कि उसके पास 28 एकड़ ज़मीन है, इसके अलावा कोई भूमि नहीं है, जबकि उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा है कि सरकार की तरफ़ से उसे 30 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराई जा चुकी है. इसके अलावा बाईपास के नज़दीक 32 एकड़ और दूसरी तरफ़ 150 एकड़ ज़मीन हासिल करने की अलग से कार्रवाई की जा रही है. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उल्लिखित इन तथ्यों का विवरण मांगा गया, तो जवाब देने के बजाय वेबसाइट से वह पेज ही गायब कर दिया गया. वेबसाइट का वह हिस्सा चौथी दुनिया के पास सुरक्षित है. वेबसाइट से हिंदी वाला पूरा हिस्सा गायब है. अराजकता का आलम यह है कि यहां के कर्मचारी (स्टाफ) दूसरे विश्वविद्यालय में रेगुलर कोर्स करते हैं और विश्वविद्यालय से गायब रहते हैं. पकड़े जाने पर कई कर्मचारियों को पूर्व वीसी डॉ. अनीस अंसारी ने नौकरी से निकाल दिया था, लेकिन नए वीसी ने आते ही उन सबको बहाल कर दिया. इसी तरह अवकाश अवधि के अनाप-शनाप भुगतान और अन्य किस्म की वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं, जिन्हें देखने और अंकुश लगाने का कोई इंतजाम नहीं है. ■

feedback@chauthiduniya.com

यह शोध पत्र मुख्यमंत्री तक पहुंचा दें...

उर्दू की शेरो-शायरी पढ़ना और ग़ज़लें गुनगुनाना न केवल मन को सुकून देता है, बल्कि दिमाग की नसों का बेहतर इलाज भी करता है. लखनऊ स्थित सेंटर फॉर बायो-मेडिकल रिसर्च (सीबीएमआर) के न्यूरो-इमेर्जिंग विभाग के वैज्ञानिक उत्तम कुमार ने एक शोध के ज़रिये यह निष्कर्ष निकाला है. उनका शोध अंतरराष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका न्यूरो साइंस लेटर्स में प्रकाशित हुआ है. लखनऊ के एक बुद्धिजीवी ने कहा कि विज्ञान पत्रिका में छपे इस शोध की एक प्रति मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक पहुंचा देनी चाहिए, ताकि वह उसे पढ़ लें. सीबीएमआर का यह शोध बताता है कि उर्दू पढ़ने से दिमाग का वह अहम हिस्सा प्रभावित होता है, जहां से कोई भी व्यक्ति अच्छे और बुरे का फ़र्क़ कर उचित फ़ैसले लेता है, जहां से भावनाएं नियंत्रित होती हैं, जहां से तनाव नियंत्रित होता है और जहां से सूचनाएं हासिल कर उनकी समीक्षा करने की शक्ति मिलती है. उर्दू पढ़ने से भूलने की प्रवृत्ति भी कम होती है. मुख्यमंत्री को शोध पत्र पढ़ने की सलाह देने वाले सज्जन ने यह भी कहा कि उर्दू किसी शख्स के दिमाग को सकारात्मक बनाने में इतनी ही प्रभावकारी है, तो आतंकी और देश विरोधी गतिविधियों में लगे लोगों को क्यों नहीं सुधार पाती?

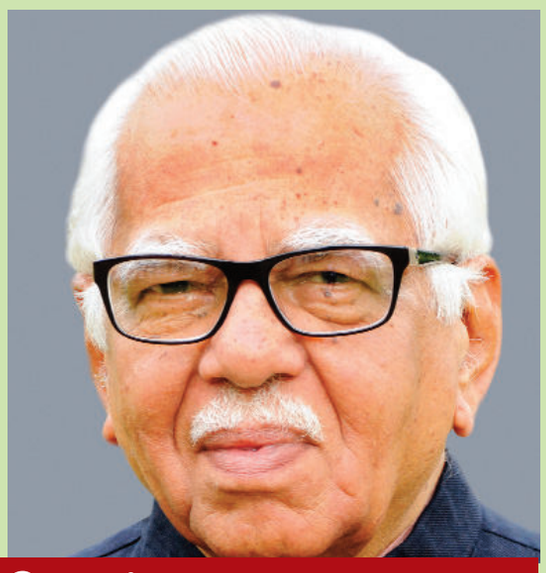

नेता बहाते हैं घड़ियाली आंसू

हिंदी हो या उर्दू, दोनों भाषाओं के लिए नेता सिर्फ़ घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उनके विकास के लिए कुछ नहीं करते. इन दोनों भाषाओं को लेकर राजनीति खूब होती है, लेकिन बढ़ावा अंग्रेजी को दिया जाता है. जहां तक उर्दू का मसला है, छह अक्टूबर, 1989 को एक अधिसूचना जारी कर इसे द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था और सात अक्टूबर, 1989 को उर्दू के सरकारी कामकाज में इस्तेमाल के विभिन्न बिंदु तय किए गए थे. उस समय मुलायम सिंह पर अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के आरोप लगे थे, लेकिन अदालत ने भी उनके फ़ैसले को सही करार दिया था. अफ़सोस! मुलायम सिंह की सारी कवायद बेमानी साबित हुई. वर्ष 2005 में सरकार ने चिंता जाहिर की थी कि दूसरी राजभाषा के रूप में उर्दू का प्रयोग और विकास संतोषप्रद नहीं है. वर्ष 2009 में प्रदेश में उर्दू-अरबी-फारसी विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया था. इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन किया गया. पांच मार्च, 2010 को बाकायदा गजट प्रकाशित हुआ. शासन ने बताया कि उर्दू, अरबी एवं फारसी में शिक्षा, अनुसंधान और उर्दू के विकास के लिए लखनऊ में उत्तर प्रदेश उर्दू-अरबी-फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है. लेकिन, राजनीति ने इसे तहस-नहस करके रख दिया. प्रदेश में हज़ारों मदरसे हैं, जहां लाखों छात्र उर्दू में तालीम हासिल करते हैं, लेकिन मदरसों की शिक्षा मुख्य धारा में शामिल नहीं है और रोज़गारपरक भी नहीं है. विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे उन तमाम छात्रों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने और प्रोफेशनल बनाने का भी इरादा था, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर स्थापना के उद्देश्य के तहत लिखा है कि उसकी स्थापना उर्दू, अरबी, फारसी भाषा एवं संस्कृति के अध्ययन और विकास के लिए की गई है, लेकिन ज़मीनी असलियत इसके ठीक विपरीत है.

हिंदू छात्र मदरसे और मुस्लिम छात्र संघ के स्कूल में!

हाल में ख़बर आई कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में हिंदू छात्रों ने मदरसे में और मुस्लिम छात्रों ने आरएसएस के स्कूल में दाखिला लेकर सांप्रदायिक कट्टरता की सियासत को करारा तमाचा लगाया. यह खास तौर पर उल्लेखनीय और उदाहरण योग्य इसलिए भी है, क्योंकि उसी रामपुर के निवासी आजम खान अपनी सांप्रदायिक कट्टरता के कारण देश भर में जाने जाते हैं. ख़बर के मुताबिक, रामपुर के 11 हिंदू छात्रों ने मदरसे और 140 मुस्लिम छात्रों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्कूल में अपना नाम लिखवाया है. इन बच्चों ने अपनी मर्जी से अपनी-अपनी पसंद के स्कूल और मदरसे में दाखिला लिया. मदरसे के प्रिंसिपल जमीतुल अंसार ने बताया कि इन छात्रों के अभिभावकों को उर्दू भाषा के प्रति लगाव है, जिसके चलते उन्होंने उक्त दाखिले कराए. अंसार ने कहा कि हिंदू छात्र एवं उनके अभिभावक उर्दू को मिर्जा गालिब और राहत इंदौरी जैसे बड़े शायरों की वजह से पसंद करते हैं. ऐसे में वे मदरसे में पढ़कर उर्दू ज़ुबान के और ज़्यादा क़रीब होना चाहते हैं. दूसरी तरफ़ 140 मुस्लिम बच्चों ने भी आरएसएस के स्कूल में दाखिला लेकर एक मिसाल कायम की.

छत्तीसगढ़

10 लाख करोड़ का चावल घोटाला !

रुपेश कुमार

कुछ दिन पहले रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरटीआई एक्टिविस्ट गौरीशंकर जैन और छत्तीसगढ़ वित्त निगम के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र पांडेय ने 10 लाख करोड़ रुपये के चावल खरीद में घाटे की बात कहकर हड़कंम मचा दिया था. इन दोनों एक्टिविस्टों ने आरोप लगाया कि कस्टम मिलिंग व्यवस्था में पिछले बीस सालों में सरकार को 10 लाख करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है. एक्टिविस्ट जैन ने इसकी शिकायत कैग से की है. उनका कहना है कि आयकर और सीबीआई को भी संज्ञान दिया गया है.

दरअसल, सरकार किसानों से धान लेकर उसे कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिल को देती है. राइस मिलर्स धान से चावल निकालते हैं. सरकार एक क्विंटल धान के बदले 67 किलो चावल राइस मिलर्स से लेती है, लेकिन बाकी बचे टूटे चावल, कुंडा और भूसी का हिसाब नहीं होता. इसे ही एक्टिविस्ट असली घाटा बता रहे हैं, क्योंकि सरकार धान से चावल निकालने के बदले 30 रुपये का भुगतान अलग से करती है. बाकी बचा हुआ टूटा चावल यानी ब्रोकेन राइस, कुंडा यानी राइस ब्रान और भूसी यानी हस्क राइस राइस मिलर्स, जो मिलर्स के पास रह जाता है, उससे मिलर्स करीब 190 से 250 रुपये का भारी मुनाफा कमाते हैं.

दोनों के आरोप इस लिहाज़ से संगीन हैं कि साल भर अपने खून-पसीने से सींचकर फसल उगाने वाले किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता. 50 से सौ रुपये समर्थन मूल्य बढ़वाने के लिए उन्हें न जाने कितनी बार आंदोलन करना पड़ता है. लाठियां खानी पड़ती हैं, लेकिन चंद घंटों में धान से चावल निकालने वाले उद्योगपति पूरी मलाई खा रहे हैं. करोड़ों का वारा-न्यारा कर रहे हैं.

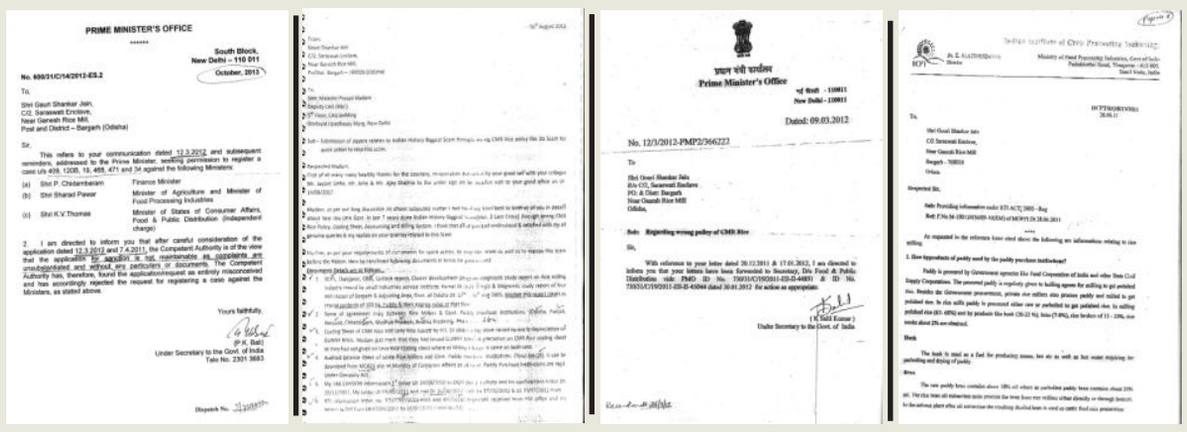

आरटीआई एक्टिविस्ट गौरीशंकर जैन की जानकारी के मुताबिक एक क्विंटल धान में 2 किलो टूटा धान 7 किलो कुंडा और 23 भूसी निकलती है. कनकी बाजार में सोलह से बीस रुपये प्रति किलो बिकती है, जबकि कुंडा 13 से चौदह रुपये किलो बिकता है. इसी तरह भूसी 2.3 रुपये किलो बिकती है. इस तरह एक राइस मिल वाला प्रति क्विंटल 190 रुपये से 250 रुपये प्रति किलो बाइ प्रोडक्ट के रूप में मिलता है. इसके बाद सरकार उन्हें 30.40 रुपये प्रति क्विंटल देती है. छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में राज्य सरकारें अलग से 10 रुपये का इनसेंटिव देती हैं. इस तरह प्रति क्विंटल के पीछे 220 से 270 रुपये राइस मिलर्स को मिलता है, जबकि किसान निजी तौर पर राइस मिलर्स सिर्फ भूसी के बदले अपने धान से चावल निकलवा लेता है. रायपुर के किसान रूपम चंद्राकर और द्वारिका साहू ने बताया कि गांव वाले जब राइस मिल जाते हैं, तो किसान अगर राइस मिलर्स को भूसी दे दे, तो उसकी मिलिंग मुफ्त में हो जाती है. अगर किसान भूसी न देना चाहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्रति क्विंटल करीब 70 रुपये देने पड़ते हैं. यानी सरकार करीब दो सौ रुपये अधिक दे रही है. जैन और पांडेय का कहना है कि धान खरीदी की कस्टम मीलिंग व्यवस्था अपनाने के बाद पूरा हिसाब लगाया जाए कि कितना अतरिक्त भुगतान सरकार ने किया है, तो ये रकम करीब 10 लाख करोड़ रुपये की बैठती है.

आरटीआई एक्टिविस्टों के मुताबिक, ये सिर्फ सरकारी घाटे की कहानी नहीं है, बल्कि राइस मिलर्स का घोटाला भी इसमें शामिल है. कनकी, कुंडा और भूसी से लाखों करोड़ों बनाने वाले राइस मिलर्स इसका हिसाब आयकर विभाग या सेलटैक्स विभाग को नहीं देते, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगता है. आरोप है कि मिलर्स अपनी बैलेंस सीट में इसकी मात्रा और कीमतों को लेकर घोटाला करते हैं. आरटीआई एक्टिविस्टों की मांग है कि जब सरकार धान को लेकर समर्थन मूल्य घोषित करती है, तो बाइ प्रोडक्ट्स का क्यों नहीं. आरटीआई एक्टिविस्ट वीरेंद्र पांडेय ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों सरकारों का बड़ा घोटाला है. उन्होंने कहा कि बरदाने की खरीद-बिक्री में भी बड़ा झोलमाल है. बरदाना बाज़ार से महंगे दामों पर ख़रीद कर मिलर्स को वो करीब मुफ्त में दे दिया जाता है. अनुमान है कि इसे मिलाकर सरकार को पिछले दस साल में 10 लाख करोड़ का चूना लग चुका है. इस मामले में आरटीआई एक्टिविस्टों ने आयकर विभाग, सीबीआई और कैग से लेकर पीएमओ तक चिट्ठी लिखी है और कई एजेंसियों ने जांच का आश्वासन दिया है. आरटीआई एक्टिविस्टों का कहना है कि इस मामले में पंजाब सरकार ने मिलरों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है कि उन्होंने बाई प्रोडक्ट को लेकर हिसाब-किताब में कितनी गड़बड़ी की है. आरटीआई एक्टिविस्टों ने नीति बनाने की प्रक्रिया को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है. आखिर साल भर की मेहनत के बाद फसल उगाने वाले किसान की मेहनत की कमाई की मलाई उनके धान से चावल निकालने वाले राइस मिलर्स खा रहे हैं.

इस मामले को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट गौरीशंकर अग्रवाल ने 2010 से शिकायत करना शुरू किया. उन्होंने कैग, इन्कम टैक्स, सीबीआई, खाद्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय से लेकर पीएमओ और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर इस प्रक्रियागत खामी की तरफ ध्यान दिलाया. उन्होंने करीब पांच साल तक लगातार सैकड़ों चिट्ठियां लिखकर इस तरफ ध्यान दिलाया, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी. एक विभाग दूसरे विभाग पर डालता रहा. बकौल जैन इस बारे में फरवरी 2015 में प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से सकारात्मक जवाब आया है. जैन का कहना है कि उन्होंने इस मामले को तब पकड़ा, जब उनके इलाके के सैकड़ों राइस मिलर्स को उन्होंने करोड़ों की दौलत का अकूत मालिक बनते देखा. जैन का कहना है कि वे इसके बाद इसकी पड़ताल में जुट गए. उनका कहना है कि वे इस मामले को लेकर तब तक लड़ेंगे, जब तक किसानों को उनका न्याय नहीं मिल जाता. वीरेंद्र पांडेय का कहना है कि अगर सही ढंग से इसकी जांच हो तो ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है. एक तरफ ये शर्मनाक बात है कि सरकार किसानों को उनका वाजिब हक नहीं दे पाती, जिसके चलते किसान गरीब से गरीब होता जा रहा है, खेती-किसानी छोड़ रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ राइस मिलिंग करने वाले पूंजीपति दिन-ब-दिन मालामाल हो रहे हैं. ये राइस मिलर्स किसानों की खून-पसीने की कमाई खा रहे हैं. अगर सरकार इस व्यवस्था को सुधारती है तो वो किसानों को अतरिक्त पैसा दे सकती है. गौरतलब है कि मोदी सरकार ने राज्यों को दिये जाने वाले बोनस पर रोक लगा दी है.

छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में ये राज्य सरकारों के खिलाफ असंतोष का बड़ा मुद्दा बन चुका है. वीरेंद्र पांडेय का कहना है कि सरकार अगर पैसे बचाए, तो इसी से वो किसानों के बोनस का भुगतान कर सकती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

किसान महापंचायत

ज़मीन बचाने की जंग जारी है

चौथी दुनिया ब्यूरो

भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली के जंतर मंतर ने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत किसान महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें देश भर से आये किसानों ने एक सुर में सरकार से भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को वापस लेने की मांग की. महापंचायत को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि यदि केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को वापस नहीं लेती, तो सरकार के खिलाफ आन्दोलन को और तेज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ-साथ संसद में होने वाली बहस में उन दलों पर भी नजर रखे हुए हैं, जो निजी स्वार्थों के कारण किसान हितों की अनदेखी कर उद्योगपतियों को समर्थन कर रहे हैं. हम उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं कि उन्हें जनता के विरोध का सामना करना पड़ेगा.

किसानों को भूमि अधिग्रहण बिल 2013 में बदलाव मंजूर नहीं है. अध्यादेश के द्वारा किसान समर्थित कई प्रावधानों को हटा दिया गया है. इन बदलावों के बाद भूमि अधिग्रहण कानून 1894 के कानून से भी बदतर हो जाएगा. किसानों के काफी संघर्ष के बाद भूमि

अधिग्रहण बिल 1894 में बदलाव किया गया था. यदि यह अध्यादेश कानून का रूप लेता है, तो यह उद्योग समर्थक और किसान विरोधी होगा. देश के किसान इस बिल का पुरजोर विरोध कर रहे हैं. राजग सरकार बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण को तैयार है, जिसका प्रभाव किसानों की आजीविका पर पड़ेगा. पहले ही लाखों हेक्टेयर जमीन औद्योगिक गलियारे, लैंड बैंक, विशेष आर्थिक जोन, राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम पर अधिग्रहीत की जा चुकी है. विशेष आर्थिक जोन पर कैग की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि जिस जमीन का विशेष आर्थिक जोन के नाम पर अधिग्रहण किया गया, उसका उपयोग नहीं हुआ है. कैग की रिपोर्ट के अनुसार, 45635.63 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण 2006 से 2012 तक किया गया. अधिग्रहीत भूमि 31886.27 हेक्टेयर का उपयोग नहीं हुआ, जबकि 5402.22 हेक्टेयर को दूसरे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए परिवर्तित कर दिया गया. हमारी मांग है कि इस अध्यादेश को अविलम्ब वापस लेते हुए भूमि अधिग्रहण पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे. देश में अधिकतर किसान एक हेक्टेयर से कम जमीन वाले हैं. इसका मतलब यह कि देश के लाखों किसान उनकी आजीविका से निर्वासित कर दिये गए. सरकार के इस तरह के कदम पूरी तरह अस्वीकार्य हैं.

महापंचायत में खेती किसानी मुद्दों के ज्वलन्त मुद्दों के साथ-साथ किसानों की जीविका से संबंधित मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा गया. किसान पंचायत के एजेंडे में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश, शांताकुमार उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिश भारत सरकार द्वारा जीएम फसलों को बढ़ावा देने एवं किसानों के उत्पाद का सही मूल्य न मिलना और किसान आयोग बनाने जैसी मांगें प्रमुख रही. किसान नेताओं ने किसानों की आत्महत्या एवं खेती के संकट पर मोदी सरकार के मूकदर्शक होने का आरोप लगाते हुए कहा कि कृषि का बजट घटकर पिछले पांच साल के सबसे निचले स्तर पर चला गया है.

भाकियू पंजाब के अध्यक्ष अजमेर सिंह लाखोवाल ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किसानों की फसलों का लागत में 50 प्रतिशत जोड़ कर मूल्य देने एवं किसान की आय में वृद्धि की बात कही थी, लेकिन अब वह अपने वादे से मुकरती दिख रही है. अभी जिस तरह से फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा की गयी है, उससे आभास होता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने वायदे को पूरा करना चाहती है. ऐसे में उससे भूमि अधिग्रहण के मसले पर किसानों के हित की कैसे अपेक्षा की जाए. किसानों के लिए अच्छे दिन व उनकी आमदनी में वृद्धि किए जाने के का नारा देकर सत्ता में आई सरकार आज किसानों की समस्याओं पर मूकदर्शक बनी हुई है और किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है. इस देश का दुर्भाग्य है कि किसानों के दम पर सत्ता में आने वाली सरकारें अंततः किसानों को ही भूल जाती हैं. चुनाव से पहले सभी पार्टियां किसान-किसान चिल्लाती हैं, लेकिन सत्ता में आते ही किसान उनके एजेंडे से बाहर हो जाते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

सरकार अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त होने की लाख कोशिश करे, विकास दर में गिरावट के कारण सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में बिखरे पड़े हैं. नीतीश सरकार ने राज्य को दूसरी हरित क्रांति का केंद्र बनाने का दावा पूरे ताम–झाम के साथ किया था. इसके लिए सारी व्यवस्थाएं की गईं. कृषि विकास के लिए दस वर्षीय कृषि रोडमैप तैयार किया गया, जिसे पांच–पांच साल के दो चरणों में पूरा होना था. इसके लिए कुछ विशेषज्ञों की तैनाती भी हुई और कृषि कैबिनेट का गठन किया गया. लेकिन हुआ क्या? राज्य के ताज़ा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, यहां कृषि का विकास नकारात्मक रहा है. राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसका योगदान घट गया है.

बिहार सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण

कहीं ख़ुशी कहीं ग़म

आर्थिक गतिविधियों के इन प्राइमरी-सेकेंडरी सेक्टरों के बाद तीसरी श्रेणी सेवा क्षेत्र की है, जो राज्य में खूब फल-फूल रहा है. होटल-रेस्तरां, मोबाइल, सूचना तकनीक और वाहनों का व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है. पिछले आठ-नौ वर्षों से राज्य के जीडीपी में इस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान रहा है. 2013-14 में भी यही हुआ. आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि राज्य में बिजली की उपलब्धता बढ़ रही है. अब मांग और उपलब्धता के बीच अंतर बहुत बड़ा नहीं रहा, लेकिन यह खुशी उधार की है.

सुकांत

यह कहना तो सही नहीं है कि बिहार में विकास की गाड़ी बेपटरी हो गई है, पर उसकी गति ज़रूर धीमी हो गई है. राज्य में पिछले सवा नौ वर्षों से उनका (नीतीश) राज–पाट है. अपने शासनकाल में उन्होंने राज्य से जुड़े कुछ राजनीतिक मिथ तोड़े, जिनमें पिछड़ापन भी एक रहा. बीते कुछ दशकों की आर्थिक जड़ता के कारण यह मान लिया गया था कि इस पिछड़े राज्य में विकास की गाड़ी नहीं चलाई जा सकती. निराशा की अंधेरी सुरंग में फंसे इस राज्य के हालात उन्होंने सुधारे, क़ानून का राज कायम किया और यहां आम तौर पर सत्ता के इकबाल का एहसास हुआ. लोगों में जान–माल सुरक्षित होने की उम्मीद जगी और उन्हें सुशासन बाबू कहा जाने लगा. इसके साथ ही विकास के मोर्चे पर फीलगुड का माहौल बना, विकास की गाड़ी पटरी पर आई और राज्य में पूंजी निवेश के नए–नए प्रस्ताव आने लगे. बिहारी समाज में आर्थिक समृद्धि के मोर्चे पर नए क्षितिज छूने की उम्मीद जगी. इस नई उम्मीद ने नीतीश कुमार को विकास पुरुष का खिताब दिया. अब दसवें वर्ष में यह खिताब ख़तरे में फंसा दिखता है. हालांकि, जद (यू) के नीतीश भक्त राजनेता और नौकरशाह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं.

आर्थिक सर्वेक्षण के मुख्य बिन्दु

- कृषि का विकास नकारात्मक रहा है.
- राज्य के जीडीपी में इसका योगदान घटा
- कृषि का योगदान 27 से घट कर 22 प्रतिशत हुआ.
- कृषि उत्पादन में 12 प्रतिशत की गिरावट
- पशुपालन एवं मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में भी गिरावट
- जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बढ़ा है
- 1,891 स्वीकृत निवेश प्रस्तावों में से केवल 272 ज़मीन पर हैं.
- 2013-14 में बिहार में प्रति व्यक्ति औसत सालाना आय 15,650 रुपये
- पटना में प्रति व्यक्ति औसत सालाना आय 63,063 रुपये
- शिवहर में यह मात्र 7,092 रुपये रही.

नीतीश सरकार ने अपने नौवें आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट बीते दिनों विधान मंडल के दोनों सदनों में पेश की. वित्तीय वर्ष 2014–15 की इस रिपोर्ट में मूलत: वित्तीय वर्ष 2013–14 का ब्यौरा ही पेश किया गया. इस रिपोर्ट में नीतीश राज से जुड़े अनेक मिथ तार–तार हुए हैं. यह रिपोर्ट न सिर्फ़ बहुत सारी बातें साफ़ करती है, बल्कि स्पष्ट संकेत देती है कि विकास के मोर्चे पर राज्य सरकार अब पिछड़ने लगी है. राज्य की विकास दर तो नीचे चली ही गई, कृषि जैसी आर्थिक गतिविधि के मोर्चे पर भी स्थिति नकारात्मक रही. नीतीश कुमार ने सत्ता संभालते ही विकास दर को नई ऊंचाई दी और उनके कार्यकाल में सदैव यह दहाई में रही. वित्तीय वर्ष 2006–07 में विकास दर 16.18 प्रतिशत तक पहुंच गई थी. इन नौ वर्षों में एक ऐसा भी दौर रहा, जब बिहार की विकास दर अनेक उन्नत राज्यों से बहुत अधिक रही और यह पिछड़ा राज्य सबसे उन्नतशील माना गया. किसी उल्लेखनीय पूंजी निवेश के बगैर केवल कठोर राजनीतिक इच्छाशक्ति की बदौलत विकास की नई ऊंचाइयां छूने के मोर्चे पर बिहार देश में उदाहरण माना जाने लगा, लेकिन यह तमगा ठिकाऊ नहीं रहा. राज्य की विकास दर अस्थिर बनी रही और इसमें घट–बढ़ होती रही. बावजूद इसके किसी भी साल यह दहाई से नीचे नहीं आई. वित्तीय वर्ष 2011–12 में विकास दर 10.24 प्रतिशत पर आ गई. सबसे ताज़ा आंकड़ा 2013–14 का है, जिसमें राज्य की विकास दर दहाई से नीचे यानी 9.92 प्रतिशत रह गई है. राज्य सरकार विकास दर में इस गिरावट के लिए सूखा और बाढ़ को ज़िम्मेदार बता रही है. हालांकि, पिछले कई वर्षों से राज्य में प्रकृति–चक्र ऐसा नहीं रहा कि विकास दर नीचे लुढ़का दे. लेकिन, राज्य सरकार प्रकृति के सिर ठीकरा फोड़कर अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त होना चाहती है.

सरकार अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त होने की लाख कोशिश करे, विकास दर में गिरावट के कारण सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में बिखरे पड़े हैं. नीतीश सरकार ने राज्य को दूसरी हरित क्रांति का केंद्र बनाने का दावा पूरे ताम–झाम के साथ किया था. इसके लिए सारी व्यवस्थाएं की गईं. कृषि विकास के लिए दस वर्षीय कृषि रोडमैप तैयार किया गया, जिसे पांच–पांच साल के दो चरणों में पूरा होना था. इसके लिए कुछ विशेषज्ञों की तैनाती भी हुई और कृषि कैबिनेट का गठन किया गया. लेकिन हुआ क्या? राज्य के ताज़ा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, यहां कृषि का विकास नकारात्मक रहा है. राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसका योगदान घट गया है. पहले जीडीपी में कृषि का योगदान 27 प्रतिशत था, जो अब 22 प्रतिशत रह गया है. कृषि के उत्पादन में भी लगभग 12 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि वित्तीय वर्ष 2012–13 में 9.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई थी. पशुपालन एवं मत्स्य पालन जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में भी गिरावट रही. हालांकि, राज्य के जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बढ़ा है, नाममात्र का ही सही. जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 18.1 प्रतिशत से बढ़कर 18.4 प्रतिशत हो गया है. राज्य सरकार इसे लेकर अपनी पीठ खुद थपथपा सकती है, लेकिन आर्थिक विकास में रुचि रखने वाले और इसकी प्रकृति के जानकार औद्योगिक क्षेत्र की इस गति से संतुष्ट तो कतई नहीं हो सकते. राज्य में स्वीकृत औद्योगिक इकाइयों के प्रस्तावों के ज़मीन पर उतरने की गति कोई उम्मीद नहीं जगाती.

सर्वेक्षण के अनुसार, 1,891 स्वीकृत निवेश प्रस्तावों में से केवल 272 ज़मीन पर हैं. इनमें भी अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण कार्य से जुड़े हैं और लघु एवं घरेलू उद्योग के दायरे में आते हैं. रिपोर्ट से यह भी साफ़ होता है कि राज्य के विकास में विनिर्माण क्षेत्र की भूमिका कतई महत्वपूर्ण नहीं रही और यह कल्पनाशील प्रोत्साहन एवं तैयारी की अपेक्षा रखता है. यह जानना कम महत्वपूर्ण नहीं है कि राज्य सरकार ने ढाई लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव अव्यवहारिक मानकर निरस्त कर दिए हैं. यह एवं ऐसे अन्य कार्य राज्य के औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया और गति को स्पष्ट करते हैं. बिहार में पर्यटन को उद्योग का दर्जा हासिल है, पर पर्यटन के नाम पर केवल यात्रियों के बिहार आने तक के आंकड़ों पर ही सरकार ज़्यादा भरोसा करती है. बिहार आने वाले लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है. लेकिन वे कौन लोग हैं? वस्तुत: बिहार आने वाले अधिकांश पर्यटक बौद्ध और जैन तीर्थयात्री होते हैं, क्योंकि उनके बड़े तीर्थस्थल इस राज्य में है. वनों एवं वन्यजीवों से जुड़े पर्यटन को विकसित करने की किसी कोशिश की जानकारी यह सर्वेक्षण रिपोर्ट नहीं देती है. पर्यटकों को आवास एवं परिवहन आदि सुविधाएं देने के लिए क्या किया गया है अथवा किया जा रहा है, यह इस सर्वेक्षण से पता नहीं चलता.

आर्थिक गतिविधियों के इन प्राइमरी–सेकेंडरी सेक्टरों के बाद तीसरी श्रेणी सेवा क्षेत्र की है, जो राज्य में खूब फल–फूल रहा है. होटल–रेस्तरां, मोबाइल, सूचना तकनीक और वाहनों का व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है. पिछले आठ–नौ वर्षों से राज्य के जीडीपी में इस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान रहा है. 2013–14 में भी यही हुआ. आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि राज्य में बिजली की उपलब्धता बढ़ रही है. अब मांग और उपलब्धता के बीच अंतर बहुत बड़ा नहीं रहा, लेकिन यह खुशी उधार की है. बिहार का अपना उत्पादन अब भी उल्लेख के लायक नहीं है और लगभग पूरी बिजली केंद्र से मिल रही है. राज्य में बिजली का औसत उत्पादन 68 मेगावाट प्रतिदिन है, जबकि बाहर से रोजाना 2,761 मेगावाट बिजली खरीदी जाती है. इस बात के लिए खुश हुआ जा सकता है कि बिहार में बैंकों का साख–जमा अनुपात (क्रेडिट–डिपॉजिट रेशियो) बढ़कर 46 प्रतिशत तक चला गया है, लेकिन अभी भी बिहार में ऋण बहुत कम जारी हो रहे हैं, क्योंकि यहां औद्योगिक गतिविधियां वैसी हैं नहीं. बिहार के लोग इस बात से भी खुश हो सकते हैं कि सरकार सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में खर्च को निरंतर बढ़ावा दे रही है और मानव विकास सूचकांक ऊपर चढ़ रहा है. वित्तीय वर्ष 2013–14 में सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय 2,423 रुपये हो गया. शिक्षा एवं स्वास्थ्य के साथ–साथ सड़क, पेयजल आदि बुनियादी सुविधाओं के विकास पर बिहार में खासा खर्च हो रहा है.

इन सारी उपलब्धियों के बावजूद एक दुर्भाग्य बिहार का पीछा नहीं छोड़ रहा है, वह यह कि राज्य में विकास के द्वीप बनते जा रहे हैं. यदि बिहार का सच्चे अर्थों में विकास करना है, तो इसके अंधेरे इलाकों में भी विकास की रोशनी पहुंचानी होगी. शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, बांका, मधुबनी, अरवल, नवादा, शेखपुरा एवं किशनगंज आदि ज़िलों की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है. पटना, मुंगेर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर आदि बिहार के विकसित ज़िले हैं, पहले भी थे. पिछले कई वर्षों से (जबसे आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जा रहा है) शिवहर बिहार का सबसे ग़रीब ज़िला रहा है. वित्तीय वर्ष 2013–14 में बिहार में प्रति व्यक्ति औसत सालाना आय 15,650 रुपये रही. पटना में प्रति व्यक्ति औसत सालाना आय 63,063 रुपये रही, लेकिन वहीं शिवहर में यह मात्र 7,092 रुपये रही. पटना बिहार में एकमात्र आलोकित द्वीप की तरह है. राज्य के दस ज़िलों की हालत शिवहर जैसी है, तो कुछ की कुछ अंकों से सुधरी हुई मान ली गई है. इन ज़िलों की प्रति व्यक्ति औसत सालाना आय पांच अंकों तक अभी नहीं पहुंची है, जबकि पटना छठवां अंक छूने को बेताब है. राज्य के आधा दर्जन ज़िले भी ऐसे नहीं हैं, जहां प्रति व्यक्ति औसत सालाना आय पटना के एक तिहाई भी हो. यह विषमता आने वाले वर्षों में बिहार के आर्थिक–राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं मानी जानी चाहिए. बिहार की नब्बे प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है और अंधेरे इलाके वे ही हैं, जहां बाढ़ एवं सूखे की मार बहुत तीखी पड़ती रही है. ऐसे अंधेरे इलाकों में सत्ता के इकबाल को चुनौती देने या विकास की गाड़ी पटरी से उतारने के नित नए रास्ते की तलाश की जाती रही है, लेकिन सत्ता–राजनीति तो सदैव एक आभा मंडल तैयार कर अपनी उसी दुनिया में संतुष्ट रहती है. और, यह आभा मंडल निश्चित रूप से पटना जैसे नगर (या ज़िले) में ही तो तैयार होते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

मोदी सरकार की मुश्किलें

नौकरशाहों के लिए यह एक पुरानी कहावत है, वे चार और अधिकारी पैदा करेंगे, जो चार और डेस्क बनाएंगे. यही कार्य संस्कृति है और इसे बदलने के लिए प्रशासनिक सुधार की ज़रूरत है. बजट पेश होने के क़रीब एक महीने के बाद मैं देख रहा हूं कि बजट के बाद का वातावरण सामान्य है. वैसा नहीं है, जैसा प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी भाषणों में बनाने की बात कही थी. दिल्ली में एक जोक चल रहा है कि भाजपा अभी भी चुनाव वाली मानसिकता में है. हर कोई ऐसे बात कर रहा है, जैसे वह चुनाव लड़ रहा हो. उन्हें महसूस नहीं हो रहा है कि अब वे सत्ता में हैं और अपने चुनावी वादे पूरे करने हैं. और, इससे भी बड़ा जोक है कि कांग्रेस यह महसूस नहीं कर पा रही है कि वह विपक्ष में है.

इस देश का इतिहास हज़ारों सालों का है. भाजपा पांच साल के लिए चुनी गई है. पांच साल बाद फिर चुनाव होंगे यानी आज से ठीक चार साल बाद. इसके बाद भी कई सरकारें आएंगी और जाएंगी. नरेंद्र मोदी और भाजपा को इसलिए याद किया जाएगा कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने क्या किया? ऐसे में, नरेंद्र मोदी को सफल प्रधानमंत्री बनाने या उनके प्रयासों को पूरा करने के बजाय ये लोग सारे किए-धरे पर पानी फेरने वाले काम कर रहे हैं. इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा. कुछ चर्च जलाकर, किसी की हत्या करके वे हिंदुत्व का लक्ष्य पा लेंगे, उनकी यह सोच ग़लत है, बल्कि ऐसा करके वे सिर्फ़ असुरक्षा की भावना और भय पैदा कर रहे हैं. असली हिंदुत्व की भावना पाने की बात भूल जानी चाहिए.

नरेंद्र मोदी को अपने साथियों समेत सरकार बनाए हुए और प्रधानमंत्री बने हुए अब 10 महीने बीत चुके हैं. कुल मिलाकर तस्वीर यह बन रही है कि सरकार हमेशा की तरह एक सरकार के रूप में काम कर रही है. इस देश में ज़्यादातर काम सामान्य रूप से चलते रहे हैं. भाजपा द्वारा कुछ बड़े परिवर्तनों की उम्मीदें जगाई गई थीं. यहां तक कि उस समय भी राजनीतिक प्रेक्षकों ने माना था कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, चाहे किसी की इच्छा कुछ भी क्यों न हो. ऐसा केवल अधिनायकवादी शासन में हो सकता है. किसी लोकतंत्र में ऐसा नहीं हो सकता. लोकतंत्र में सभी हितधारकों को किसी मुद्दे पर एक साथ लाकर ही कुछ किया जा सकता है. इसलिए सरकार अभी तक विभिन्न बाधाओं के बीच संतोषजनक रूप से काम करती आ रही है.

नरेंद्र मोदी विकास की बात करते हैं. वह कहते हैं सबका साथ, सबका विकास. उनका मुख्य उद्देश्य भी विकास ही है और वह यह मानते भी हैं कि इसके बिना देश का भविष्य बहुत अच्छा नहीं हो सकता. यह अच्छी बात है. समस्या वाली बात और है. संघ परिवार से जुड़े कई संगठन, चाहे वह विश्व हिंदू परिषद हो या कोई अन्य, वे ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है. दरअसल, वे सब नरेंद्र मोदी के प्रयासों को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं. पुणे में दाभोलकर की हत्या, साध्वी द्वारा हिंदुओं को चार बच्चे पैदा करने की सलाह, चर्चों पर हमले इसका प्रमाण हैं. इन सबका कोई मतलब नहीं है. हमारे जैसे धर्मनिरपेक्ष लोग या कांग्रेस इस बात को लेकर चाहे जितने गुस्से में हों, वह अलग बात है, लेकिन इस सबमें नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ही सबसे बड़ी लूजर (हारने वाला) है.

इस देश का इतिहास हज़ारों सालों का है. भाजपा पांच साल के लिए चुनी गई है. पांच साल बाद फिर चुनाव होंगे यानी आज से ठीक चार साल बाद. इसके बाद भी कई सरकारें आएंगी और जाएंगी. नरेंद्र मोदी और भाजपा को इसलिए याद किया जाएगा कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने क्या किया? ऐसे में, नरेंद्र मोदी को सफल प्रधानमंत्री बनाने या उनके प्रयासों को पूरा करने के बजाय ये लोग सारे किए-धरे पर पानी फेरने वाले काम कर रहे हैं. इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा. कुछ चर्च जलाकर, किसी की हत्या करके वे हिंदुत्व का लक्ष्य पा लेंगे, उनकी यह सोच ग़लत है, बल्कि ऐसा करके वे सिर्फ़ असुरक्षा की भावना और भय पैदा कर रहे हैं. असली हिंदुत्व की भावना पाने की बात भूल जानी चाहिए. यह लेखक एक हिंदू है, एक समर्पित हिंदू. और, मुझे लगता है कि मैं यह कहने की हिम्मत कर सकता हूं कि हिंदुत्व का प्रचार करने वालों से बेहतर हिंदू मैं हूं. इस पृथ्वी पर ऐसा किसने कहा है कि हिंदुत्व के विचार का विरोध करने वाले की हत्या से हिंदुत्व को ताकत मिल जाएगी या अयोध्या में मस्जिद तोड़कर या कुछ चर्च जलाकर राम और कृष्ण की महिमा बढ़ जाएगी? किसने और कहां ये सारी बातें कही-लिखी हैं? जाहिर है, इन लोगों ने हमारे धर्मग्रंथ नहीं पढ़े हैं.

जो मूल बात मैं कहना चाह रहा हूं, वह यह है कि नरेंद्र मोदी अब देश के प्रधानमंत्री हैं, वे सिर्फ़ भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं हैं और सिर्फ़ भाजपा के नेता नहीं हैं. उन्हें सफलता मिले, इसके लिए प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य बनता है कि वह उनकी सहायता करे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सफलता का मतलब है, देश की सफलता. यदि आप अधिक रोज़गार, अधिक उद्योग, कृषि का विकास, सभी की समृद्धि चाहते हैं, जो मोदी का उद्देश्य है, तो उनकी नीतियों का सफल होना बहुत ज़रूरी है. आरएसएस को एक चिंतन बैठक बुलाने की ज़रूरत है और उन्हें यह निर्णय लेना चाहिए कि वे क्या करना चाहते हैं? अपनी अदूरदर्शिता के तहत अपना एजेंडा आगे करने के लिए सरकार के इस्तेमाल से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा. ऐसा करके वे भाजपा सरकार का संपूर्ण आधार नष्ट कर देंगे. मुख्य बात यह है कि पहले से ही बहुत अधिक शिकायतें हैं. उदाहरण के लिए, कॉरपोरेट और ट्रेड सेक्टर महसूस करते हैं कि बजट अप टू मार्क (उम्मीद के मुताबिक) नहीं रहा. आख़िर क्यों? वजह, पहले से ही अपेक्षाएं इतनी बढ़ा दी गई थीं कि वित्त मंत्री जो भी करते, वह कम ही लगता.

व्यापार एक निरंतर बात है, इसलिए यह हमारी चिंता का विषय नहीं है. यहां तक कि सख्त समाजवाद और सख्त क़ानूनों के बीच भी कारोबार समृद्ध हुआ. उन दिनों में भी बड़े व्यापारिक घराने अस्तित्व में आए, जब क़ानून कठोर थे. यह सरकार बहुत अधिक भ्रमित है. मोदी विकास चाहते हैं, वहीं संघ परिवार अपना एजेंडा आगे बढ़ाना चाहता है और नौकरशाह नहीं चाहते कि सिस्टम में कोई बदलाव हो. वे किसी भी क़ानून में परिवर्तन नहीं चाहते. सरकार कह रही है कि हम व्यापार को आसान बनाएंगे. मोदी सिंगापुर, फिलीपींस और दक्षिण पूर्व के साथ खुद की तुलना करते हुए व्यापार को आसान बनाना चाहते हैं. वह न जाने किस दुनिया में जी रहे हैं! भारत व्यापार करने के लिए सबसे मुश्किल जगहों में से एक है. यह उनके लिए आसान है, जो यहां रह चुके हैं. ऐसे लोग लाइसेंस, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार की संस्कृति से परिचित हैं और इन सबका कोई न कोई विकल्प तलाश लेते हैं. कोई विदेशी, अगर उसे कोई अन्य विकल्प मिले, तो वह भारत क्यों आएगा? नरेंद्र मोदी इस संस्कृति को बदलना चाहते हैं, लेकिन नौकरशाही उसमें बाधा उत्पन्न करती है.

माफी के साथ कहना चाहता हूं कि गुजरात मॉडल मंत्री से अधिक नौकरशाह पर निर्भर है और प्रधानमंत्री दिल्ली में यही मॉडल दोहराने की कोशिश कर रहे हैं. इससे सफलता बहुत सीमित हो जाएगी. नौकरशाही के बारे में कहा जाता है कि कोई चीज सरल बनाने के लिए आप एक कमेटी बनाते हैं. तीन महीने बाद वह कमेटी एक ऐसी रिपोर्ट लेकर आती है, जो सरलीकरण के नाम पर उस चीज को और अधिक जटिल बनाने का काम करती है. नौकरशाहों के लिए यह एक पुरानी कहावत है, वे चार और अधिकारी पैदा करेंगे, जो चार और डेस्क बनाएंगे. यही कार्य संस्कृति है और इसे बदलने के लिए प्रशासनिक सुधार की ज़रूरत है. बजट पेश होने के क़रीब एक महीने के बाद मैं देख रहा हूं कि बजट के बाद का वातावरण सामान्य है. वैसा नहीं है, जैसा प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी भाषणों में बनाने की बात कही थी. दिल्ली में एक जोक चल रहा है कि भाजपा अभी भी चुनाव वाली मानसिकता में है. हर कोई ऐसे बात कर रहा है, जैसे वह चुनाव लड़ रहा हो. उन्हें महसूस नहीं हो रहा है कि अब वे सत्ता में हैं और अपने चुनावी वादे पूरे करने हैं. और, इससे भी बड़ा जोक है कि कांग्रेस यह महसूस नहीं कर पा रही है कि वह विपक्ष में है. वह ऐसे बात कर रही है, जैसे अभी भी वह सत्ता में है. वह विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका नहीं निभा रही है.

दूसरा मुख्य मुद्दा जिससे देश परेशान है, वह है भूमि सुधार अधिनियम. कांग्रेस का अंतिम एक्ट, जिसे भाजपा ने समर्थन दिया था. ठीक है कि भाजपा आज सत्ता में है और उसे लगता है कि अब इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है. लेकिन इसके लिए उसे एक, दो, तीन, चार यानी कुछ बिंदु बनाने चाहिए और बताना चाहिए कि हम इसे बदलना चाहते हैं. फिर कांग्रेस के साथ बहस करके, उसे सहमत कराकर इसे पास कराना चाहिए. लेकिन, इसकी जगह वे एक अध्यादेश ले आए और लोकसभा से उसे पास करा दिया. अब अन्ना हजारे इस पर आंदोलन कर रहे हैं, विपक्ष आंदोलन कर रहा है और किसान नाराज हैं. मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वास्तव में इस सरकार का उद्देश्य क्या है? वे पांच साल शासन करने वाले हैं, लेकिन ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, जैसे पांच साल से पहले ही सत्ता से बाहर जाना चाहते हैं. लेकिन यह मुश्किल है. उन्हें पांच साल शासन करना है और काम भी करना है. जब वे सत्ता में आए थे, तब 15 साल, 20 साल की बात कर रहे थे. केजरीवाल के सत्ता में आने के बाद यह बात होनी बंद हो गई है, अब पांच साल की बात होती है. लेकिन, जितनी जल्दी वे ज़मीनी हक़ीक़त को समझ लें और हालात के मुताबिक काम करना शुरू कर दें, उतना ही अच्छा होगा.■

feedback@chauthiduniya.com

विक्रम मल्लाह और फूलन देवी-4

पुलिस का अत्याचार, बाबू गूजर का अंत

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

फूलन के अपहरण के दूसरे दिन जब उसकी मां थाने में रिपोर्ट लिखाने गई, तो दारोगा ने कहा, तुम भी मल्लाह, वह भी मल्लाह. ले गया, तो ले जाने दो. क्या वह उसे रखेगा, महीना-दो महीना बाद छोड़ देगा. पुलिस ने फूलन के गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखी. फूलन जबसे गई, तबसे पुलिस लगातार गुड़हा जाती है तथा उसकी मां को मारती है. सारा सामान कुर्क कर लिया गया तथा घर खोदकर देखा गया कि कहीं फूलन ने सोना न भिजवाया हो, जिसे गाड़कर रखा गया होगा. गांव वाले मुझे घेर कर बैठे थे तथा अपने शरीर के उन निशानों को दिखा रहे थे, जो पुलिस की मार के कारण पड़े थे. फूलन का गांव पुलिस के अत्याचार का स्थायी अड्डा बन गया है. गांव वालों का कहना है कि वे दोनों तरफ़ से मर रहे हैं. चूंकि यह ऑपरेशन एरिया है, इसलिए किसी भी अत्याचार की सुनवाई नहीं होती, न डाकुओं के अत्याचार की, न पुलिस के अत्याचार की.

फूलन अब बाबू गूजर के कब्जे में थी. बाबू उसके साथ एक तरह से बलात्कार ही करता था तथा फूलन भी उसी भाव से उसके साथ रही. वह फूलन को बहुत गिरी अवस्था में रखता था, जैसे धूप निकलने तक कुएं पर नंगे बैठाए रखना, दल के लोगों के सामने उसके साथ संभोग करना. इन स्थितियों में विक्रम का जातीय स्वाभिमान जाग उठा तथा उसमें आग सुलगने लगी. वह मौक़े की तलाश में रहने लगा. बाबू के तीन सहयोगी थे. एक दिन बाबू का एक विशिष्ट सहयोगी राइफल ठीक कराने चला गया तथा दो सहयोगी जमुना में नहाने चले गए. जो व्यक्ति बाबू की देखरेख के लिए था, वह रात भर की थकावट के कारण खुमारी में झूम रहा था. तभी भारत सिंह व विक्रम ने मिलकर बाबू पर गोली चला दी. बाबू अपने तीन सोते हुए साथियों सहित मारा गया. अब फूलन देवी मात्र विक्रम की होकर रह गई.

बाबू गूजर के मरने के बाद विक्रम के गिरोह की स्थिति काफी कमजोर हो गई. भारत ने साथियों के साथ गिरोह की स्थिति संभाली, पर इस गिरोह पर एक बहुत बड़ा ख़तरा मंडरा रहा था. वह ख़तरा था मलखान सिंह का. दरअसल, बाबू गूजर मलखान के गिरोह से उसकी वेंचेस्टर राइफल व घनश्याम की दुनाली बंदूक धोखे से लेकर भाग आया था, जिस पर मलखान ने उसे अपना दुश्मन करार दे दिया था. वह वेंचेस्टर राइफल व दुनाली बंदूक अब विक्रम के पास थी. उस समय मलखान-घनश्याम का गिरोह राजस्थान की तरफ़ था, किंतु वे लोग किसी भी समय आ सकते थे. दीवाली 1979 के आसपास जैसे ही घनश्याम का गिरोह नरिहान के बीहड़ों में आया, विक्रम अपने साथियों सहित तुरंत उससे मिलने आया. घनश्याम के सामने उसने वह वेंचेस्टर राइफल व

कालपी थाने से दो किलोमीटर दूर देवकली गांव में डकैती के दौरान पुलिस से मुठभेड़ हुई और घनश्याम, गब्बर व विक्रम तीन दलों में बंट गए. गब्बर की टुकड़ी एक नए गिरोह के रूप में जोरों से उभरने लगी. इसी समय गब्बर के संपर्क में माया आई और उसे गब्बर ने अपने साथ रख लिया. इसी दौरान आज का कुख्यात डाकू छोटेलाल मिश्रा भी गब्बर से आ मिला. छोटेलाल मिश्रा का अतीत अलग किस्म का है. वह एक संभ्रांत परिवार में पैदा हुआ था. गांव का प्रतिभाशाली युवक था तथा हर काम में आगे रहता था. गांव के प्रभावशाली, कूटनीतिज्ञ तथा पुलिस के दलाल समझे जाने वाले कुछ व्यक्तियों ने उसे फंसाने के लिए उससे विशेष स्नेह दिखाया.

दुनाली बंदूक समर्पित कर दी. घनश्याम ने विक्रम से कहा, मुझे इसका दु:ख नहीं है कि बाबू मारा गया, क्योंकि वह मेरा शत्रु था. पर वह साहसी आदमी था. ऐसे बहादुर आदमी को तुमने कुत्ते की मौत मार डाला. यदि तुम उसे आमने-सामने मारकर आए होते, तो मैं तुम्हें वह इनाम देता, जो दस्यु इतिहास में एक विशेष स्थान रखता. किंतु तुमने उसे धोखे से मारा. तुम घृणा के पात्र हो. तमाम मिन्नतों व सफाइयों के बावजूद घनश्याम नहीं पिघला. तब एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति पर निर्णय छोड़ दिया गया, जिसकी दस्यु दलों में एक अलग तरह की प्रतिष्ठा थी. उस व्यक्ति ने विक्रम को घनश्याम के साथ रहने की आज्ञा दे दी. अब घनश्याम के नेतृत्व में विक्रम मल्लाह और फूलन देवी डाका डालने लगे. इनके साथ हरदास उर्फ गब्बर सिंह नामक एक शातिर डकैत भी था.

कालपी थाने से दो किलोमीटर दूर देवकली गांव में डकैती के दौरान पुलिस से मुठभेड़ हुई और घनश्याम, गब्बर व विक्रम तीन दलों में बंट गए. गब्बर की टुकड़ी एक नए गिरोह के रूप में जोरों से उभरने लगी. इसी समय गब्बर के संपर्क में माया आई और उसे गब्बर ने अपने साथ रख लिया. इसी दौरान आज का कुख्यात डाकू छोटेलाल मिश्रा भी गब्बर से आ मिला. छोटेलाल मिश्रा का अतीत अलग किस्म का है. वह एक संभ्रांत परिवार में पैदा हुआ था. गांव का प्रतिभाशाली युवक था तथा हर काम में आगे रहता था. गांव के प्रभावशाली, कूटनीतिज्ञ तथा पुलिस के दलाल समझे जाने वाले कुछ व्यक्तियों ने उसे फंसाने के लिए उससे विशेष स्नेह दिखाया. इन लोगों ने अपने परिवार की कुछ लड़कियों को भी बड़ी चालाकी से उसके संपर्क में ला दिया. पर छोटेलाल किसी का पुर्जा बनने के लिए तैयार नहीं था. परिणाम स्वरूप पुलिस के माध्यम से गांव के उन्हीं लोगों ने छोटेलाल को अवैध ढंग से तंग कराना प्रारंभ कर दिया.

दूसरी तरफ़ उन्हीं लोगों ने छोटे का संपर्क गब्बर सिंह से कराकर उसे अपराधी बना दिया. इन कामों को वह खेल समझ कर करता रहा. अंततोगत्वा पैसा, विलासिता व कामुकता की ओर अग्रसर छोटेलाल गांव के उन्हीं लोगों की दासता स्वीकार करने पर विवश हो गया. अब वह अपराध करके धन एकत्र करने लगा और इन परिवारों की लड़कियों के मोहजाल में आशक्त होने की वजह से उन्हीं के पास सारा धन रखने लगा. आवश्यकता पड़ने पर छोटेलाल ने अपना धन मांगा, जो अब तक लगभग 50 हज़ार के आसपास हो गया था, पर इनकी नीयत खराब थी. इन लोगों ने पुलिस को अपने प्रभाव में लेकर छोटेलाल को पकड़ कर इतना ज़्यादा मारा कि उसके हाथ-पैर तोड़ दिए. शरीर का कोई हिस्सा नहीं बचा था, जहां छोटेलाल को चोट न लगी हो. छोटेलाल मिश्रा जिन अपराधों को अब तक खिलवाड़ समझ कर करता था, उनकी वास्तविकता का अब उसे एहसास हुआ. पर वक्त निकल चुका था संभलने का. उसे जेल भेज दिया गया. उस पर कई मुक़दमे लगवा दिए गए तथा उन व्यक्तियों द्वारा यह ध्यान रखा जाने लगा कि यह किसी तरह जेल से न निकलने पाए.■

क्रमश:

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

संपादकीय

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

समाज की यह तस्वीर बहुत डरावनी है

“जिस तेजी से समाज में धार्मिक चैनल बढ़े, उसी तेजी से समाज में अपराध का ग्राफ बढ़ा. आख़िर इन चैनलों पर आए हुए संत-महात्माओं ने किसे प्रेरित किया? साधुओं की भी जमातें हो गईं. एक बड़ा तबका राजनीतिक साधुओं के रूप में जाना जाने लगा, जिनमें कुछ कांग्रेस के हो गए और कुछ भारतीय जनता पार्टी के हो गए. भारतीय जनता पार्टी ने पिछले तीन-चार लोकसभा चुनावों में साधु-संतों को टिकट देकर लोकसभा पहुंचाया. इतना ही नहीं, उनमें से कुछ को मंत्री भी बनाया.”

जिस तरह राजनीति की दिशा बदल रही है और राजनीति का स्तर गिर रहा है, उससे कहीं ज़्यादा समाज की दिशा बदल रही है और समाज का स्तर गिर रहा है. आज से 40 साल पहले समाज और राजनीति का एक स्तर था. आज समाज और राजनीति का बिल्कुल दूसरा स्तर है. यह एक बड़ा फ़र्क़ है और बहुत डरावना है. इसका यह मतलब नहीं है कि समाज में ज़्यादातर शोहदे, लुच्चे या गुंडे हो चुके हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि समाज का वह हिस्सा, जो आवाज़ करता है, उसका एक बड़ा हिस्सा इसी प्रकार के विशेषणों के नज़दीक पहुंच गया है.

इसके उदाहरण तलाशने की ज़रूरत नहीं है. जबसे सैटेलाइट टीवी का आविर्भाव हुआ, जिसे हम 90 का दशक कह सकते हैं, अचानक धार्मिक चैनलों की बाढ़ आ गई. जितने भी बड़े-बड़े साधु, संत, महात्मा, मंडलेश्वर और कमंडलेश्वर थे, वे सब किसी न किसी चैनल पर आकर देश को प्रवचन देने लगे, लोगों को रास्ते पर चलने की अलग-अलग ढंग से प्रेरणा देने का काम करने लगे. ज़्यादातर साधुओं ने टेलीविजन पर आना अपना स्टेटस सिंबल मान लिया. जो टेलीविजन पर आता है, वह बड़ा साधु है और जो नहीं आता है, वह छोटा साधु है, ऐसी मान्यता साधु समाज में फैला दी गई. नतीजे के तौर पर छोटे-छोटे साधु भी पैसा इकट्ठा करके विभिन्न चैनलों में टाइम खरीदने लगे. और, जो साधु हमारे बीच में नहीं हैं, उनके शिष्य उन साधु महाराज के रिकॉर्ड किए हुए प्रवचन बड़े-बड़े चैनलों पर वक्त खरीद कर दिखा रहे हैं. शायद यह धर्म की मार्केटिंग का विद्रूप चेहरा है.

जिस तेजी से समाज में धार्मिक चैनल बढ़े, उसी तेजी से समाज में अपराध का ग्राफ बढ़ा. आख़िर इन चैनलों पर आए हुए संत-महात्माओं ने किसे प्रेरित किया? साधुओं की भी जमातें हो गईं. एक बड़ा तबका राजनीतिक साधुओं के रूप में जाना जाने लगा, जिनमें कुछ कांग्रेस के हो गए और कुछ भारतीय जनता पार्टी के हो गए. भारतीय जनता पार्टी ने पिछले तीन-चार लोकसभा चुनावों में साधु-संतों को टिकट देकर लोकसभा पहुंचाया. इतना ही नहीं, उनमें से कुछ को मंत्री भी बनाया. जो साधु लोकसभा में नहीं जा सके, उन्होंने अपनी अलग-अलग पीठें स्थापित कीं. शंकराचार्य भी मुखर हो गए, बड़े साधु भी मुखर हो गए और छोटे साधु भी मुखर हो गए, पर समाज के ऊपर इसका रंचमात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा. बल्कि समाज में खाई बढ़ती दिखाई दी और पराकाष्ठा तो तब हो गई, जब बहुत सारे साधु जातियों के साधु हो गए. कुछ जातियों ने अपने-अपने महात्माओं को चुन लिया. जो संन्यास लेने से पहले उस जाति समुदाय से आते थे. हालांकि, यह माना जाता है कि संन्यास लेना मृत्यु के बाद दूसरा जन्म है. पर ये तो पुनर्जन्म प्राप्त करके भी जातियों के साधु बन गए. बहुत से साधुओं ने तो राजनीति में किसे बढ़ाना है, किसे गिराना है और किसे घटाना है, इसमें भी महारथ हासिल कर ली.

अफ़सोस की बात यह है कि इतने साधु-संतों के विचार टेलीविजन द्वारा समाज में सुबह-शाम फैलाए जाने के बाद भी बलात्कार की घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी जा रही है. सख्त क़ानून ने बलात्कारियों के मन में कोई डर नहीं पैदा किया और इन साधु-संतों ने बलात्कार की भावना रखने वाले लोगों के मन को बदलने में अपना कोई रोल अदा नहीं किया. अब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से बदला लेने या उसे नीचा दिखाने के लिए वैसे ही औरतों को निशाना बना रहे हैं, जैसे पुराने जमाने में कोई बादशाह या कोई राजा अपनी सत्ता का दबदबा दिखाने के लिए अपने सिपाहियों से सामूहिक बलात्कार कराता था या वे सेनाएं दूसरे देश के लोगों का मन तोड़ने के लिए सामूहिक बलात्कार किया करती थीं. आख़िर क्या कारण है कि इतने सारे साधु-संतों के रहते हुए एक सत्तर साल की औरत के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और इन साधु-संतों का कोई भी असर समाज के उस वर्ग पर नहीं होता, जो अपनी हवस मिटाने, दूसरे समाज का मनोबल तोड़ने और उन्हें शर्मशार करने के लिए बलात्कार या औरत के ऊपर जुल्म करने को सबसे ज़्यादा असरदार तरीका मानता है.

बहुत सारी घटनाएं बाहर नहीं आ पातीं. दबे-कुचले वर्गों के साथ उसी वर्ग के लोग दबंगई करते हैं. उसी समाज के लोग औरतों, लड़कियों या बच्चियों का अपहरण करके उनके साथ बलात्कार करते हैं और उसके बाद उनकी जान भी ले लेते हैं, ताकि कोई सुबूत न रहे. यह सब क़ानून से कैसे रुकेगा, नहीं पता. यह सब साधु-संतों के प्रवचनों से भी कैसे रुकेगा, नहीं पता. क्योंकि, कई बड़े साधु-संत तो स्वयं इसी तरह के आरोपों में जेल में बंद हैं. दरअसल, समाज का विश्वास हर जगह से टूटता जा रहा है. राजनीति से उसका विश्वास लगभग उठ गया है. थोड़ा-बहुत न्यायपालिका में बचा है, पर उसके भी टूटने में बहुत वक्त नहीं लगने वाला. लेकिन सामाजिक नेता, जिनमें से अधिकांश जातियों के नेताओं में बदल गए हैं, उनका भी कोई असर न अपनी जाति पर है और न देश के बाकी हिस्से पर. समाज पर तो बिल्कुल नहीं.

अब सवाल यह है कि इसके बारे में सोचेगा कौन? यह यक्ष प्रश्न है और इसका उत्तर हमें भी नहीं मालूम. लेकिन, हम यह ज़रूर देख रहे हैं कि स्थितियां बहुत तेजी से खराब हो रही हैं और जो प्रतिस्पर्धा राजनीति में है कि अपने साथ चल रहे व्यक्ति की पीठ में छुरा घोंपो, उसे लंगड़ी मारो, वहीं प्रतिस्पर्धा और वहीं मानसिकता अब संतों में आ गई है. तब समाज की दशा भला कैसे सुधरेगी? धर्मग्रंथों में कहा गया है कि जब-जब पाप का घड़ा भरता है, तब-तब कोई अवतार या पैगंबर आता है और समाज को सुधारता है. इसका मतलब अभी पाप का घड़ा भरा नहीं है. अभी हमें ऐसी और भी घटनाएं देखने को मिलेंगी, जिससे वे लोग, जो यह सब नापसंद करते हैं और जिनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन खामोश रहते हैं, वे उठकर खड़े हो जाएं. याद आता है और उस पर अब भरोसा भी होता है कि:-

आसमां पर है खुदा और जमीं पर हम,
आजकल वह इस तरफ़ देखता है कम.

editor@chauthiduniya.com

अटल, लाल बहादुर और मोदी

मेघनाद देसाई

मोदी की जो सबसे चौंकाने वाली नीति है, वह है कल्याणकारी प्रावधानों पर ज़ोर देना. यूपीए ने अपनी कल्याणकारी योजनाएं ग़रीबी रेखा के आधार पर तैयार की थीं, लेकिन कुछ ग़रीब ऐसे भी हैं, जो ग़रीबी रेखा के नीचे नहीं हैं. ताज़ा बजट में हमने देखा कि सस्ती प्रीमियम दरों पर 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा और पेंशन के साथ-साथ सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की महत्वाकांक्षी योजना की बात कही गई है. जब इसे व्यापक रूप से लागू किया जाएगा, तो इससे करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचेगा. मोदी उन लोगों में से हैं, जो बीपीएल में नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद वह उनके (बीपीएल) भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं. इसीलिए वह रिटायरमेंट पेंशन और स्वास्थ्य बीमा की योजना लेकर आए हैं. इस दृष्टि से देखा जाए, तो मोदी हमें लाल बहादुर शास्त्री की याद दिलाते हैं. वह शास्त्री ही थे, जिन्होंने यह सवाल उठाया था कि सरकारी योजनाओं की वजह से आम आदमी के जीवन स्तर में कितना सुधार आया है?

नौ महीने की सत्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि कैसी है? चुनाव से पहले उनके आलोचक उन्हें हिटलर या उससे भी बुरे शख्स के रूप में पेश कर रहे थे. ऐसा कहा जा रहा था कि उनके सत्ता में आते ही मुसलमानों पर हमले शुरू हो जाएंगे. चुनाव के नतीजे आने से एक दिन पहले मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा था कि वह दिल्ली की आख़िरी कव्वाली की मजलिस में हिस्सा लेने के लिए वहां जा रही हैं. ये वे लोग थे, जो नरेंद्र मोदी का खौफ तरह-तरह से उजागर करने की कोशिश कर रहे थे. वहीं उनके बहुत से प्रशंसक ऐसे भी थे, जो अपनी खुद की कल्पनाओं को उनसे जोड़कर देख रहे थे. इसमें कोई शक नहीं था कि वह एक शक्तिशाली नेता बनने जा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल था कि वह रातोंरात देश की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था दुरुस्त कर देंगे या कांग्रेस की राज्यवादी नीति (जिसमें सब कुछ सरकारी नियंत्रण में हो) ख़त्म कर देंगे या फिर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मारग्रेट थैचर की तरह वामपंथियों एवं दक्षिणपंथियों, सबका निजीकरण कर देंगे. बिग-बैंग की तरह कोई बड़ी घटना होगी, जो मोदी काल के आगमन की घोषणा करेगी. यानी मोदी को लेकर पूरे देश में अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय थी.

लेकिन हमने जिस मोदी को देखा, वह एक बिल्कुल अलग व्यक्तित्व था. अपने कार्यकाल के पहले ही दिन से लोगों तक पहुंचने के लिए उन्होंने अलग रास्ता अपनाया. यह सोचने की बात है कि उनसे पहले किसी भी प्रधानमंत्री को यह क्यों नहीं सूझा कि वह अपने शपथ ग्रहण को एक बड़े सार्वजनिक समारोह में बदल सकता है. देश में और विदेश जाकर विश्व के नेताओं से उनके मिलने का सिलसिला जारी है. 10 लाख रुपये का सूट छोड़कर अब तक उन्होंने कोई ग़लत क़दम नहीं उठाया है. मोदी ने पूर्वी देशों के साथ रिश्तों को मज़बूती प्रदान की और अमेरिका एक सहयोगी देश बन गया. इस लिहाज़ से देखा जाए, तो मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की याद दिलाते हैं. वाजपेयी एक सफल विदेश मंत्री थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वह अपनी विदेश नीति में सफल रहे. अभी तक कोई बिग-बैंग परिवर्तन नहीं हुआ और न पुरानी शासन व्यवस्था में कोई दरार पड़ी है. यूपीए सरकार के समय से जारी नीति-गतिहीनता अभी भी बरकरार है. विकास के लिए आर्थिक सुधारों की कोशिश में आश्चर्यजनक रूप से ठहराव है. रेलवे या सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की संभावना सरकार ने सिरे से ख़ारिज कर दी है. यहां तक कि विनिवेश की रफ्तार भी सुस्त है. मोदी को सरकारी क्षेत्र से लगाव है, इसलिए वह इसे बेचने के बजाय अधिक कारगर बनाना चाहेंगे.

मोदी की जो सबसे चौंकाने वाली नीति है, वह है कल्याणकारी प्रावधानों पर ज़ोर देना. यूपीए ने अपनी कल्याणकारी योजनाएं ग़रीबी रेखा के आधार पर तैयार की थीं, लेकिन कुछ ग़रीब ऐसे भी हैं, जो ग़रीबी रेखा के नीचे नहीं हैं. ताज़ा बजट में हमने देखा कि सस्ती प्रीमियम दरों पर 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा और पेंशन के साथ-साथ सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की महत्वाकांक्षी योजना की बात कही गई है. जब इसे व्यापक रूप से लागू किया जाएगा, तो इससे करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचेगा. मोदी उन लोगों में से हैं, जो बीपीएल में नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद वह उनके (बीपीएल) भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं. इसीलिए वह रिटायरमेंट पेंशन और स्वास्थ्य बीमा की योजना लेकर आए हैं. इस दृष्टि से देखा जाए, तो मोदी हमें लाल बहादुर शास्त्री की याद दिलाते हैं. वह शास्त्री ही थे, जिन्होंने यह सवाल उठाया था कि सरकारी योजनाओं की वजह से आम आदमी के जीवन स्तर में कितना सुधार आया है? शास्त्री अपनी साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि कभी नहीं भूले. इसीलिए उन्हें याद रहा कि उनके जैसे करोड़ों और लोग हैं. दुर्भाग्यवश वह अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सके, ताकि नेहरूवादी भारी उद्योग की नीति बदल सकें.

शास्त्री में युद्ध का निर्णय लेने की क्षमता नेहरू से अधिक थी. आज़ादी के बाद देश को किसी युद्ध में उन्होंने पहली जीत दिलाई थी. हालांकि, मोदी को अभी तक वैसी स्थिति से नहीं गुज़रना पड़ा है, लेकिन यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर ऐसी कोई नौबत आई, तो वह पूरे नंबरों के साथ पास हो जाएंगे. दरअसल, कोई भी नरेंद्र मोदी में एक उदारवादी आम नेता देखने की उम्मीद नहीं रखता था. कुछ लोगों को निराशा है कि जिस तेजी से बदलाव की उम्मीद थी, वह नहीं हो रही है. मोदी भारत में विकास की दर में तेजी लाने के दृढ़ संकल्प के साथ-साथ पिछली सरकारों की तरह ग़रीब एवं कमज़ोर वर्ग की उम्मीदें पूरी करना चाहते हैं. इसके अलावा भारत को विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों के साथ खड़ा करने का उनका निरंतर प्रयास भी जारी है. मोदी के लिए कई ख़तरे हैं. उन्हें राज्यसभा में एक लंबे समय तक ज़बरदस्त विरोध का सामना करना पड़ेगा. उन्हें देश में भी उसी स्टेटमैनशिप (राजनीतिक कुशलता) को अपनाना होगा, जिसका प्रदर्शन उन्होंने विदेशों में किया है. आम चुनाव में भाजपा को ज़बरदस्त कामयाबी दिलाकर उन्होंने पार्टी के दूसरे नेताओं को हाशिये पर डाल दिया है. लेकिन, कामयाबी का वह स्तर कायम रखना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है. अगर विकास की रफ्तार धीमी होती है, तो धोखे खाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि दोस्त ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट की मानें तो 102 में से 85 बीमारियों या चोटों के पीछे पर्यावरण से जुड़े कारक जिम्मेदार होते हैं, जिसके कारण रोगों से लड़ने वाले हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है. जानते हैं, बदलती जीवनशैली और मौसम के बीच कैसे कर सकते हैं हम अपने इम्युनिटी को मजबूत...

इंफेक्शन से बचना है तो इम्युनिटी को मजबूत करें

मोनिशा भटनागर

बदलते मौसम का मानव शरीर के इम्युनिटी सिस्टम (प्रतिरोधक क्षमता) पर सर्वाधिक प्रभाव होता है. जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, तब शरीर किसी भी तरह के इंफेक्शन से लड़ने में असमर्थ हो जाता है. नतीजा, हम बार–बार बीमार पड़ने लगते हैं, लेकिन हम कुछ बातों पर ध्यान दें, तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हमारा शरीर इंफेक्शन से लड़ने में सक्षम हो जाएगा.

लक्षण

बदलते मौसम में एलर्जिक और वायरल संक्रमण का खतरा काफी बढ़ जाता है. सुबह व शाम की ठंड और दिनभर गर्मी के इस मौसमी बदलाव में सामान्य बुखार, जुकाम, खांसी और किसी भी प्रकार के फ्लू इसके प्रमुख लक्षणों में से हैं. वायरल, ब्रोनकाइटिस, डायरिया, सांस लेने में परेशानी और गला खराब होना इस मौसम में आम है. ऐसे मौसम में डायबिटीज या क्रोनिक बीमारी के मरीज, छोटे बच्चे, बूढ़े व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं को अपना खास ख्याल रखने की ज़रूरत है.

सेवन करें

लिक्विड डाइट जैसे छाछ, नींबू पानी, फलों या सब्जियों का रस और पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं. लिक्विड डाइट शरीर में मौजूद विषैले तत्वों को बाहर निकाल देते हैं. पौष्टिक आहार लें और बाहर के खाने से परहेज करें. जहां तक संभव हो, ठंडी चीजों को खाने से बचें. साबुत अनाज, हरी सब्जियां, फलियां और दालें अधिक मात्रा में खाएं. भोजन में एंजाइम्स विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर खाद्य पदार्थ जरूर शामिल करें. गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे अनाज खाएं. भोजन के साथ सलाद का उपयोग अधिक से अधिक करें. आंवला, नीबू, संतरा और मौसमी जैसे फलों का सेवन करें.

फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दें

हमारा शरीर तमाम तरह के हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस के संपर्क में रहता है, जो इम्युनिटी कमज़ोर होने पर आपको बीमार कर देते हैं. इसलिए इम्युनिटी या प्रतिरोधक क्षमता मज़बूत बनाये रखने की ज़रूरत है. इम्युनिटी बढ़ाने के सबसे कारगर उपाय हैं पौष्टिक खाना और नियमित व्यायाम. खाने में रंगीन सब्जियां जैसे हरी सब्जियां और फलों का सेवन जितना ज्यादा होगा, शरीर उतना ही सेहतमंद रहेगा. अच्छे खान–पान, नियमित व्यायाम या योग के साथ–साथ फिजिकल फिटनेस इम्युनिटी को बढ़ाने और मज़बूत करने के लिए अहम है. इम्युनिटी बढ़ाने के लिए एलोपैथिक मेडिसिन में कोई दवाई नहीं है. कई लोग विटामिन की गोली ये सोच कर लेते हैं कि इससे इम्युनिटी बढ़ती है, पर ऐसा नहीं है. बदलते मौसम में बीमारियों से बचने के लिए भीड़भाड़ वाली जगहों पर न जाएं, ज्यादा धूल–मिटटी वाली जगहों से दूर रहें और खासकर कोल्ड एक्सपोज़र से अपना बचाव करें. ऐसे लोग, जो स्टेरॉयड्स लेते हैं, डायबिटीज, लीवर या टीबी–कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनमें प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही कमज़ोर होती है. ऐसे लोगों को बदलते मौसम में अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत है.

डॉ राजेश भटनागर, सीएमओ, सी.जी.एच.एस (दिल्ली)

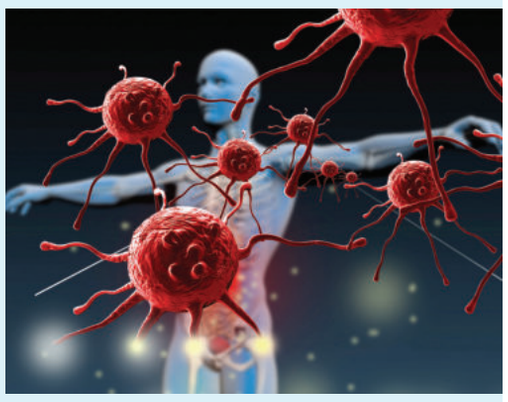

क्या करें

पानी की पर्याप्त मात्रा लें. प्रचुर मात्रा में पानी का सेवन किडनी की कार्यप्रणाली को चुस्त–दुरस्त रखने और शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए बहुत जरूरी होता है. इम्युनिटी को बेहतर बनाने में संपूर्ण और संतुलित आहार, जिसमें फल, सब्जियां, अनाज और दूसरे आवश्यक पोषक तत्व संतुलित मात्रा में होनी चाहिए. ब्रोकोली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, गोभी आदि सब्जियां एक प्रकार के कैमिकल का उत्पादन करती हैं, जो कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में आपकी मदद करती हैं. इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए आसपास के वातावरण को साफ रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गंदगी के कारण संक्रमण की चपेट में आने का खतरा बढ़ जाता है. फल और सब्जियों को खाने और पकाने से पहले अच्छी तरह से धो लें. खाना बनाने और खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह साफ करें. इसके अलावा अपने शरीर और कपड़ों की साफ–सफाई का भी विशेष ख्याल रखें. तनाव से बचें, क्योंकि तनाव से पाचन तंत्र प्रभावित होने के कारण इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है. एक्सरसाइज, योग व प्राणायाम व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से संतुलित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. अधिक वसा वाला आहार हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाता है, लेकिन अपने भोजन में सही वसा का सेवन जरूर करें. यह इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में आपकी मदद करता है. जिंक ऐसा मिनरल है, जो एंटीबॉडीस, टी–सेल्स व सफेद रक्त कणों में बढ़ोत्तरी कर इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है. एक शोध के अनुसार, जिंक की कमी बैक्टीरिया, वायरस व परजीवी द्वारा किए गए आक्रमणों से आपका बचाव नहीं कर पाते. मोटापा प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य के बीच बाधा उत्पन्न करता है, जिससे संक्रमण का जोखिम बढ़ जाता है. इसलिए अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले अपने मोटापे को कम करें. आपके शरीर और मस्तिष्क के ठीक ढंग से काम करने के लिए 6–8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है. अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते, तो इम्यून सिस्टम को पुनर्निर्माण का समय नहीं मिलने के कारण वह कमजोर हो जाता है.■

feedback@chauthiduniya.com

नीली बलाई ने खोजी पत्रकारिता का इतिहास बदल दिया

शफीक आलम

feedback@chauthiduniya.com

न्यूयॉर्क वर्ल्ड अखबार के एडिटर अपने अख़बार के नौजवान और ख़ूबसूरत रिपोर्टर नीली बलाई को एक बहुत ही खतरनाक और दिलचस्प मिशन के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे थे– हम तुम्हें वहां इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि वहां जाकर कोई सनसनीखेज़ खुलासा करो. हां, तुम से यह आशा ज़रूर है कि चीज़ों को जिस तरह से देखो, वैसे ही लिख डालो. अगर बुरी हैं, तो बुरी और अच्छी हैं, तो अच्छी. नीली एडिटर की बात सुनकर मुस्कुराई थी. लेकिन तुम्हारी यह मानीखेज मुस्कराहट मुझे डरा रही है. एडिटर की बात सुनकर नीली ने जवाब में सिर्फ इतना कहा था–अब मैं बिल्कुल नहीं मुस्कुराउंगी. वह एडिटर के कमरे से भारी क़दमों से बहार निकल कर उस दिलचस्प और खतरनाक मिशन के लिए खुद को तैयार करने लगीं. हालांकि नीली को खुद पर भरोसा था, लेकिन मिशन के खतरों के मद्देनज़र उन्हें खुद को तैयार करने में काफी समय लग गया. यह मिशन था न्यूयॉर्क स्थित ब्लैकवेल आइलैंड पागलखाने की क्रियाकलापों की वास्तविक हालात को जनता के सामने लाने का. चूंकि यह पागलखाना एक द्वीप पर स्थित था, इसलिए आम लोगों की बात कौन करे, वहां इलाज करवा रहे मरीजों के रिश्तेदारों के लिए भी इस पर नज़र रख पाना नामुमकिन था. इसी वजह से इस काम को द न्यूयॉर्क वर्ल्ड अख़बार ने अपने हाथों में लेकर यहां की कार्यप्रणाली पर एक विस्तृत और वास्तविक रिपोर्ट प्रकाशित करने का फैसला किया. अख़बार के एडिटर के पास इस काम के लिए नीली बलाई से उपयुक्त कोई दूसरा पत्रकार नहीं मिला.

एलिज़ाबेथ जेन कोकरेन उर्फ़नीली बलाई को जब वर्ष 1887 में पिट्सबर्ग डिस्पैच अख़बार ने एक बार फिर उन्हें थिएटर और आर्ट्स की रिपोर्टिंग का काम सौंपा, तो उन्होंने यह फैसला कर लिया कि अब पिट्सबर्ग डिस्पैच में उनके दिन पूरे हो गए हैं. यहां से निकलने के बाद उन्होंने सीधे आधुनिक पत्रकारिता के पितामह कहे जाने वाले जोसफ पुलित्ज़र के अख़बार द न्यूयॉर्क वर्ल्ड का रुख किया. यह ऐसा क़दम था, जो उन्हें गुमनामी के अंधेरे से निकाल कर पत्रकारिता की शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाने वाला था. द न्यूयॉर्क वर्ल्ड में क़दम रखने के कुछ वर्ष बाद उन्हें अख़बार की तरफ से एक अंडरकवर रिपोर्टिंग की पेशकश की गई. अख़बार के एडिटर नें इस रिपोर्टिंग से जुड़े खतरे को देखते हुए उन्हें इस मिशन पर जाने के लिए मन बनाने का पूरा समय दिया, क्योंकि नीली को ब्लैकवेल आइलैंड पागलखाने में एक पागल के रूप में दाखिल होना था, जिसमें मेडिकल जांच की प्रक्रिया से भी गुजरना शामिल था. काम बहुत ही खतरनाक और नाज़ुक था, क्योंकि एक गलत कदम पूरे मिशन को तहस–नहस कर देता.

जब नीली ने इस काम के लिए खुद को तैयार कर लिए, तब भी उनके मन में कई आशंकाएं थीं, जिन्हें वह दूर करना चाहती थीं. सबसे पहली आशंका यह कि वह पागल खाने कैसे पहुंचेंगीं. अगर पागल बन कर वहां पहुंच गईं, तो उन्हें वहां से निकालने के लिए कौन आएगा, कब आएगा? अख़बार के एडिटर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह समय रहते उन्हें वहां से निकाल लाएंगे.

एलिज़ाबेथ जेन कोकरेन उर्फ़नीली बलाई को जब वर्ष 1887 में पिट्सबर्ग डिस्पैच अख़बार ने एक बार फिर उन्हें थिएटर और आर्ट्स की रिपोर्टिंग का काम सौंपा, तो उन्होंने यह फैसला कर लिया कि अब पिट्सबर्ग डिस्पैच में उनके दिन पूरे हो गए हैं. यहां से निकलने के बाद उन्होंने सीधे आधुनिक पत्रकारिता के पितामह कहे जाने वाले जोसफ पुलित्ज़र के अख़बार द न्यूयॉर्क वर्ल्ड का रुख किया. यह ऐसा क़दम था, जो उन्हें गुमनामी के अंधेरे से निकाल कर पत्रकारिता की शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाने वाला था. द न्यूयॉर्क वर्ल्ड में क़दम रखने के कुछ वर्ष बाद उन्हें अख़बार की तरफ से एक अंडरकवर रिपोर्टिंग की पेशकश की गई.

नीली ने कई रातों तक पागल दिखने का अभ्यास किया. जब वह खुद से आस्वस्थ हो गईं, तो उन्होंने कामकाजी महिलाओं के बोर्डिंग हाउस के रास्ते ब्लैकवेल आइलैंड पागल खाने में दाखिल होने का फैसला किया. बोर्डिंग हाउस में अपनी पहली ही रात को उन्होंने अपने बिस्तर में जाने से इंकार कर दिया. कहने लगीं कि यहां सभी पागल हैं और उन्हें उन सब से डर लग रहा है. फिर क्या था, दूसरे दिन ही पुलिस आ गई. नीली को अदालत में पेश किया गया. जज इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्हें कोई नशीली दवा दी गई है. उसके बाद अदालत के आदेश पर उनकी जांच हुई. जांच के बाद एक के बाद एक कई डॉक्टरों ने उन्हें पागल घोषित कर दिया. मैं इस केस से नाउम्मीद हूं. मेरे हिसाब से मरीज़ को वहां होना चाहिए, जहां उसका पूरा ख्याल रखा जा सके, डॉक्टरों में से एक ने अपनी रिपोर्ट में कहा था. डॉक्टरी जांच में क्या हुआ, नीली को पता नहीं चला, क्योंकि मेडिकल को धोखा देने के लिए उन्होंने कुछ नशीली दवाइयां ले रखी थीं. एक अंजान पागल और रहस्यमयी लड़की का मामला अख़बारों की सुर्ख़ियों में भी छाया रहा, जो हताशापूर्ण लहजे में चीख रही थी–मैं कौन हूं, मुझे मालूम नहीं है. नीली का मकसद पूरा हो चूका था. वह अपने काम में लग चुकी थीं. उन्होंने ब्लैकवेल आइलैंड अस्पताल में देखा कि वहां का खाना घटिया था. पीने का पानी जानवरों के पीने के लिहाज़ से भी गन्दा था. खतरनाक मरीजों को एक साथ रस्सियों में बांध कर रखा गया था. मरीजों को लगातार सख्त सर्दी में बाहर बैठने पर मजबूर किया जा रहा था. अस्पताल में चारों तरफ चूहों का राज था. नहाने का पानी बर्फ बना हुआ था. नर्सें डाइनों की तरह थीं और बिना गाली के बात नहीं करती थीं. नीली लिखतीं हैं–मेरे दांत बज रहे थे. ठंड से मेरी हड्डियां चटक रहीं थीं. पूरे दिन के लिए मुझे तीन बाल्टी बर्फ की तरह ठंडा पानी दिया गया. कुल मिला कर यह जगह इंसानों के लिए नहीं थी.

दस दिन ब्लैकवेल आइलैंड में गुजरने के बाद योजना के मुताबिक नीली को बाहर निकाल लिया गया. वहां से निकलने के बाद उन्होंने यहां गुज़ारे वक़्त की याद पहले उनके अख़बार में छपी. उसके बाद उसे किताबी शक्ल में टेन डेज इन ए मैड–हाउस के नाम से छपा गया. जहां यह रिपोर्ट अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ को कठघरे में खड़ा किया, वहीं अधिकारियों ने इस उपेक्षित अस्पताल पर ध्यान देना शुरू किया. न्यूयॉर्क की ग्रैंड जूरी ने खुद अपना अलग जांच करवा कर यहां की हालत सुधारने के लिए अपने सुझाव रखे. सरकार ने देश के पागलखानों के लिए फंड में 8.5 लाख डॉलर का इजाफा किया और नीली ने खोजी पत्रकारिता के इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया. इसके बाद नीली बलाई को दुनिया घूमने के लिए एक दूसरा असाइनमेंट मिला, जिसके बारे में उन्होंने अराउंड द वर्ल्ड इन एट डेज नामक किताब में लिखी है.■

पहली बार भारत ने समुद्र की रणनीतिक कूटनीति को महत्व देते हुए तीन समुद्रतटीय देशों की यात्रा पूरी की है. यानी यह कहा जा सकता है कि भारत ने हिंद महासागर की अहमियत को पहचान लिया है. अगर वाकई में यह यात्रा समुद्री कूटनीति को गहराई से समझकर की गई है तो यह विश्व पटल में भारत को मजबूत स्थिति देने के लिए बढ़ाया गया एक सूझबूझ भरा कदम है, क्योंकि मोदी की यह यात्रा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में द्वीपीय देशों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाने वाला सफर साबित हो सकती है. ऐसा करके भारत अपने पक्ष में रणनीतिक संतुलन बनाने में कामयाब हो सकता है.

समुद्री देशों के सफर के गहरे मायने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दुनियाभर में घूम रहे हैं. विपक्ष इसे समय और धन की बबार्दी कह रहा है तो समर्थक इसे दुनियाभर के अलग-अलग देशों के साथ नये रिश्ते बनाने और पुराने रिश्ते मजबूत करने के लिए जरूरी मान रहे हैं. खैर, सत्ता और विपक्ष की इस असहमति के अपने-अपने तर्क हैं. लेकिन समुद्री देशों के सफर की गहराई नापने के लिए इसका निष्पक्ष विश्लेषण जरूरी है. तीनों देशों सेशल्स, मॉरीशस और श्रीलंका के साथ भारत के भौगोलिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को समझना बेहद जरूरी है.

अरुण तिवारी

मॉरीशस, सेशल्स और श्रीलंका में नरेंद्र मोदी का जाना और वहां पर हुए समझौतों को समझें तो एक तरह से भारत ने अरब सागर के द्वीपों में सांस्कृतिक और सामरिक हितों को साधने की कोशिश की है. श्रीलंका की बात करें तो यहां बुनियादी ढांचे और पर्यटन पर जोर दिया गया है. श्रीलंका और भारत के रामायणकालीन संबंधों का जिक्र करके प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि भौगोलिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक रूप से दोनों देशों की बीच की दूरी घटाने का मन भारत बना चुका है. मॉरीशस और सेशल्स के साथ हुए समझौतों पर नजर घुमाएं तो साफ दिखेगा कि भारत हिंद महासागर में सुरक्षा, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक संबंधों को स्थापित कर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है.

अगर इतिहास उठाकर देखें तो हिंद महासागर ने व्यापार और संस्कृतियों को हमेशा जोड़ने का काम किया है. वैसे भी संस्कृति में इसे रत्नाकर यानी रत्न उत्पन्न करने वाला कहा गया है. ऐसे में मॉरीशस और सेशल्स के बीच संबंधों को स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाना हितकर ही साबित होगा. हिंद महासागर अपने नाम के अनुकूल ही रत्न उत्पन्न करने वाला साबित हो सकता है. इतिहास बताता है कि हिंद महासागर दो दुनियाओं यानी पूरब और पश्चिम को जोड़ने वाला एक पुल, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से हाइवे और सामरिक लिहाज से रणनीतिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता रहा है. ऐसे में अगर किसी देशों को वैश्विक व्यवस्था में अपना पैर जमाना है, दुनिया की अगुवाई करने वाले देशों की कतार में खड़ा होना है तो महासागरीय कूटनीति में अपनी पकड़ बनानी ही होगी. तो कुछ सवाल उठाने जरूरी हैं–

पहला सवाल कि क्या मौजूदा स्थिति में हम महासागरीय कूटनीति में कहीं कोई जगह रखते हैं? दूसरा सवाल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन देशों की यात्रा क्या हमें महासागरीय कूटनीति का हिस्सा बनने में मददगार साबित होगी?

पहली बार भारत ने समुद्र की रणनीतिक कूटनीति को महत्व देते हुए तीन समुद्रतटीय देशों की यात्रा पूरी की है. यानी यह कहा जा सकता है कि भारत ने हिंद महासागर की अहमियत को पहचान लिया है. अगर वाकई में यह यात्रा समुद्री कूटनीति को गहराई से समझकर की गई है तो यह विश्व पटल में भारत को मजबूत स्थिति देने के लिए बढ़ाया गया एक सूझबूझ भरा कदम है, क्योंकि मोदी की यह यात्रा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में द्वीपीय देशों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाने वाला सफर साबित हो सकती है. ऐसा करके भारत अपने पक्ष में रणनीतिक संतुलन बनाने में कामयाब हो सकता है. अगर ऐसा हो सका, तो यकीन मानिए कि यह स्थिति इक्कीसवीं सदी में निर्मित हो रही नई विश्व व्यवस्था में निर्णायक भूमिका दिलाएगी. लेकिन इस तरफ कदम बढ़ाने का जोखिम भी है. अगर भारत असफल साबित हुआ तो भारत की मौजूदा अंतरराष्ट्रीय स्थिति को धक्का भी लग सकता है.

प्रधानमंत्री की समुद्री देशों की यात्रा सेशल्स से शुरू हुई. दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चार समझौते हुए, जिनमें–हाइड्रोग्राफी, नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचा विकास और इलेक्ट्रॉनिक नौवहन चार्टों पर हस्ताक्षर शामिल हैं. इसके साथ ही भारत ने सेशेल्स के लिए दूसरे डॉर्नियर लड़ाकू विमान और द्विपक्षीय सहयोग के प्रतीक के रूप में तटीय निगरानी रडार परियोजना की घोषणा भी की. हिंद महासागर में बसा अफ्रीकी देश सेशेल्स 115 द्वीपों का समूह है. इसकी आबादी का आठ फीसदी हिस्सा भारतीय मूल के लोगों का है. 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दौरा किया था और अब प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने यात्रा की है. हालांकि 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भी सेशेल्स गई थीं.

मोदी की सेशेल्स यात्रा के मुख्य लक्ष्य रक्षा और सागरीय सुरक्षा के क्षेत्र में परस्पर संबंधों को मजबूत करना था. हिंद महासागर में समुद्री डाकुओं के आतंक से व्यापारिक गतिविधियों पर लंबे अरसे से असर पड़ रहा है और भारत इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी है. भारत पिछले कई वर्षों से सामुद्रिक निगरानी में सेशेल्स की नौसैनिक क्षमता बढ़ाने के लिए सहयोग करता आ रहा है. 2006 और 2014 में दो जहाज उपहारस्वरूप दिए गए थे. इनके अलावा सतर्कता और निगरानी के लिए जरूरी साजो-सामान भी मुहैया कराए गए हैं. 2013 में एक हवाई जहाज भी दिया गया था. सेशेल्स के हिस्से में वृहत 1-3 मिलियन वर्ग किलोमीटर का सागर है, जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है. सेशल्स के बाद प्रधानमंत्री मॉरीशस पहुंचे. इसके साथ दोहरे कराधान से बचाव की संधि पर बातचीत की. यह काफी समय से ठप पड़ी थी. हालांकि बजट में सरकार ने गार यानी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल को टाल कर भारत ने पहले ही यह संकेत दे दिए थे कि वह मॉरीशस के साथ संबंध बढ़ाने और इन्हें मजबूत करने का मन बना चुका है. भारत ने मॉरीशस को बातचीत के दौरान यह भरोसा दिलाया है कि भारत में इसके वित्तीय और व्यापारिक हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा. हालांकि गार को टालने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोद की विपक्ष ने आलोचना भी की, क्योंकि कालेधन को मुद्दा बानाने वाले नरेंद्र मोदी जब इस नियम को ठंडे बस्ते में डालते नजर आते हैं तो सवाल उठने लगते हैं कि क्या वह इस नियम में ढील देकर दूसरे निवेश बढ़ाने पर तो जोर दे रहे हैं, लेकिन टैक्स भरने के पारदर्शी नियम को सख्ती से लागू करने से बच रहे हैं? टैक्स चोरी और काले धन को रोकने हेतु बनाया गया गार यानी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल एक प्रकार का नियम है, जिसके पीछे सरकार का एक ही लक्ष्य है कि जो भी विदेशी कंपनी भारत में निवेश करे, वह यहां पर तय नियमों के मुताबिक टैक्स दे.

मॉरीशस टैक्स हैवेंस का एक अहम घटक देश है. भारत को संदेह है कि वहां से भारत आने वाला निवेश कालेधन का हिस्सा होता ही है. दोहरे कराधान से बचाव संबंधी आपसी संधि के कारण भारतीय कंपनियों पर यह आरोप लगता रहा है कि मॉरीशस के द्वारा वह भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम कालेधन को सफेद बनाने का काम करती हैं. प्रधानमंत्री ने मॉरीशस को असैन्य परियोजनाओं के विकास के लिए पचास करोड़ डालर का कर्ज सुविधा देने और वहां दूसरा साइबर शहर स्थापित करने, पेट्रोलियम जरूरतों को पूरा करने में सहयोग की पेशकश की है.

मॉरीशस में भारतीय मूल के लोगों की बड़ी आबादी है, जो अंगरेजों के द्वारा मजदूर के रूप में ले जाए गए भारतीयों के वंशज हैं. जिस समुद्री तट पर भारतीय मजदूरों का पहला दस्ता मॉरीशस के चीनी कारखानों और गन्ना खेतों में काम करने के लिए उतरा था, उसे अप्रवासी तट कहा जाता है. मॉरीशस का राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है, जो महात्मा गांधी के प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह की तारीख है. यहां के लोग 1968 में मिली आजादी का प्रेरणास्नेत गांधी को ही मानते हैं. भारत का 70 फीसदी ऊर्जा आयात समुद्री मार्ग से होता है, जिसकी सुरक्षा के लिए मॉरीशस से सहयोग बहुत अहम है.

प्रधानमंत्री मोदी की मॉरीशस यात्रा के दौरान पांच समझौतों पर हस्ताक्षर हुए तथा भारत ने आसान शर्तों पर 500 मिलियन डॉलर की राशि देने का प्रस्ताव किया है. इन समझौतों में मॉरीशस के व्यापक समुद्री संसाधनों का उपयोग करना तथा तेल के भंडारण-केंद्रों की स्थापना कर अफ्रीका में उत्पादों का फिर से आयात करना आदि शामिल हैं. मॉरीशस इन देशों में शामिल है, जो काला धन छुपाने के लिए कुख्यात हैं. दोनों देशों के बीच कर-संबंधी समझौते हैं, जिन्हें बेहतर करने की दिशा में भी बातचीत हुई है. समझा जाता है कि भारत ने मॉरीशस को हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव पर अपनी चिंता से अवगत कराया है.

प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा से पूर्व श्रीलंकाई प्रधानमंत्री ने भारतीय मछुआरों को लेकर जो बयान दिया था, इससे स्पष्ट हो गया था कि श्रीलंका भारत के साथ अभी बड़ी सौदेबाजी करने का इच्छुक है, क्योंकि आम तौर पर कोई श्रीलंकाई प्रधानमंत्री भारतीय मछुआरों को लेकर वैसा बयान नहीं देते थे. हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने वहां जाकर मछुआरों के मुद्दे को बेहद जटिल करार दिया और स्पष्ट किया कि यह आजीविका और मानवीय चिंता से जुड़ा मुद्दा है, जिसका दीर्घकालिक समाधान ढूंढने की जरूरत है. इन्होंने तमिल बहुल उत्तरी इलाके को शक्तियां सौंपने के मुद्दे पर तेरहवें संविधान संशोधन के जल्द और पूर्ण क्रियान्वयन पर जोर भी दिया, जो तमिल बहुल प्रांत की स्वायत्तता से जुड़ा विषय है. इसके बाद चार समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें कूटनीतिक स्तर के पासपोर्ट पानेवालों को वीजा में छूट, सीमा शुल्क में पारस्परिक सहयोग, युवा विकास और श्रीलंका विश्वविद्यालय में रबींद्रनाथ टैगोर संग्रहालय की स्थापना आदि शामिल हैं. प्रधानमंत्री ने यह घोषणा भी की कि भारतीय तेल कंपनी की इकाई लंका आईओसी और सिलोन पेट्रोलियम कोर ने साझा शर्तों के साथ संयुक्त रूप से त्रिंकोमाली में अपर टैंक फॉर्म ऑफ द चाइना बे इंस्टॉलेशन स्थापित करने पर सहमति जतायी है. साथ ही प्रधानमंत्री ने श्रीलंकाई रेलवे को 31..8 लाख डॉलर का नया ऋण दिये जाने की घोषणा की.

कुल मिलाकर तीनों देशों के साथ हुए समझौतों पर नजर दौड़ाएं तो भारत ने अरब सागर के द्वीपों में सांस्कृतिक, सामरिक और व्यापारिक हितों को साधने की कोशिश शुरू की है. तमाम उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध हमेशा से मजबूत रहे हैं. पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2013.14 में द्विपक्षीय व्यापार 5.23 बिलियन डॉलर था, जिसमें भारत का निर्यात 3.98 बिलियन डॉलर और श्रीलंकाई निर्यात 678 मिलियन डॉलर रहा था. मोदी ने कहा है कि दिसंबर, 1998 में किए गए मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाते हुए श्रीलंकाई सामानों के भारत में आने की प्रक्रिया को सुगम बनाया जाएगा. इस दिशा में 2003 से शुरू हुए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को भी अंतिम रूप देने पर विचार किया जा रहा है. मोदी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए श्रीलंकाई नागरिकों को आगमन पर वीजा देने की घोषणा की है. निश्चित रूप से यह कदम व्यापारिक, पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्र में बड़ा योगदान करेगा. इस यात्रा के दौरान नागरिक परमाणु ऊर्जा, कृषि, नालंदा विश्वविद्यालय और सामुद्रिक सुरक्षा से जुड़े समझौतों पर सहमति बनी है.

कुल मिलाकर तीनों देशों के साथ संबंध बनाना विश्व व्यवस्था में अपनी मजबूत जमीन तलाशने की रणनीति का हिस्सा दिखाई देता है. हालांकि यह सफर देश के लिए कितना सुहाना साबित होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

सभी जानवर एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे. तभी पक्षीराज गरूण वहां उपस्थित हुए और उपस्थित सभी जानवरों को सम्बोधित करते हुए बोले–सोनू हाथी प्रतिदिन पत्थर लेकर गड्ढे तक जाता था किंतु जब उसने देखा कि उस गड्ढे में मेरे अंडे रखे हुए हैं तो वह पत्थरों को उसमें न डालकर पास ही जमीन पर एकत्रित करता रहा. सोनू ने अपने राजा बनने के लालच को छोड़ एक जीव को बचाना ज्यादा उपयोगी समझा. उसकी इस परोपकार की भावना को देखकर हम पक्षियों ने तय किया कि जो अपने लालच को छोड़कर दूसरों के सुख–दुःख का ध्यान रखें वही सच्चे तौर पर शासक बनने का अधिकारी है.

साई बाबा मोक्षदाता हैं

चौथी दुनिया ब्यूरो

मृत्यु के समय जो अंतिम इच्छा या भावना होती है, वही भवितव्यता का निर्माण करती है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो अपने जीवन के अंतिम क्षण में मुझे स्मरण करता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है तथा उस समय वह जो कुछ भी दृश्य देखता है, उसी को अन्त में पाता है. यह कोई भी निश्चयात्मक रुप से नहीं कह सकता कि उस क्षण हम केवल उत्तम विचार ही कर सकेंगे. जहां तक अनुभव में आया है, ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय अनेक कारणों से भयभीत होने की संभावना अधिक होती है. इसके अनेक कारण है. इसलिये मन को इच्छानुसार किसी उत्तम विचार के चिंतन में ही लगाने के लिए नित्याभ्यास अत्यन्त आवश्यक है. इस कारण सभी संतों ने हरिस्मरण और जप को ही श्रेष्ठ बताया है, ताकि मृत्यु के समय हम किसी घरेलू उलझन में न पड़ जायें. अतः ऐसे अवसर पर भक्तगण पूर्णतः सन्तों के शरणागत हो जाते हैं, ताकि संत, जो कि सर्वज्ञ है, उचित पथप्रदर्शन कर हमारी यथेष्ठ सहायता करें. इसी प्रकार का उदाहरण नीचे दिया गया है.

एक सन्यासी विजयानंद मानसरोवर की यात्रा करने निकले. मार्ग में वे बाबा की कीर्ति सुनकर शिरडी आये, जहां उनकी भेंट हद्वार के सोमदेव जी स्वामी से हुई और इनसे उन्होंने मानसरोवर की यात्रा के सम्बन्ध में पूछताछ की. स्वामी जी ने उन्हें बताया कि गंगोत्री से मानसरोवर 500 मील उत्तर की ओर है तथा मार्ग में जो कष्ट होते हैं, उनका भी उल्लेख किया जैसे कि बर्फ की अधिकता, 50 कोस तक भाषा में भिन्नता तथा भूटानवासियों के संशयी स्वभाव, जो यात्रियों को अधिक कष्ट पहुंचाया करते हैं. यह सब सुनकर सन्यासी का चित्त उदास हो गया और उसने यात्रा करने का विचार त्यागकर मस्जिद में जाकर बाबा के श्री चरणों का स्पर्श किया. बाबा क्रोधित होकर कहने लगे– इस निकम्मे सन्यासी को निकालो यहां से. इसका संग करना व्यर्थ है. सन्यासी बाबा के स्वभाव से पूर्ण अपरिचित था. उसे बड़ी निराशा हुई, लेकिन वहां जो कुछ भी गतिविधियां चल रही थीं, उन्हें वह बैठे–बैठे ही देखता रहा. प्रातःकाल का दरबार लोगों से ठसाठस भरा

बाबा ने उसका अंतकाल समीप देखकर उसे यह उपचार बता दिया और साथ ही रामविजय पढ़ने की भी आज्ञा दी, जिससे यमराज अधिक प्रसन्न होते हैं. दूसरे दिन स्नानादि तथा अन्य शुद्धि के कृत्य कर उसने लेंडी बाग के एकांत स्थान में बैठकर भागवत का पाठ आरम्भ कर दिया. दूसरी बार का पठन समाप्त होने पर वह बहुत थक गया और वाड़े में आकर दो दिन ठहरा.

हुआ था और बाबा को यथाविधि अभिषेक कराया जा रहा था. कोई पाद–प्रक्षालन कर रहा था तो कोई चरणों को छूकर तथा कोई तीर्थस्पर्श से अपने नेत्र सफल कर रहा था. कुछ लोग उन्हें चन्दन का लेप लगा हे थे तो कोई उनके शरीर में इत्र ही मल रहा था. जातिपाति का भेदभाव भुलाकर सब भक्त यह कार्य कर रहे थे. यद्यपि बाबा उस पर क्रोधित हो गये थे तो भी सन्यासी के हृदय में उनके प्रति बड़ा प्रेम उत्पन्न हो गया था. उसे यह स्थान छोड़ने की इच्छा ही न होती थी. दो दिन के पश्चात् ही मद्रास से पत्र आया कि उसकी मां की स्थिति अत्यन्त चिंताजनक है, जिसे पढ़कर उसे बड़ी निराशा हुई और वह अपनी मां के दर्शन की इच्छा करने लगा, लेकिन बाबा की आज्ञा के बिना वह शिरडी से जा ही कैसे सकता था. इसलिये वह हाथ में पत्र लेकर उनके समीप गया और उनसे घर लौटने की अनुमति मांगी. त्रिकालदर्शी बाबा को तो सबका भविष्य विदित ही था. उन्होंने कहा कि जब तुम्हें अपनी मां से इतना मोह था तो फिर सन्यास धारण करने का कष्ट ही क्यों उठाया. ममता या मोह भगवा वस्त्रधारियों को क्या शोभा देता है. जाओ, चुपचाप अपने स्थान पर रहकर कुछ दिन शांतिपूर्वक बिताओ लेकिन सावधान. वाड़े में चोर अधिक हैं. इसलिए द्वार बंद कर सावधानी से रहना, नहीं तो चोर सब कुछ चुराकर ले जायेंगे. लक्ष्मी यानी संपत्ति चंचला है और यह शरीर भी नाशवान है, ऐसा ही समझ कर इहलौकिक व पालौकिक समस्त पदार्थों का मोह त्याग कर अपना कर्त्व्य करो. जो इस प्रकार का आचरण कर श्रीहरि के शरणागत हो जाता है, उसका सब कष्टों से शीघ्र छुटकार हो उसे परमानंद की प्राप्ति हो जाती है. जो परमात्मा का ध्यान व चिंतन प्रेम और भक्ति प्रेम पूर्वक करता है, परमात्मा भी उसकी अविलम्ब सहायता करते हैं. पूर्वजन्मों के शुभ संस्कारों के फलस्वरुप ही तुम यहां पहुंचे हो और अब जो कुछ मैं कहता हूं, उसे ध्यानपूर्वक सुनो और अपने जीवन के अंतिम ध्येय पर विचार करो. इच्छारहित होकर कल से भागवत का तीन सप्ताह तक पठन–पाठन प्रारम्भ करो. तब भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारे सब दुःख दूर कर देंगे. माया का आवरण दूर होकर तुम्हें शांति प्राप्त होगी. बाबा ने उसका अंतकाल समीप देखकर उसे यह उपचार बता दिया और साथ ही रामविजय पढ़ने की भी आज्ञा दी, जिससे यमराज अधिक प्रसन्न होते हैं. दूसरे दिन स्नानादि तथा अन्य शुद्धि के कृत्य कर उसने लेंडी बाग के एकांत स्थान में बैठकर भागवत का पाठ आरम्भ कर दिया. दूसरी बार का पठन समाप्त होने पर वह बहुत थक गया और वाड़े में आकर दो दिन ठहरा. तीसरे दिन बाबा की गोद में उसके प्राण पखेरु उड़े गये. बाबा ने दर्शनों के निमित्त एक दिन के लिये उसका शरीर संभाल कर रखने के लिये कहा. तत्पश्चात पुलिस आई और यथोचित्त जांच–पड़ताल करने के उपरांत मृत शरीर को उठाने की आज्ञा दे दी. धार्मिक कृत्यों के साथ उसकी उपयुक्त स्थान पर समाधि बना दी गई. बाबा ने इस प्रकार सन्यासी की सहायता कर उसे सदगति प्रदान की. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे

हालांकि सरकार अभी भी यह कह रही है कि किसी भी सरकारी सेवा के उपभोग के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, लेकिन एक के बाद एक कई सरकारी सेवाएं (विशेष रूप से निचले स्तर की सेवाएं) आधार कार्ड से जोड़ी जा रही हैं. उदहारण के लिए रियायती दर पर सप्लाई किये जाने वाले गैस सिलेंडर और ग्रामीण बैंकों में खाता खुलवाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाया जा रहा है. भाजपा ने कहा था कि अगर सरकारी सेवाओं में आधार कार्ड को अनिवार्य बनाया गया तो वह उस पर पाबन्दी लगा देगी. बहरहाल, आधार कार्ड के सिलसिले में जो आंकड़े इकट्ठा किये गए हैं वह पहले से ही विदेशी हाथों में चले गए हैं. मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया जाए कि आधार कार्ड बनाने की और इसके लिए आंकड़े इकट्ठा करने की ज़िम्मेदारी अमेरिकी विशेषज्ञों को क्यों दी गई? जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि अब अमेरिका के पास दुनिया के लगभग हर इन्सान की व्यक्तिगत जानकारी का एक बड़ा डेटाबेस मौजूद है. ऐसी जानकारियां जो तकनीकी और नीतिगत महत्व की हो सकती हैं, विदेशों में कैसे जाने दी जा सकती हैं? मुझे नहीं लगता कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का गहराई से आंकलन किया है.

आपका
सैयद शहाबुद्दीन
(पूर्व सांसद)

भ्रामक प्रचार पर रोक लगे

आम तौर पर दवा कंपनियां क्लीनिकल ट्रायस द्धारा पहले दवा की विशेषता का पता कर अपनी दवा को प्रमाणित करने के बाद बाजार में उतारती थीं. लेकिन कई कंपनियां भ्रामक व गलत प्रचार कर जनता को गुमराह कर पैसा बना रही हैं. वहीं कुछ लोग आयुर्वेद के नाम पर जनजीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं. ऐसे में ड्रग एण्ड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट की समीक्षा कर सख्त से सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है. जिसमें दवा का भ्रामक प्रचार करने वालों पर अर्थदण्ड के साथ जेल भेजने का भी प्रावधान हो. इस संबंध में मीडिया की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि उसी के माध्यम से दवा कंपनियां जनजीवन से खिलवाड़ करने में सफल होती हैं.

–सत्यप्रकाश(शिक्षक) लखीमपुर, उत्तरप्रदेश.

ओझल हुए सपने..

कांग्रेस को जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया है, लेकिन उसने अभी भी यह असम्मानपूर्वक राजशाही से अपनी विदाई स्वीकार नहीं की है. उसकी मानसिकता अभी भी राजशाही वाली ही है. उसी भावना से वह अपने तथाकथित ट्रम्प कार्ड युवराज राहुल गांधी को निरंतर समाचारो में रहने व छपने की बीमारी से बचना नहीं चाहती. जरा सोचो जब देश के विवादकारी घोटालों पर अगर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर विधिअनुसार कार्यवाही हो और जब राहुल गांधी का दिल्ली वासियों के सुरक्षा सम्बंधित पुलिस के नियामानुसार होने वाले सत्यापन की आवश्यकता हो तो उसपर आपत्ति करके सरकारी कार्यवाही में अवरोध पैदा करना क्या किसी राजा के बिगड़े हुए स्वरूप को नहीं दर्शाता? यह धुल उड़ाने वाली राजनीति करके कांग्रेस क्यों उपहास का पात्र बनती जा रही है. एक हारे हुए योद्धा की मनोदशा को न मानकर कांग्रेस कब तक अपनी राजशाही के ओझल हो चुके सपनो से बाहर नहीं निकलेगी?

–विनोद कुमार सर्वोदय, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश.

एक और काला कारनामा

कवर स्टोरी–एनटीपीसी के सीएमडी की करतूतें दबाए बैठा है ऊर्जा मंत्रालय, घोटालों का कॉरपोरेशन... ! (9 मार्च–15 मार्च 2015) पढ़ा. काफी तथ्यपरक कवर स्टोरी है. प्रभात रंजन दीन की स्टोरी से एनटीपीसी और ऊर्जा मंत्रालय दोनों सवालों के घेरे में आ रहे हैं. यदि एनटीपीसी की करतूतों को ऊर्जा मंत्रालय जानता था तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की. जिस प्रकार कांग्रेस के चुनाव प्रचार में एनटीसी के हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है उससे साफ पता चलता है कि इस घोटाले में एनटीपीसी के साथ ऊर्जा मंत्रालय भी इस घोटाले में शामिल था. यह बिल्कुल सही है कि जब अरूप रॉय चौधरी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था तो उनका चयन सीएमडी के लिए कैसे हुआ. यह घोटाला यूपीए सरकार का एक और कारनामा है. मोदी सरकार को चाहिए कि इस घोटाले की शुरू से जांच करें और इस घोटाले में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी से कार्रवाई करे. अगर ऐसा नहीं होता है तो मोदी सरकार भी सवाल घेरे में खड़ी होगी.

–अरुण श्रीवास्तव, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.

विश्वसनीय समाचार पत्र

चौथी दुनिया समाचार पत्र (09 मार्च–15 मार्च 2015) पढ़ा. इस अंक में प्रकाशित सभी आलेख तथ्यों पर आधारित हैं. इस अंक में प्रकाशित कवर स्टोरी यूपीए सरकार के एक और घोटाले को जनता के सामने लाई है. जब तोप मुकाबिल हो–अन्ना देश आपकी ओर देख रहा है पढ़ा. काफी विचारोत्तेजक संपदाकीय है. कमल मोरारका का आलेख सिर्फ घोषणाएं नहीं अमल भी जरूरी है, कोयला महाघोटाला चौथी दुनिया का अनुमान सच साबित हुआ समेत सभी आलेख प्रभावित करने वाले हैं. चौथी दुनिया समाचार पत्र ने ही कोयला महाघोटाला जैसे घोटाले को ऊजागर किया था. आशा है कि वह आगे भी ऐसे ही घोटलों को ऊजागर करता रहेगा. चौथी दुनिया समाचार पत्र एक विश्वसनीय समाचार पत्र है.

–राजेश सिंह, बक्सर, बिहार.

लघु कथा

सच्चा शासक

कंचन वन में शेरसिंह का राज समाप्त हो चुका था पर वहां बिना राजा के स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे जंगलराज हो. वन में अशांति, मारकाट, गंदगी, इतनी फैल गई कि वहां जानवरों का रहना मुश्किल हो गया. कुछ जानवर शेरसिंह को याद कर रहे थे कि जब तक शेरसिंह ने राजपाट संभाला हुआ था सारे वन में कितनी शांति और एकता थी. गोलू भालू बोला– कोई न कोई उपाय तो करना ही होगा–क्यों न सभी कहीं सहमति से हम अपना कोई राजा चुन लें जो शेरसिंह की तरह हमें पुनः एक जंजीर में बांधे और वन में एक बार फिर से अमन शांति के स्वर गूंज उठे. सभी गोलू भालू की बात से संतुष्ट हो गए. पर समस्या यह थी कि राजा किसे बनाया जाए? सभी जानवर स्वयं को दूसरे से बड़ा बता रहे थे. माया मोर बोली– क्यों न एक पखवाड़े तक सभी को कुछ न कुछ काम दे दिया जाए जो अपने काम को सबसे अच्छे ढंग से करेगा उसे ही यहां का राजा बना दिया जाएगा. माया की बात से सहमत हो गए और फिर सभी जानवरों को उनकी योग्यता के आधार पर काम दे दिया गया. बिम्पी लोमड़ी को मिट्टी हटाने का काम दिया गया तो भोलू बंदर को पेड़ों पर लगे जाले हटाने का, सोनी हाथी को पत्थर उठाकर एक गड्ढे में डालने का काम सौंपा गया था और मोनू खरगोश को घास की सफाई की. जब एक पखवाड़ा बीत गया तो सभी जानवर अपने–अपने कार्यों का ब्यौरा लेकर एक मैदान में एकत्रित हो गए. सभी जानवरों ने अपना काम मेहनत से पूरा किया था. सिर्फ सोनू हाथी ने अपना काम नहीं किया था. अब एक समस्या फिर खड़ी हो गई कि आखिर किसके काम को सबसे अच्छा माना जाए. सबने कहा चुनाव हो जाए. अगले दिन सुबह चुनाव रख लिया गया और एक बड़े मैदान में सभी पशु–पक्षी मत देने के लिए उपस्थित हो गए. मतदान समाप्त होने के एक घंटे बाद मतों को गिनने का काम शुरु हुआ और जब मतों की गिनती समाप्त हुई तो सोनू हाथी सबसे ज्यादा मतों से विजयी हो गया. सभी जानवर एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे. तभी पक्षीराज गरूण वहां उपस्थित हुए और उपस्थित सभी जानवरों को सम्बोधित करते हुए बोले–सोनू हाथी प्रतिदिन पत्थर लेकर गड्ढे तक जाता था किंतु जब उसने देखा कि उस गड्ढे में मेरे अंडे रखे हुए हैं तो वह पत्थरों को उसमें न डालकर पास ही जमीन पर एकत्रित करता रहा. सोनू ने अपने राजा बनने के लालच को छोड़ एक जीव को बचाना ज्यादा उपयोगी समझा. उसकी इस परोपकार की भावना को देखकर हम पक्षियों की भावना को देखकर हम पक्षियों ने तय किया कि जो अपने लालच को छोड़कर दूसरों के सुख–दुःख का ध्यान रखें वही सच्चे तौर पर शासक बनने का अधिकारी है.

शिक्षा : सच्चा शासक वही होता हैं जो परोपकार की भावना को सर्वोच्च स्थान दें.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर–11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन–201301

ग़ैर हिंदी प्रदेश में हिंदी का परचम

अनंत विजय

पिछले कुछ वर्षों के साहित्यिक परिदृश्य पर अगर हम नज़र डालते हैं, तो यह पाते हैं कि पूरे देश में लिटरेचर फेस्टिवल की संख्या में इजाफ़ा हुआ है. ऐसा नहीं है कि ये लिटरेचर फेस्टिवल सिर्फ़ अंग्रेजी या हिंदी में ही हो रहे हैं, बल्कि ये भारत की अन्य भाषाओं में भी आयोजित होने लगे हैं. लिटरेचर फेस्टिवल की लोकप्रियता इतनी बढ़ी है कि अब ये महानगरों से निकल कर शहरों में पहुंचने लगे हैं. कई बड़े अख़बार समूहों ने भी अपने नाम के साथ लिटरेचर फेस्टिवल शुरू कर दिए हैं. साहित्यिक हलचलों पर नज़र रखने वालों का मानना है कि लिटरेचर फेस्टिवल की लोकप्रियता की वजह जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सफलता है. देश के जिस भी कोने में लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित होता है, लगभग सभी आयोजनों के लिए आदर्श जयपुर लिट फेस्ट ही होता है. उसी की तर्ज पर आयोजन होते हैं यानी समानांतर सत्र चलते हैं. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सफलता के पीछे कम से कम तीन शख्सियतों का बड़ा हाथ है यानी अंग्रेजी की मशहूर लेखिका नमिता गोखले, मशहूर इतिहास लेखक विलियम डेलरिंपल और इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संजोय रॉय.

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल भी जब शुरू हुआ, तो दिग्गी पैलेस होटल के फ्रंट लॉन में श्रोताओं की संख्या बहुत कम थी. कालांतर में आयोजकों की मेहनत, नया कांस्पेट, मशहूर शख्सियतों का उसमें शिरकत करना और फिर कई साल यहां होने वाले विवाद ने जयपुर लिट फेस्ट को विश्व प्रसिद्ध बना दिया. अब तो यह

ग़ैर हिंदी प्रदेश मुंबई में आयोजित लिट ओ फेस्ट में हिंदी को लेकर कई सत्र थे. यह बात खास तौर पर रेखांकित की जानी चाहिए कि चाहे वह हिंदी कविता पाठ का सत्र हो या फिर हिंदी कितनी लोकप्रिय नामक सत्र हो, सबमें श्रोताओं की खासी उपस्थिति रही. सत्र के पहले दिन की शुरुआत राजनीतिक विषयों से हुई, तो दूसरे दिन कविता रसिकों के लिए गगन गिल से लेकर सुंदर ठाकुर और स्मिता पारिख से लेकर अशोक चक्रधर तक अपनी कविताओं के साथ मंच पर मौजूद थे.

माना जाता है कि भारत में लिटरेचर का नया साल जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजन के साथ शुरू होता है. अट्ठाइस फरवरी और एक मार्च को मुंबई के मशहूर जेजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में लिट ओ फेस्ट के नाम से दो दिनों का साहित्यिक जलसा हुआ. कई सत्र समानांतर रूप से चले, कई पुस्तकों का विमोचन हुआ. गुलजार, जावेद सिद्दीकी से लेकर आशुतोष तक की किताब वहां रिलीज की गई. मुंबई में आयोजित इस लिट ओ फेस्ट में सत्रों का कैनवस बहुत बड़ा था. कार्यक्रम का शुभारंभ राजनीति से हुआ और फिर सिनेमा, साहित्य, प्रगतिशील आंदोलन, आत्मकथा और जीवनी लेखन में समस्याएं, हिंदी की

मौजूदा स्थिति से लेकर मीडिया मंडी के बदलते नियम तक को दो दिनों में समेटा गया. गुलजार तो अब इस तरह के साहित्यिक आयोजनों में स्थायी मेहमान के तौर पर मौजूद रहते हैं, यहां भी थे. उनकी उपस्थिति लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजकों को संबल देती है. उनकी लोकप्रियता की वजह से श्रोता भी जुट जाते हैं.

मीडिया मंडी के बदलते नियम को लेकर सत्र में बेहद गर्मागर्म बहस हुई. इस बात पर सहमति थी कि सोशल मीडिया के आने की वजह से न्यूज रूम का एजेंडा बदल रहा है. लेकिन, इस बात को लेकर बेहद गहरे मतभेद थे कि सोशल मीडिया के आने से मुख्य धारा के मीडिया का अंत हो जाएगा. दरअसल, सोशल मीडिया के आगमन के बाद से ही मुख्य धारा की मीडिया का मर्सिया लिखा जाने लगा है. विशेषज्ञ इस दोष के बहुधा शिकार होते रहे हैं. जब देश में कंप्यूटर आया, तो इस बात को लेकर खूब हो-हल्ला मचा कि अब लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर के आने के बाद इस देश में किस तरह की क्रांति हुई, वह सबके सामने है. किस तरह से कंप्यूटर ने देश के नौजवानों के लिए नौकरियां बढ़ाईं, इसके लिए तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही वह इस लेख का विषय है. इसी तरह से देश में जब निजी न्यूज चैनलों का फैलाव शुरू हुआ, तो फिर कुछ विशेषज्ञ छाती कूटने लगे कि अब तो अख़बारों का बंद हो जाना तय है.

उस वक्त यह तर्क दिया गया था कि दिन भर जो ख़बरें चलती रहेंगी, उन्हें लोग अगले दिन क्यों कर पढ़ना चाहेंगे. रात को दर्शक अगर वही ख़बर देख लेगा, तो सुबह अख़बार का इंतज़ार क्यों करेगा. लेकिन, तमाम आशंकाओं के विपरीत हुआ यह कि न्यूज चैनलों के फैलाव के साथ-साथ अख़बारों की प्रसार संख्या और पाठक संख्या दोनों बढ़ीं. साल दर साल आने वाले इंडियन रीडरशिप सर्वे और नेशनल रीडरशिप सर्वे के आंकड़े इस बात की चीख-चीख कर गवाही देते हैं. तो हर नए बदलाव के साथ पुरानी व्यवस्था के अंत की घोषणा करना बेहद आसान होता है, क्योंकि वह भावुकता और अपने विचारों के पूर्वाग्रहों से जकड़ा होता है. इस बात का भी ऐलान किया गया कि आने वाले दिनों में भारत के बड़े प्रकाशन संस्थान बंद हो जाएंगे, क्योंकि जनता अब इंटरनेट पर किताबें पढ़ेगी. यहां बेहद विनम्रता पूर्वक यह बताना ज़रूरी है कि फ्रांस और जर्मनी के अलावा यूरोप और अमेरिका में किताबों की बिक्री पर ई-बुक्स के बढ़ते चलन का असर लगभग नगण्य है.

सोशल मीडिया के बढ़ते चले जाने से एक अच्छी बात यह अवश्य हुई है कि वहां जो ट्रेंड करने लगता है, उसे मुख्य धारा के मीडिया में जगह मिलने लगी है. वेबसाइट्स पर सबसे ज़्यादा, न्यूज चैनलों में उससे कम और अख़बारों में सबसे कम. सोशल मीडिया की वजह से एक और बात हुई है, जिसे रेखांकित करना आवश्यक है. वह यह कि अब पाठकों की फौरन प्रतिक्रिया मिल जाती है या यह भी फौरन पता चल जाता है कि किस टॉपिक को पाठक सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. इस सहूलियत का लाभ मीडिया संस्थान उठाने लगे हैं. दरअसल, अगर हम देखें, तो भारत में इस वक्त तक़रीबन नब्बे करोड़ मोबाइल उपभोक्ता हैं. एक अनुमान के मुताबिक, इन उपभोक्ताओं में से क़रीब तीस करोड़ के मोबाइल में इंटरनेट मौजूद है, वह टू जी या थ्री जी यानी कोई भी हो सकता है. इसका मतलब यह हुआ कि ये तीस करोड़ लोग इंटरनेट पर एक साथ मौजूद हैं. इतनी बड़ी संख्या किसी भी विशेषज्ञ को आशावान बना सकती है, लेकिन किसी के लिए आशा करना अलहदा बात है, पर उस आशा और अपेक्षा के बोझ तले दबकर किसी अन्य की मृत्यु की घोषणा कर देना पूरे परिदृश्य को न समझ पाने का नतीजा है.

ग़ैर हिंदी प्रदेश मुंबई में आयोजित लिट ओ फेस्ट में हिंदी को लेकर कई सत्र थे. यह बात खास तौर पर रेखांकित की जानी चाहिए कि चाहे वह हिंदी कविता पाठ का सत्र हो या फिर हिंदी कितनी लोकप्रिय नामक सत्र हो, सबमें श्रोताओं की खासी उपस्थिति रही. सत्र के पहले दिन की शुरुआत राजनीतिक विषयों से हुई, तो दूसरे दिन कविता रसिकों के लिए गगन गिल से लेकर सुंदर ठाकुर और स्मिता पारिख से लेकर अशोक चक्रधर तक अपनी कविताओं के साथ मंच पर मौजूद थे. कवियों में भी रेंज काफी बड़ी थी. रविवार की सुबह सभागार लगभग भरा हुआ था. हिंदी कविता को लेकर ग़ैर हिंदी प्रदेश में श्रोताओं की उपस्थिति आश्वस्ति कारक रही, क्योंकि हिंदी में तो यह माना जाने लगा है कि कविता के पाठक नहीं हैं, प्रकाशकों ने काव्य संग्रह छापने से कन्नी काटना शुरू कर दिया है. हिंदी की लोकप्रियता के सत्र में अरुण माहेश्वरी ने हिंदी और भारतीय भाषाओं को लेकर कई ज़रूरी सवाल उठाए. इस सत्र का विषय था कि क्या प्रकाशक हिंदी के लेखकों को समान अवसर देते हैं? यह सवाल वहां अवश्य उठा, लेकिन इसे लिट ओ फेस्ट से बाहर ले जाकर बड़े फलक पर देखने की आवश्यकता है. इस विषय के आलोक में अगर हम विदेशी प्रकाशकों को देखें, तो साफ़ झलकता है कि हिंदी के लेखक वहां दोयम दर्जे के माने जाते हैं और उनकी प्राथमिकता अंग्रेजी होती है. अंग्रेजी में भी वे वैसे लेखकों को तरजीह देते हैं, जिनके नाम या पद से किताबें बिक जाएं.

अंग्रेजी की पुस्तकों के बरक्श अगर हम भारत में काम कर रहे विदेशी प्रकाशकों या मूल रूप से अंग्रेजी के प्रकाशकों की बात करें, तो यह साफ़ दिखाई देता है कि वे न सिर्फ़ हिंदी, बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं को भी तरजीह नहीं देते हैं. लिट ओ फेस्ट में एक और महत्वपूर्ण सत्र रहा, जिसने साहित्य जगत को झकझोरा और फिर से बड़े सवाल खड़े कर दिए. जावेद सिद्दीकी, रक्षंदा जलील और सलीम आरिफ प्रगतिशील लेखक आंदोलन पर उठ रहे सवालों से टकराते रहे. जावेद सिद्दीकी ने तो यहां तक कह दिया कि अदब जमाने का मोहताज नहीं होता, लेकिन इस सत्र में इस बात को लेकर वक्ता कन्नी काटते रहे कि क्या वजह रही कि प्रगतिशील लेखक आंदोलन की सांसें फूल रही हैं, क्या वजह रही कि प्रगतिशील आंदोलन लगातार बिखरता चला गया? गुलजार ने बांबे के जमाने में डबल डेकर बस में लेखकों की बैठकी के किस्से सुनाए, लेकिन प्रगतिशील आंदोलन पर कोई भी गंभीर बात नहीं की. इस तरह के लिटरेचर फेस्टिवल में श्रोताओं की यह अपेक्षा रहती है कि विषय विशेष पर बड़े लेखकों की राय जानें. संस्मरणों को सुनना अच्छा लगता है, लेकिन वैचारिकी के स्तर पर उससे ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होता है. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

किताबें मिलीं

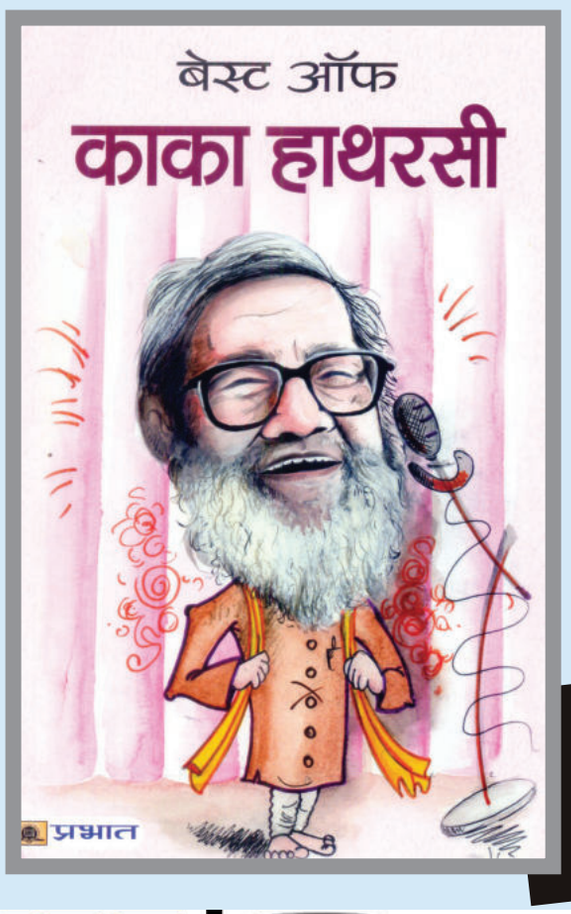

हास्य कवि काका हाथरसी को भला कौन नहीं जानता! उन्होंने न केवल हिंदी कवि सम्मेलन के मंच पर हास्य को स्थापित किया, बल्कि उसे महत्वपूर्ण स्थान भी दिलाया. काका ने अपनी तुकांत एवं अतुकांत कविताओं के साथ अपने हास्य में जीवन की व्यापक विसंगतियों को समेटा. उन्होंने नारी को गरिमा प्रदान की. नाम बड़े और दर्शन छोटे, लिंग भेद जैसी कविताएं उनकी गहरी निरीक्षण क्षमता और खोजपूर्ण दृष्टि की परिचायक हैं. प्रस्तुत संकलन में उनकी वे कविताएं हैं, जो काव्य प्रेमियों के हृदय-पटल पर राज करती आई हैं और हमें बताती हैं कि निर्मल हास्य द्धारा समाज में कैसे सुधार किया जा सकता है.

पुस्तक : बेस्ट ऑफ काका हाथरसी
रचयिता : काका हाथरसी
प्रकाशक : प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली
मूल्य : 150 रुपये

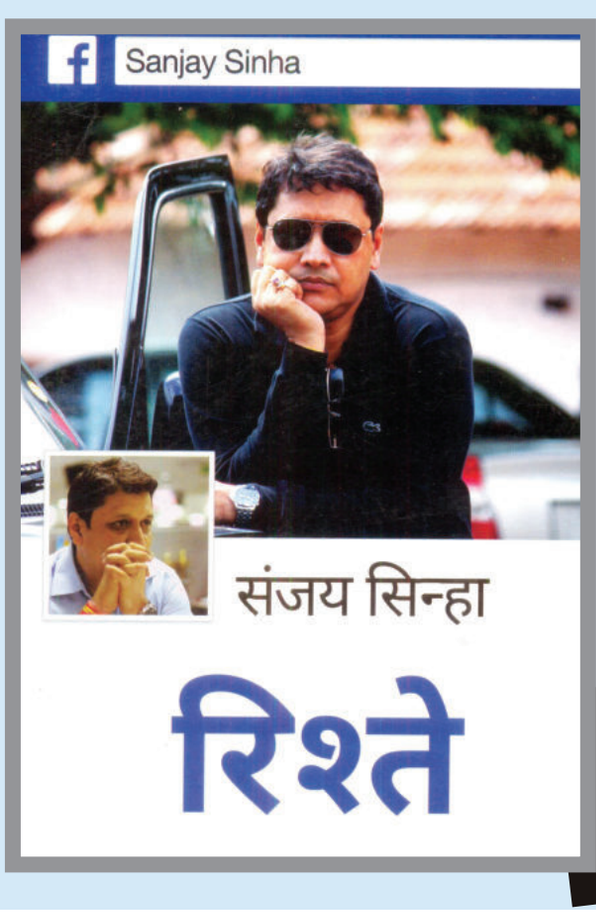

रिश्ते वरिष्ठ पत्रकार संजय सिन्हा की वह कृति है, जिसमें उन्होंने आभासी दुनिया समेत जीवन के विभिन्न रिश्तों पर अपनी कलम चलाई है. फेसबुक के माध्यम से जुड़ने वाले दोस्तों, वरिष्ठों, कनिष्ठों के रिश्ते संजय को किस हद तक प्रभावित करते हैं, किस तरह संजय उन्हें जीते हैं और वे सारे रिश्ते उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, आदि बिंदुओं पर उनके बेबाक लेखन का नतीजा मालूम पड़ती है-रिश्ते. दरअसल, हमारा जीवन ही रिश्तों पर टिका है, बिना रिश्ते हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते. उम्मीद है, रिश्ते पाठकों को लेखन के एक नए विषय, नई विधा, नई शैली से भी अवगत कराएगी.

पुस्तक : रिश्ते
लेखक : संजय सिन्हा
प्रकाशक : प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली
मूल्य : 245 रुपये

कंपनी का कहना है कि बाजार में सस्ते स्मार्टफोन के आने से सही मायने में डिजिटल इंडिया का उद्देश्य पूरा होगा. कंपनी की ओर से बताया कि भारत में हर साल 1.25 करोड़ ऐसे स्मार्टफोन की बिक्री होती है, जिसकी कीमत 3000 रुपये से कम है. कंपनी बाजार के इसी सेक्शन पर अपनी पकड़ बनाना चाहती है. डेटाविंड अब तक टैबलेट का निर्माण करती रही है, लेकिन अब वह ऑनलाइन बाजार के साथ ही रिटेल बाजार में भी स्मार्टफोन बिक्री पर जोर देना चाहती है.

ऐसे बढ़ाएं अपने लैपटॉप का बैट्री बैकअप

कभी-कभी हमें कोई जरूरी मेल करना होता है या कोई दूसरा काम. उस समय लैपटॉप की बैट्री डेड होती है और शटडाउन की वार्निंग स्क्रीन पर फ्लैश करने लगता है. असल में यह एक ऐसी समस्या है, जिससे देर-सवेर दुनिया का हर लैपटॉप यूजर दो-चार होता है. ऐसी परिस्थिति में यह मान लिया जाता है कि बैट्री बदलने या नई बैट्री के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है. अब आप इन टिप्स का का इस्तेमाल कर अपने लैपटॉप की बैट्री बैकअप बढ़ा सकते हैं.

1- लैपटॉप को बैट्री सेवर मोड या ईको मोड पर रखें. यह आपके लैपटॉप को कम पावर में बेहतर प्रदर्शन की क्षमता देता है. हालांकि, इसका स्क्रीन की ब्राइटनेस पर थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन थोड़े समझौते से बढ़िया बैकअप का फल भी मिल रहा है.

2-जब भी लैपटॉप ऑन होता है. एक साथ कई हार्डवेयर ऑन हो जाते हैं. इनमें से कई हार्डवेयर को हम हर बार इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, फिर भी उन तक बैट्री का पावर तो पहुंच ही रहा होता है. ऐसे में उन हार्डवेयर को तत्काल ऑफ या डिसेबल कर बैट्री के स्ट्रैंथ को बढ़ाया जा सकता है.

3-उदाहरण के लिए लैपटॉप में कई यूएसबी पोर्ट्स होते हैं, लेकिन हम हर पल उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं. ऐसे में इन्हें तत्काल डिसेबल किया जा सकता है. फिर इस्तेमाल होने पर बिना झंझट के इसे इनेबल कर लें.

4-हार्डवेयर को डिसेबल या तत्काल ऑफ करने के लिए डवाइस मैनेजर (Device Manager) का इस्तेमाल करें. इसके लिए माई कम्प्यूटर (My Computer) पर राइट क्लिक करें, प्रापट्रीज(Properties) पर क्लिक करें और लेफ्ट साइडबार में डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करें. अब जिस हार्डवेयर को डिसेबल करना चाहते हैं, उस पर राइट क्लिक करें और डिसेबल करें.

5-सबसे अधिक बैट्री खर्च करने वाले हार्डवेयर में DVD/CD-ROM² का नाम सबसे पहले आता है. इस्तेमाल नहीं होने के क्रम में इसे डिसेबल किया जा सकता है.

6-हर वक्त ब्लूटुथ, वाईफाई, कार्ड रीडर को भी इनेबल या ऑन रखने का कोई तुक नहीं है. आप इस्तेमाल करें न करें आपके बैट्री का कुछ हिस्सा यह हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं.

7-डिवाइस मैनेजर इस्तेमाल करते वक्त थोड़ी सावधानी इस मायने में बरतें कि किसी ऐसे हार्डवेयर को डिसेबल न करें, जिसके बाद लैपटॉप का इस्तेमाल मुश्किल हो जाए. जैसे हार्ड डिस्क के किसी ड्राइव को ही डिसेबल न कर दें.

8-जब भी लैपटॉप ऑन करें Ctrl+Shift+Esc के जरिए टास्क मैनेजर खोलकर उन एप्पस की जानकारी ले लें, जो बैकग्राउंड में रन करते हैं. आप चाहें तो Ctrl+Alt+Del दबाकर किसी ऐसे एप को बंद कर सकते हैं जो आपकी नजर में फिजूल है.

9-कई लैपटॉप में की-बोर्ड के साथ बैकलाइट की व्यवस्था होती है. जरूरत न हो तो इसे डिसेबल किया जा सकता है.

10-डिस्पले ब्राइटनेस को हमेशा 100 फीसदी पर न रखें. 50 फीसदी पर रखना एक स्टैंडर्ड हो सकता है.

11-डिस्पले को 1080p पर हमेशा रखना कोई समझदारी नहीं है. आप चाहें तो बेसिक 1366x768 के रिजॉल्यूशन पर रख सकते हैं.

12-जब कभी साउंड का इस्तेमाल न हो तो म्यूट कर दें या साउंड लेवल को जीरो पर रखें.

13-सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं, बैकग्राउंड में चलने वाले एप और लाइव टाइल भी बैट्री की खपत बढ़ाते हैं. बेहतर होगा ऐसे एप्प को डिसेबल कर दें.

14-अगर बैट्री कम चार्ज है तो एक साथ कई काम करने से बचें. इससे प्रोसेसर पर लोड कम होगा और बैट्री की खपत थोड़ी कम होगी.

जब भी लैपटॉप ऑन होता है. एक साथ कई हार्डवेयर ऑन हो जाते हैं. इनमें से कई हार्डवेयर को हम हर बार इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, फिर भी उन तक बैट्री का पावर तो पहुंच ही रहा होता है. ऐसे में उन हार्डवेयर को तत्काल ऑफ या डिसेबल कर बैट्री के स्ट्रैंथ को बढ़ाया जा सकता है.

15-लैपटॉप को समय-समय पर ट्यून अप करते रहें. यानी डिस्क क्लीनअप, डिफ्रैगमेंट आदि.

16-अगर लैपटॉप का इस्तेमाल बिस्तर पर कर रहे हैं तो नीचे पेपर या कोई स्टैंड जरूर रखें. गर्म हवा को निकलने के लिए समय दें.

17-लैपटॉप को कभी भी चार्ज में लगा हुआ न छोड़े. मसलन, काम होने के बाद चार्जिंग बंद कर दें. या फुल चार्ज होने पर चार्जिंग बंद कर दें.

18-समय-समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहें. इससे भी बैट्री बैकअप पर असर पड़ता है. ■

माइक्रोसॉफ्ट का सबसे सस्ता नोकिया 215

इस कैटिगरी में यह पहली डिवाइस है जो यूजर्स को फेसबुक को 9 स्थानीय भाषाओं में इस्तेमाल करने का ऑप्शन देगी.

माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सबसे सस्ता इन्टरनेट रेडी फोन नोकिया 215 ड्यूल सिम भारत में लॉन्च किया है. इस कैटिगरी में यह पहली डिवाइस है जो यूजर्स को फेसबुक को 9 स्थानीय भाषाओं में इस्तेमाल करने का ऑप्शन देगी. साथ ही इस फोन में फेसबुक मेसेंजर भी प्री-लोडेड आएगा. कंपनी का मानना है कि भारत मोबाइल-फर्स्ट बाजार है और इंटरनेट पर ऐक्सेस के लिए फीचर फोन्स पर बड़ी संख्या में मोबाइल यूजर्स निर्भर है. माइक्रोसॉफ्ट पहली बार मोबाइल फोन यूज करने वालों के लिए फोन्स लाने के लिए प्रतिबद्ध है जिनमें बढ़िया टेक्नॉलजी भी दी जाएगी. नोकिया 215 में नोकिया सीरीज़ 30+ ऑपरेटिंग सिस्टम और वीजीए कैमरा है. इस फोन की कीमत सिर्फ 2,149 रुपये है. ■

1890 रुपये में एप्पल जैसी वॉच

एप्पल इंक ने कुछ दिन पहले ही एप्पल वॉच लांच की थी. चीन में इसी वॉच की तरह की दिखने वाली घड़ियां बड़े पैमाने पर बिक रही हैं. चीन में यू वॉच और डी वॉच नाम की घड़ियां बिक रही हैं, जिनकी कीमत केवल करीब 1890 रुपये है. ये दिखने में भी एप्पल की घड़ियों की तरह ही है. एप्पल की सबसे सस्ती घड़ी करीब 19 हजार रुपये की है. हालांकि इन घड़ियों पर एप्पल का लोगो नहीं है, लेकिन ये देखने में अमेरिकी एप्पल घड़ियों जैसी ही लगती हैं. चीन में मिल रही इन घड़ियों पर कॉल आ सकती है और इसका उपयोग टेक्स्ट मैसेज भेजने में भी किया जा सकता है. इस पर म्यूजिक बज सकता है. हालांकि इसमें लोकप्रिय मैसेजिंग एप वीचैट नहीं है. कुछ दुकनदारों ने कहा कि ये घड़ियां केवल दिखने में ही एप्पल जैसी हैं. काम के मामले में यह घड़ियां एप्पल से बहुत पीछे है. ये घड़ियां जनवरी से ही ऑनलाइन मिल रही हैं. मॉल के कुछ विक्रेताओं ने कहा कि बेहतर आईओएस अनुकूल किस्म वाली घड़ियां अगले महीने तक आ जाएंगी, जिनकी कीमत चार हजार रुपये के आसपास होगी. ■

आकाश बनाने वाली कंपनी का सबसे सस्ता स्मार्टफोन

आकाश टैबलेट बनाने वाली कंपनी डेटाविंड ने सस्ते बजट स्मार्टफोन की नई सीरीज लॉन्च की है. कनाडा की कंपनी ने दावा किया है कि ये स्मार्टफोन भारतीय बाजार में उपलबध किसी भी स्मार्टफोन से सस्ते हैं. कंपनी के नए 2जी स्मार्टफोन की कीमत 2000 रुपये है, जबकि 3जी मॉडल की कीमत 3000 और 5500 रुपये है. डेटाविंड अब मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले स्मार्टफोन का निर्माण करने की योजना रखती है. कंपनी का कहना है कि बाजार में सस्ते स्मार्टफोन के आने से सही मायने में डिजिटल इंडिया का उद्देश्य पूरा होगा. कंपनी की ओर से बताया कि भारत में हर साल 1.25 करोड़ ऐसे स्मार्टफोन की बिक्री होती है, जिसकी कीमत 3000 रुपय से कम है. कंपनी बाजार के इसी सेक्शन पर अपनी पकड़ बनाना चाहती है. डेटाविंड अब तक टैबलेट का निर्माण करती रही है, लेकिन अब वह ऑनलाइन बाजार के साथ ही रिटेल बाजार में भी स्मार्टफोन बिक्री पर जोर देना चाहती है. ■

हुंडई की नई एलीट आई 20 कार

हुंडई मोटर इंडिया ने भारतीय बाजार में एक नई प्रीमियम हैचबैक कार एलीट आई 20 पेश की है. 1.2 पेट्रोल और 1.4 डीजल इंजन के साथ लॉन्च की गई इस कार को हुंडई ने स्पोर्टी लुक देने की कोशिश की है. इसका इंटीरियर पहले के मुकाबले अच्छा है. एलीट आई20 ब्लैक, ब्राउन और ग्रे जैसे नए रंगों में भी उपलब्ध होगी. खास बात यहां यह है कि हुंडई ने इस कार को सबसे पहले भारत में ही लॉन्च किया है. अपने सेगमेंट में इसका मुकाबला फॉक्सवैगन की पोलो से होगा जिसका हाल ही में नया मॉडल लॉन्च हुआ है. साथ ही यह 6 से आठ लाख की रेंज की गाड़ियों में इटियोस क्रॉस और फिएट जैसी कारों को टक्कर देगी. हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड सीईओ बीएस सियो ने कहा कि आई 20 एक्टिव स्पोर्ट स्टाइल की कार है जो नए चलन को स्थापित करने वाली साबित होगी. इससे कंपनी को भारतीय बाजार में अपनी मौजूदगी मजबूत करने में मदद मिलेगी. इसे ड्राइविंग इनोवेशन और आरामदायक सुविधा के लिहाज से डिजाइन किया गया है.

दिल्ली में इस कार के पेट्रोल वर्जन की एक्स शोरुम कीमत 6.38 लाख जबकि डीजल वर्जन के लिए शुरुआती कीमत 7.63 लाख रुपये रखी गई है. ■

एलीट आई20 ब्लैक, ब्राउन और ग्रे जैसे नए रंगों में भी उपलब्ध होगी. खास बात यहां यह है कि हुंडई ने इस कार को सबसे पहले भारत में ही लॉन्च किया है. अपने सेगमेंट में इसका मुकाबला फॉक्सवैगन की पोलो से होगा जिसका हाल ही में नया मॉडल लॉन्च हुआ है.

रिकॉर्ड्स का विश्वकप

ग्रुप स्टेज के 42 मैचों में कुल 35 शतक लगे, जिसमें श्रीलंका की तरफ से 8, दक्षिण अफ्रीका की तरफ से 5, भारत की तरफ से 4, वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 3-3, बांग्लादेश, इंग्लैंड, आयरलैंड और जिंबाब्वे की तरफ से 2-2, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, यूएई और स्कॉटलैंड की तरफ से 1-1 शतक लगे. साल 2011 में खेले गए विश्व कप में कुल 24 शतक लगे थे.

नवीन चौहान

भारतीय टीम की विश्व खिताब बचाने की जंग जारी है, लेकिन यह विश्वकप पिछले सभी विश्व कप से कई मायने में अलग है. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त मेजबानी में आयोजित 11वें क्रिकेट विश्व कप में जिस गति से रन बन रहे हैं, उसी गति से नए रिकॉर्ड भी बन रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तेज-तर्रार पिचों पर गेंदबाजों के दबदबे की आशंका जताई जा रही थी. वहां बल्लेबाज हर दिन एक नई इबारत लिख रहे हैं. ऐसे गेंदबाज भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं.

1975 से शुरू हुई एकदिवसीय विश्व कप प्रतियोगिता में 40 साल में खेल के स्तर में जमीन-आसमान का फर्क आ गया है. प्रतियोगिता में शतकों के मामले में एक नया इतिहास रचा गया है. ग्रुप स्टेज में ही 35 शतक लगे, जबकि 1975 के पहले विश्व कप में केवल 7 शतक बने थे. श्रीलंका के कुमार संगकारा न एक ही विश्व कप में चार और एकदिवसीय क्रिकेट में लगातार चार शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है. इससे पहले एक ही विश्व कप में सबसे ज्यादा विश्व कप बनाने का रिकॉर्ड भारत के सौरव गांगुली और ऑस्ट्रेलिया के मार्क वॉ के नाम दर्ज था. संगकारा ने विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ 105 नाबाद, इंग्लैंड के खिलाफ 117 नाबाद, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 104 और स्कॉटलैंड के खिलाफ 124 रनों की शतकीय पारी खेली. श्रीलंका के ही तिलकरत्ने दिलशान, भारत के शिखर धवन, जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर और बांग्लादेश के मोहम्मद महमदुल्लाह ने ग्रुप चरण में दो-दो शतक लगाए. ग्रुप स्टेज के 42 मैचों में कुल 35 शतक लगे, जिसमें श्रीलंका की तरफ से 8, दक्षिण अफ्रीका की तरफ से 5, भारत की तरफ से 4 , वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया की ओर से 3-3, बांग्लादेश, इंग्लैंड, आयरलैंड, जिंबाब्वे की तरफ से 2-2 और न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, यूएई और स्कॉटलैंड की तरफ से 1-1 शतक लगे. साल 2011 में खेले गए विश्व कप में कुल 24 शतक लगे थे.

इस विश्व कप में सबसे लंबी पारी वेस्टइंडीज के क्रिस गेल के नाम रही. उन्होंने विश्व कप इतिहास का पहला दोहरा शतक लगाया. यह एक दिवसीय क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक भी है. गेल ने अपनी मैराथन पारी के दौरान गैरी क्रिस्टन के रिकॉर्ड को तोड़ा. क्रिस्टन ने 1996 के विश्व कप में यूएई के खिलाफ 188 रनों की नाबाद पारी खेली थी. इस बार विश्व कप में 150 से रनों की छह पारियां खेली गईं. गेल के अलावा ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉनर ने 178, दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स ने 162, श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान ने 161, दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला ने 159 और स्कॉटलैंड के जे कोइट्ज़र ने 156 रनों की पारियां खेलीं. इन पारियों में भी कई नए रिकॉर्ड बने. दिलशान ने बिना छक्का जड़े एकदिवसीय क्रिकेट की सबसे लंबी पारी खेली, वहीं एबी डिविलियर्स ने एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 62 गेंदों में 150 रन बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया. डिविलियर्स के नाम पहले से ही एकदिवसीय क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक, शतक दर्ज है. इसके साथ ही उनके नाम बल्लेबाजी का एक और विश्व रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.

शतकों के अलावा इस विश्व कप में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारियों का भी नया रिकॉर्ड बना. जहां साल 2011 के विश्व कप में कुल 38 शतकीय साझेदारियां हुई थीं. वहीं, इस विश्व कप के ग्रुप स्टेज के पहले 38 मैचों में ही 39 शतकीय साझेदारियां हो गईं.

विश्व कप के दौरान क्रिस गेल और मार्वन सैमुअल्स की जोड़ी ने एकदिवसीय क्रिकेट में किसी भी विकेट के लिए सबसे लंबी साझेदारी का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया. दोनों ने जिबाब्वे के खिलाफ 372 रनों की साझेदारी निभाई. इससे पहले विश्व कप का यह रिकार्ड सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ के नाम दर्ज था. दोनों ने 1999 के विश्व कप कै दौरान विश्व कप में सबसे लंबी साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया था.

इस बार विश्व कप में छक्कों की जमकर बरसात हुई. विश्व कप में लीग चरण तक कुल 388 छक्के लगे. यह एक नया विश्व कप रिकॉर्ड है. छोटे मैदान और बल्लेबाजों के अनुकूल माने जाने वाले भारतीय उप महाद्वीप में खेल गए पिछले विश्व कप के दौरान 258 छक्के लगे थे. एक विश्व कप में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड 2007 के विश्व कप में बना था. उस विश्व कप में कुल 373 छक्के लगे थे. एबी डिविलियर्स 20 छक्के लगाकर विश्व कप में छक्के लगाने वालों की दौड़ में सबसे आगे हैं. यह एक विश्व कप में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा छक्के लगाने का नया विश्व रिकॉर्ड है. इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडेन के नाम दर्ज था. उन्होंने साल 2007 के विश्व कप में 18 छक्के लगाए थे. इस बार सबसे ज्यादा छक्के लगाने वालों में 18 छक्कों के साथ गेल दूसरे स्थान पर हैं. विश्व कप में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के मारने का नया रिकॉर्ड क्रिस गेल ने बनायाम उन्होंने जिंबाब्वे के खिलाफ अपनी 215 रन की पारी के दौरान 16 गगनचुंबी छक्के जड़े और एक पारी में सर्वाधिक छक्के मारने के रोहित शर्मा और एबी डिविलियर्स के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की. विश्व कप इतिहास में एबी डिविलियर्स सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं. 2007 से 2015 तक तीन विश्व कप के कुल 21 मैचों में उनके 36 छक्के हो गए हैं.

इस विश्व कप में सर्वाधिक स्कोर बनाने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया है, जिसने अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 417 रन बनाए. इससे पहले विश्व कप में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड टीम इंडिया के नाम दर्ज था. भारत ने 2007 के विश्वकप में बरमूडा के खिलाफ 413 रन बनाये थे और 157 रनों से जीत हासिल की थी. यह विश्व कप की रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत थी. विश्व कप में सर्वाधिक रनों से जीत का रिकॉर्ड भी ऑस्ट्रेलिया ने इसी मैच में अपने कर लिया. उसने अफगानिस्तान को 275 रनों के अंतर से मात दी. एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के नाम है, जिसने 2008 में आयरलैंड को 290 रनों से हराया था. इस विश्व कप में केवल दो टीमों ने 400 रनों के आंकड़े को पार किया है. मेजबान ऑस्ट्रेलिया के अलावा दक्षिण अफ्रीका ने आयरलैंड के खिलाफ 411 और वेस्टइंडीज के खिलाफ 408 रन बनाये. दक्षिण अफ्रीका ने विश्व कप में दो बार 400 रनों का स्कोर पार करके नया विश्व कप रिकॉर्ड बनाया है. एकदिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक बार 400 से अधिक स्कोर खड़ा करने के मामले में भारत, दक्षिण अफ्रीका के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर है. दोनों ही टीमें पांच-पांच बार यह कारनामा कर चुकी हैं. इसके साथ ही इस विश्व कप में सर्वाधिक बार टीमों का स्कोर 300 के पार गया. लीग स्टेज में 25 बार टीमों ने इस आंकड़े को पार किया है. आयरलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 304 रनों को चेज करते हुए 307 रन बनाने का कारनामा किया था. इसके बाद श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ 309 रनों का पीछा करते हुए 312 रन बनाये. यह लीग स्टेज में किया गया सबसे बड़ा चेज है. इस विश्व कप में गेंदबाजों ने तकरीबन 5.5 की इकॉनामी से विकेट लिये है, जो कि अब तक के सभी विश्व कप से ज्यादा है. इस बार यह अंतर अंतिम 10 ओवर के लिए लागू किए गए क्षेत्ररक्षण के नये नियमों की वजह से है. गेंदबाजों को नुकसान हुआ है, इसलिए इस नियम की आलोचना भी हो रही है.

अभी विश्व कप प्रतोगिता अपने अंजाम तक नहीं पहुंची है, इसके समापन तक कुछ और नए रिकॉर्ड बन सकते हैं और नया इतिहास रचा जा सकता है, लेकिन इस विश्व कप में बल्ले से जो कारनामे हुए हैं, उस आधार पर इस विश्व कप को हमेशा रिकॉर्ड्स के विश्वकप के रूप में याद किया जाएगा.■

navinonline2003@gmail.com

शतकों की संख्या

विश्वकप 2015 :	34
विश्वकप 2011 :	24
विश्वकप 2007 :	20
विश्वकप 2003 :	21
विश्वकप 1996 :	15
विश्वकप 1999 :	11
विश्वकप 1992 :	08
विश्वकप 1987 :	11
विश्वकप 1983 :	08
विश्वकप 1979 :	02
विश्वकप 1975 :	06

शतकीय साझेदारियों की संख्या

विश्वकप 2015 :	39
विश्वकप 2011 :	38
विश्वकप 2007 :	32
विश्वकप 1996 :	28
विश्वकप 2003 :	25
विश्वकप 1992 :	23
विश्वकप 1999 :	21
विश्वकप 1987 :	15
विश्वकप 1983 :	14
विश्वकप 1979 :	08
विश्वकप 1975 :	10

इस विश्व कप में सबसे लंबी पारी वेस्टइंडीज के क्रिस गेल के नाम रही. उन्होंने विश्व कप इतिहास का पहला दोहरा शतक लगाया. यह एक दिवसीय क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक भी है. गेल ने अपनी मैराथन पारी के दौरान गैरी क्रिस्टन के रिकॉर्ड को तोड़ा. क्रिस्टन ने 1996 के विश्व कप में यूएई के खिलाफ 188 रनों की नाबाद पारी खेली थी. इस बार विश्व कप में 150 से रनों की छह पारियां खेली गईं. गेल के अलावा ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉनर ने 178, दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स ने 162, श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान ने 161, दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला ने 159 और स्कॉटलैंड के जे कोइट्ज़र ने 156 रनों की पारियां खेलीं. इन पारियों में भी कई नये रिकॉर्ड बने.

किदाम्बी श्रीकांत ने जीता स्विस ओपन खिताब

युवा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने पुरुष एकल के कड़े फाइनल में डेनमार्क के विक्टर एलेक्सन को हराकर स्विस ओपन ग्रां प्री गोल्ड का खिताब जीत लिया. दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी श्रीकांत ने 1.2 लाख डॉलर की इनामी राशि वाली इस प्रतियोगिता के 47 मिनट तक चले फाइनल मुकाबले में दुनिया के छठवें नंबर के खिलाड़ी को तान संट तक चले मुकाबले में 21-15, 12-21, 21-14 से मात दी. चीन ओपन सुपर सीरीज प्रीमियर 2014 के फाइनल में पांच बार के विश्व विजेता और दो बार के ओलंपिक चैम्पियन चीन के लिन डैन को हराकर बहुत सुर्खियां बटोरी थीं. श्रीकांत ने पहला सेट आसानी से जीत लिया, लेकिन दूसरे सेट में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. लेकिन तीसरे सेट में उन्होंने वापसी करते हुई मैच अपने नाम कर लिया.■

विश्व हॉकी लीग : भारतीय महिला टीम चैंपियन बनी

भारतीय महिला हॉकी टीम ने दिल्ली के मेजर ध्यान चंद राष्ट्रीय स्टेडियम में एफआईएच विश्व हॉकी लीग के दूसरे दौर के फाइनल में पोलैंड को 3-1 से हरा दिया. वंदना कटारिया (15 वें मिनट) ने पहले क्वार्टर के अंतिम लम्हों में गोल दागकर भारत को बढ़त दिलाई. पोलैंड ने हालांकि दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में ही ओरियाना वालसेक के पेनाल्टी कार्नर पर गोल करके स्कोर 1-1 से बराबर कर लिया था. तीसरे क्वार्टर में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी. इसके बाद रानी ने 44 वें मिनट में मैदानी गोल दागकर भारत को 2-1 की बढ़त दिला दी. करियर का 200 वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रही कप्तान रितु रानी ने इसके बाद 59 वें मिनट में एक और गोल दागकर भारत की जीत सुनिश्चित की. भारत ने यह मैच 3-1 के अंतर से जीत लिया. वहीं क्लासीफिकेशन मैचों में मलेशिया ने थाईलैंड को 3-0 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि कजाख्स्तान को 9-0 से रौंदकर रुसी टीम पांचवें स्थान पर रही. घाना ने सिंगापुर को 2-1 के अंतर से हराकर सातवां स्थान हासिल किया.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

वायरल हुआ
एक पहेली लीला का ट्रेलर

सनी लियोनी बॉलीवुड में लगातार अपने जलवे बिखेरती जा रही हैं. उन्होंने अपनी अदाओं से लोगों को इस कदर दीवाना बनाया है कि उनकी फैन फॉलोविंग दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है. सनी की आने वाली फिल्म एक पहेली लीला का ट्रेलर लॉन्च होते ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर इस कदर वायरल हो गया है कि हर जगह सनी ही सनी नज़र आ रही हैं. बॉलीवुड में एक वक्त ऐसा भी था, जब अभिनेत्रियों के बीच आइटम सॉन्गस करके खुद को बॉलीवुड में स्थापित करने की होड़ मची थी. न जानें कितनी आईं और कितनी गईं, सनी ने सबको पीछे छोड़ बॉलीवुड में अपनी एक अगल जगह बनाई. सनी आज बॉलीवुड की हॉट और बोल्ड अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं. सनी की एंट्री बिग-बॉस-5 में दबंग सलमान खान ने कराई थी, जिन्हें सनी अपना लकी चैंप मानती हैं. सनी की आगामी फिल्म एक पहेली लीला का निर्देशन बॉबी खान कर रहे हैं, फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होते ही इसे यू-ट्यूब पर 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं. जिस हिसाब से फिल्म का ट्रेलर वायरल हुआ है उस हिसाब से यह मानने में किसी को कोई संकोच नहीं है कि सनी के प्रशंसकों की संख्या में दिनों दिन इज़ाफा हो रहा है. फिल्म के खुदा भी गाने में सनी ने बोल्डनेस की सारी हदें लांघ दी हैं. इस फिल्म में ऐश्वर्या रॉय और सलमान खान की सुपर हिट जोड़ी का सुपरहिट गाना ढोली तारो भी सनी पर हॉट अंदाज में फिल्माया गया है. फिल्म के दूसरे गीत भी धूम मचा रहे हैं, यह फिल्म पुनर्जन्म की कहानी पर आधारित है. इस फिल्म में सनी दो रोल में नज़र आयेंगी. एक रोल में वह विदेशी मॉडल की भूमिका कर रही हैं तो दूसरे में वह एक राजस्थानी लड़की का किरदार निभा रही हैं. फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज़ होगी. फिल्म में बोल्डनेस के साथ-साथ मिस्ट्री और ग्लैमर का जबरदस्त तड़का है. अब देखते हैं कि फिल्म का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता है या नहीं. ■

बॉलीवुड में एक वक्त ऐसा भी था, जब अभिनेत्रियों के बीच आइटम सॉन्गस करके खुद को बॉलीवुड में स्थापित करने की होड़ मची थी. न जानें कितनी आईं और कितनी गईं, सनी ने सबको पीछे छोड़ बॉलीवुड में अपनी एक अगल जगह बनाई. सनी आज बॉलीवुड की हॉट और बोल्ड अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं.

तनु वेड्स मनु रिटर्न्स
सही मायने में सीक्वल

साल 2011 की सफल फिल्म तनु वेड्स मनु के सीक्वल तनु वेड्स मनु रिटर्न्स की निर्मात्री कृषिका लूला का कहना है कि यह फिल्म सही मायने में पिछली फिल्म की सीक्वल है, क्योंकि यह फिल्म वहां से शुरू होती है, जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी. लूला ने कहा, मुझे हमेशा लगता है कि सीक्वल हमेशा पिछली फिल्म से जुड़ा होना चाहिए. बॉलीवुड में बहुत सी फिल्मों के सीक्वल बन रहे हैं, लेकिन या तो उनके कलाकार बदल दिए जाते हैं, या फिर कहानी पूरी तरह बदल जाती है. यहां ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए यह सही मायने में सीक्वल है. अनिल एल राय निर्देशित तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में भी कंगना रानावत और आर. माधवन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. इस फिल्म के प्रचार के लिए अनोखी योजना बनाई जा रही है. कृषिका ने कहा कि अभी इन सब के बारे में बताना जल्दबाजी होगी. यह फिल्म मई में सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी.■

'युवा' गर्ल पूनम

अभिनत्री ऋचा चड्ढा पिछले दिनों एक पार्टी में गई थीं. वहां दो युवकों ने उनके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी. बाद में सुरक्षाकर्मियों ने मामले को संभाला. बहरहाल, यह पहला मामला नहीं था जब किसी अभिनेत्री के साथ इस तरह का हादसा हुआ हो. इससे पहले भी कई फिल्म अभिनेत्रियों के साथ प्रचार के दौरान या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस तरह के हादसे होते रहे हैं. इस मामले में फिल्म 'ट्रिप टू भानगढ़' से सुर्खियों में आई अभिनेत्री पूनम पांडे का कहना है कि चाहे किसी फिल्म स्टार के साथ बदतमीजी हो या आम लड़कियों के साथ, दोनों ही मामलों में ऐसे लोग सामने आते हैं जो बाद में बलात्कार जैसी वारदातों में पकड़े जाते हैं. इसलिए ऐसे लोग आसानी से छूट गए तो समाज के लिए ठीक नहीं है. ऐसे लोग के आसानी से छूट जाने पर उनकी हिम्मत बढ़ जाती है और वे दोबारा ऐसी हरकतें करते हैं. ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. ताकि वे आगे से इस तरह की हरकतें ना कर सकें. पूनम पांडे की जल्द ही 'युवा' नाम की फिल्म रिलीज होने जा रही है, जो इसी तरह के युवाओं से जुड़े गंभीर मुद्दों पर फिल्माई गई है.■

एक साथ दिखाई देगी
बच्चन फैमिली!

महानायक अमिताभ बच्चन जल्दी ही अपनी पूरी फैमिली के साथ एक विज्ञापन में नजर आने वाले हैं. अब तक अमिताभ, अभिषेक, जया और ऐश्वर्या अलग अलग विज्ञापनों में नजर आते रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि पूरा बच्चन परिवार एक साथ एक ही विज्ञापन में दिखाई देगा. बच्चन फैमिली के सभी सदस्य सिलेब्रिटी हैं और इनमें से किसी एक को भी किसी एड में लेना निर्माताओं के लिए महंगा होता है. ऐसे में बच्चन परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ विज्ञापन के लिए साइन करना काफी महंगा सौदा होगा. अगर किसी ऐड में बच्चन परिवार एक साथ नजर आते हैं तो वह काफी खास होगा. विज्ञापन उद्योग के जानकार इसे साल की सबसे बड़ी विज्ञापन डील बता रहे हैं. खबरों के अनुसार बच्चन परिवार बच्चों के एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल के लिए ब्रैंड एंबेसडर बना है. जल्द ही इसका विज्ञापन भी दिखाई देगा. दर्शकों के लिए चारों बच्चन सदस्यों को एक साथ देखना काफी दिलचस्प अनुभव होगा. हालांकि, अभी तक इसकी किसी भी पक्ष की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.■

फिर नज़र आएगी शाहरुख़ काजोल जोड़ी

रुपहले पर्दे की सुपरहिट जोड़ियों में से एक शाहरुख और काजोल की रोमांटिक जोड़ी एक बार फिर नज़र आने वाली है. रोहित शेट्टी की आगामी फिल्म दिलवाले में दोनों लीड रोल प्ले करेंगे. उनके साथ वरुण धवन और कृति सेनन की जोड़ी भी दिखाई देगी. शाहरुख़ और काजोल ने बाज़ीगर, दिलवाले दुल्हनियां ले जायेंगे, कभी खुशी कभी गम, कुछ-कुछ होता है और माई नेम इज ख़ान जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में एक साथ काम किया है. उनकी तकरीबन सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट भी रहीं. इन फिल्मों को दर्शकों ने बहुत सराहा और लोगों के दिलों पर इन फिल्मों का जादू भी खूब चला. इन दोनों को एक साथ सिल्वज स्क्रीन पर देखने की चाहत तो दर्शकों को लंबे समय से थी. जो अब पूरी होने जा रही है. इस दौरान शाहरुख की कई फिल्में आईं, लेकिन काजोल लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं. ऐसे में दर्शकों को इस बात का भी इंतजार है कि इन दोनों के रोमांस का जादू इस बार दर्शकों पर बरकरार रह पायेगा या नहीं. क्या फिल्म दिलवाले, दिलवाले दुलहनिया ले जायेंगे की तरह लोगों का दिल जीत पायेगी. रोहित ने एक इंटरव्यू में इस फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा कि यह फिल्म पूरी तरह से मनोरंजक और रोमांटिक फिल्म है. फिल्म एक फैमिली ड्रामा है. पर कुछ लोगों का कहना है कि यह फिल्म मधुबाला और किशोर कुमार की फिल्म चलती का नाम गाड़ी की रीमेक है. खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि यह फिल्म अभिताभ बच्चन की फिल्म हम से प्रेरित है. मगर रोहित ने इन सभी खबरों को गलत बताते हुए फिल्म की कहानी को इन सबसे अलग बताया है. रोहित शेट्टी प्रोडक्शन और शाहरुख के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट इस फिल्म को संयुक्त रूप से प्रोड्यूस कर रहे हैं. यह फिल्म 25 दिसंबर 2015 को क्रिसमस पर रिलीज होगी.■

विक्की डोनर की घर वापसी

बॉलीवुड में विक्की डोनर के नाम से मशहूर आयुष्मान खुराना एक बार फिर से जॉन अब्राहम की फिल्म आगरा का डाबरा में काम करते दिखेंगे. आयुष्मान को जॉन अब्राहम ने अपनी फिल्म विक्की डोनर से लांच किया था. आयुष्मान को दोबारा जॉन की फिल्म में काम करना घर वापसी जैसा लग रहा है. इसीलिये कहा जा रहा है लौट के विक्की डोनर घर को आये. अभिनेता-गायक आयुष्मान खुराना अपनी अगली फिल्म आगरा का डाबरा में जॉन अब्राहम और निर्देशक शूजीत सरकार के साथ काम करने जा रहे हैं. विक्की डोनर से अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाले आयुष्मान अब तक नौटंकी साला, बेवकूफियां और हवाईजादा जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं. अपनी पिछली फिल्मों की असफलता के बाद आयुष्मान काफी परिपक्व हो गए हैं. वह हाल ही में फिल्म दम लगाके हईशा में नजर आए. इस फिल्म को दर्शकों ने खूब सराहा है. इसके बाद आयुष्मान ने कहा, मैंने अब फैसला किया है कि मैं आराम से सोच-समझकर सही फिल्में चुनूंगा. मैंने अपनी गलतियों से सीखा है.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

30 मार्च –05 अप्रैल 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

भाजपा के ख्वाब, हक़ीक़त से दूर

नागपुर से आई एक ख़बर ने भाजपा नेताओं के माथे पर चिंता की मोटी–मोटी रेखाएं खींच दीं. संघ की हाल में हुई नागपुर की बैठक में यह कहा गया है कि बिहार में भाजपा भले ही कुछ दावा करे पर जमीन पर पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. इसलिए समय रहते इसे सुधारने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर चुनाव परिणाम आशा के अनुकूल नहीं होंगे. जदयू और राजद का महागठबंधन अगर सही मायनों में जमीन पर उतरा तो जातीय और सामाजिक समीकरण के आधार पर भाजपा को कड़ी चुनौती मिलना तय है.

सरोज सिंह

इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा भारी जीत का ख्वाब देख रही है. भाजपा का हर छोटा–बड़ा नेता यह दावा कर रहा है कि पार्टी भारी जीत के साथ बिहार में अगली सरकार बनाने जा रही है. पार्टी कार्यालय में गहमागहमी का नज़ारा आम है और नए नेताओं का पार्टी में शामिल होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है. भाजपा अगले माह 15 अप्रैल को गांधी मैदान में प्रस्तावित कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर बेहद उत्साहित है और पूरी ताकत झोंक कर इसे सफल बनाने में लगी है. शायद उसी दिन अमित शाह बिहार में पार्टी की ओर से प्रदेश के लिए चुनाव प्रचार का शंखनाद कर देंगें. लेकिन इन सबके बीच नागपुर से आई एक ख़बर ने भाजपा नेताओं के माथे पर चिंता की मोटी–मोटी रेखाएं खींच दीं. संघ की हाल में हुई नागपुर की बैठक में यह कहा गया है कि बिहार में भाजपा भले ही कुछ भी दावा करे पर ज़मीन पर पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. इसलिए समय रहते इसे सुधारने की ज़रूरत है नहीं तो फिर चुनाव परिणाम आशा के अनुकूल नहीं होंगे. नागपुर से आई इस खबर ने भाजपा के प्रदेश नेताओं के होश उड़ा दिए. मंथन तो दिल्ली में भी शुरू हुआ पर राजधानी पटना में बैठकों का अनवरत सिलसिला शुरू हो गया. भाजपा ने अपनी कमज़ोर कड़ियों को खोजना शुरू कर दिया. पहली नज़र तो सदस्यता अभियान पर ही पड़ गई. शुरुआती जोश के बाद तो यह अभियान लगभग ठंडा ही पड़ गया था, लेकिन अब भाजपा नेतृत्व ने इस मामले में साफ कर दिया है इस मामले में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. खासकर टिकट के दावेदारों से कह दिया गया है कि अगर क्षेत्र में लक्ष्य से भटक गए तो फिर टिकट का संकट भी खड़ा हो सकता है. विचार विमर्श में यह बात सामने आई कि जीतन राम मांझी प्रकरण को भी पार्टी ने बहुत ढंग से हैंडल नहीं किया. दिल्ली से लेकर पटना तक इस मामले में तालमेल का घोर अभाव दिखा. अंतिम समय तक कोई ठोस कदम न उठा पाने के कारण पार्टी इससे होने वाले लाभ से वंचित रह गई. दरअसल भाजपा हां और ना के बीच फंसी हुई दिखी. इसलिए बाद में जीतन राम मांझी ने यह बयान भी दिया कि भाजपा ने समर्थन देने में काफी देर कर दी. अगर साथ देने का फैसला कुछ पहले कर लिया जाता तो हमारी सरकार बच जाती. दरअसल भाजपा में जीतनराम मांझी को लेकर एक राय बन ही नहीं पाई. भाजपा चुनावी जीत का दावा तो कर रही है पर अभी तक उसने अपने सहयोगी दलों को भरोसे में नहीं लिया है. लोजपा और रालोसपा के नेता बार–बार इस बात का अनुरोध कर रहे हैं कि सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द कर दिया जाए ताकि क्षेत्र में जाकर जनता को गोलबंद किया जाए. खासकर लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष कई बार सीट बंटवारे की मांग कर रहे थे. शाहनवाज हुसैन जब पारस से मिलने उनके निवास पर गए थे तो उस दरम्यान भी पारस ने इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने का आग्रह शाहनवाज से किया था लेकिन उस मुलाकात के भी दो महीने हो गए और स्थिति जस की तस है. इसका एक सीधा नुकसान यह हो रहा है कि सहयोगी दल पूरी ताकत के साथ अपनी चुनावी रणनीति को अमलीजामा नहीं पहना पा रहे हैं. चूंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि उन्हें अपनी ताकत किस इलाके में ज्यादा झोंकनी है और किस इलाके में कम. चुनाव लड़ने वाले किस नेता को अपनी पार्टी में ज्यादा तवज्जो देनी है और किसे यह साफ कह देना है कि हम आपको टिकट नहीं दे सकते क्योंकि यह सीट पार्टी के खाते में है ही नहीं. इस अनिश्चय की स्थति के कारण सहयोगी दलों की ढेर सारी ऊर्जा बेवजह खर्च हो रही है. भाजपा में जिस तरह से पिछले दिनों कई नेताओं को शामिल किया गया उसे लेकर भी पार्टी में असंतोष है. भाजपा के लिए सालों से मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं को लगता है कि नए नेताओं के आने से उनकी हकमारी तय है. इनका मानना है कि संघर्ष के दिनों में हमलोगों का पसीना सड़कों पर बहा अब मलाई खाने के लिए दूसरे दलों के नेता भाजपा में आ रहे हैं. पार्टी दिल्ली के चुनावों से भी कुछ सबक सीखने को तैयार नहीं है. पार्टी के भीतर भी किसी एक नेता को लेकर एकराय हो, ऐसी बात भी अभी नहीं है. सुशील मोदी भले अभी फ्रंट रनर दिख रहे हैं लेकिन उनकी राह में कई कांटे हैं. दिल्ली की राजनीति में शामिल शाहनवाज हुसैन और रविशंकर प्रसाद जैसे नेता बिहार की ओर टकटकी लगा कर देख रहे हैं. सार्वजनिक बयानों में भले वे इस तरह की बातों को सिरे से खारिज कर देते हैं लेकिन दिल में कोई बात नहीं हो, यह कहना गलत होगा. प्रदेश में सीपी ठाकुर, प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव जैसे नेताओं का अपना गेम प्लान है और ये नेता बिना कुछ कहे अपने मिशन में लगे हैं. विधानसभा सत्र के दौरान हर मौके पर नंदकिशोर यादव और प्रेम कुमार ने यह साबित करने की कोशिश की कि उनमें प्रदेश की सत्ता संभालने के सभी गुण कूट–कूट कर भरे हैं, बस पार्टी और जनता उन्हें एक मौका देकर तो देखे. नंदकिशोर यादव कहते हैं कि भाजपा में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता, संगठन सर्वोपरि है. हमलोग किसी रेस में नहीं हैं. हमारा लक्ष्य बिहार का विकास है और इस एजेंडे के साथ हमलोग जनता का जनादेश लेंगे. अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कौन नहीं, यह कोई मुद्दा नहीं है और वैसे भी यह मामला संसदीय बोर्ड का है. जो तय होगा उसे सभी लोग मानेंगे. प्रेम कुमार भी यही मानते हैं कि पार्टी में कहीं कोई दो राय नहीं है. अभी तो चुनाव होने हैं चुनाव के बाद केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा उसे सभी मानेंगे. कहने को तो ये नेता जो कहें पर इंतजार करना होगा कि उनकी दिल की बात कब जुबान तक आती है. भाजपा की दिक्कत यहीं खत्म नहीं हो जा रही है. भाजपा की अपनी आंतरिक परेशानियों के अलावा उनके विरोधी भी अब पहले से ज्यादा अच्छी स्थिति में आ गए हैं. नीतीश कुमार के सत्ता संभालने के बाद से जदयू में भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है. जदयू अब पहले की तुलना में ज्यादा संगठित दिख रही है और सरकार भी काम करती हुई दिखाई पड़ रही है. महागठबंधन को लेकर भी गंभीर प्रयास जारी हैं. अगर यह महागठबंधन ज़मीन पर उतरा तो जातीय और सामाजिक समीकरण के आधार पर भाजपा को कड़ी चुनौती मिलना तय है. चूंकि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की संयुक्त ताकत ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को आसानी से आगे नहीं बढ़ने देगी. सरकार में आने के बाद नीतीश कुमार और उनकी टीम का हौंसला बढ़ा है और अब हर विधानसभा क्षेत्र के लिए वहां के हालात के हिसाब से पार्टी रणनीति तय करने में लगी हुई है. ये सारी नई चुनौतियां भाजपा के सामने आने वाली है. नागपुर से आए संदेश के बाद से भाजपा सकते में है और डैमेज कंटोल की कवायद शुरू करने में लग गई है. कहा जाए तो अभी से तीन महीने पहले जो अच्छे हालात भाजपा के लिए बिहार में थे वे आज की तारीख में तो कतई नहीं हैं. बिहार की सत्ता को हासिल करने का सपना देखना और दावा करना जो पहले हकीकत के नजदीक दिख रहा था उसके आगे आज की तारीख में कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं. इसलिए अगर भाजपा को अपने ख्वाब को हक़ीक़त में बदलना है तो उसे इन चुनौतियों से जल्द से जल्द निपटना होगा वरना कहीं ऐसा न हो कि दिल के अरमां आंसूओं में बह जाएं.■

चुनाव लड़ने वाले किस नेता को अपनी पार्टी में ज्यादा तवज्जो देनी है और किसे यह साफ कह देना है कि हम आपको टिकट नहीं दे सकते क्योंकि यह सीट पार्टी के खाते में है ही नहीं. इस अनिश्चय की स्थति के कारण सहयोगी दलों की ढेर सारी ऊर्जा बेवजह खर्च हो रही है. भाजपा में जिस तरह से पिछले दिनों कई नेताओं को शामिल किया गया उसे लेकर भी पार्टी में असंतोष है.

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

मानवाधिकारों की जानकारी पहुंचाना उद्देश्य

मानवाधिकारों की जानकारी एवं इसके लाभ जन-जन तक पहुंचाना मुख्य उद्देश्य है. मानवाधिकार संगठन के झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष शाह अब्दुल कादिर इकबाल ने कहा है कि झारखंड गठन के बाद प्रदेश में कई गठबंधन की सरकारें बनीं जो पूर्ण कार्यकाल तक कम ही चल पाई. इस बीच प्रदेश में रिकार्ड घोटाले भी उजागर हुए जिनमें राजनेताओं के अलावा पदाधिकारियों की संलिप्तता पाई गई. मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है. इन 15 वर्षों के दौरान राज्य में जनता को सुविधा देने तथा विकास के नाम पर करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाए गए परन्तु धरातल पर सब शून्य दिख रहा है. दहेज को लेकर महिला उत्पीड़न के मामले रोज दर्ज हो रहे हैं, बाल शोषण की समस्या बरकरार है. मनरेगा एवं अन्य सरकारी योजनाओं में मजदूरों का शोषण जारी है. इस कारण मजदूरों का दूसरे राज्यों में पलायन हो रहा है जहां उनका कई प्रकार से शोषण हो रहा है. जेल में साधारण कैदी के भोजन एवं रहन सहन की सुविधा चिंतनीय पाई जा रही हैं. आए दिन रिमांड होम से अनियमितताओं की खबर आ रही है. *– रणजीत झा*

केसरिया महोत्सव आयोजित

तीन दिवसीय केसरिया महोत्सव का आयोजन केसरिया में किया गया. महोत्सव के प्रथम सत्र का उद्घाटन बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री व विधान पार्षद सतीश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. पीसी चन्दा के नेतृत्व में बौद्ध भिक्षुओं ने बुद्धम शरणम गच्छामी का पाठ किया. कार्यक्रम का संचालन प्रो. अरुण कुमार ने किया जबकि अध्यक्षता स्थानीय विधायक सचिन्द्र प्रसाद सिंह ने की. मौके पर डीएम जितेन्द्र श्रीवास्तव, एसपी सुनिल कुमार, प्रखण्ड प्रमुख रंजू देवी, नगर पंचायत की मुख्य पार्षद स्नेहलता सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद थे. जिला प्रशासन की ओर से आगत अतिथियों को बुके व मोमेन्टो दे कर स्वागत किया गया. केसरिया नगर पंचायत की मुख्य पार्षद स्नेहलता सिंह,विधान पार्षद सतीश कुमार, सीएस मीरा वर्मा, सर्व नारायण यादव, वरीय समाहर्ता मधुसूदन प्रसाद, प्रवीण कुमार, मनीष कुमार, युवा समाजसेवी अभय सिंह, सीता राम यादव, अशोक सिंह, वसील खां समेत कई लोग उपस्थित थे. तीनों दिन अनेक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये और कलाकारों ने श्रोताओं को खूब झुमाया.

उपेन्द्र का भव्य स्वागत

राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री उपेन्द्र कुशवाहा का पकड़ीदयाल में स्थित प्रदेश उपाध्यक्ष श्री भगवान साह के आवास पर जम कर स्वागत हुआ.वे जैसे ही वहां पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से लाद दिया. उन्होंने किसानों की बदहाली के लिए नीतीश सरकार जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सरकार की कथनी व करनी में काफी अन्तर है. उन्होंने बिहार सरकार की शिक्षा नीति पर भी सवाल उठाया और कहा कि यह कैसी नीति है कि एक ही विद्यालय में एक शिक्षक को छियालिस हजार तो दूसरे शिक्षक को नौ-दस हजार वेतन दिये जाते हैं. मौके पर सीतामढ़ी के सांसद रामपुकार शर्मा, प्रधान महासचिव शम्भू कुशवाहा, संगठन सचिव प्रदीप कुमार, राजेश्वर सिंह, सीता राम साह, राज किशोर प्रसाद, अशर्फी साह सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे.

मोतीझील में लगे शहरवासी

शासन-प्रशासन की उदासीनता और निष्क्रियता को देखते हुए मोतीझील बचाव अभियान समिति के तत्वावधान में नगरवासी सड़क पर उतर गये और श्रमदान कर इसकी सफाई की. सुबह आठ बजे से गायत्री मंदिर छठ घाट के नजदीक झील की सफाई शहरवासियों ने काफी उत्साह के साथ की और इस बदहाल मोतीझील के बचाव के लिए हर सम्भव सहयोग करने का संकल्प लिया.जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष अंसारूल हक ने कहा कि पन्द्रह मार्च को श्रम दान कार्यक्रम के तहत गायत्री मंदिर छठ घाट के नजदीक मौजूद सभी जल कुम्भियों को बाहर निकाल दिया गया. मौके पर समिति के अध्यक्ष अंसारूल हक, डॉ. अतुल कुमार, डॉ. डी नाथ, डॉ. आशुतोष शरण, डॉ. दीपक कुमार, दीपक कश्यप, रोटरी क्लब, रोटरी लेक टाइन, चम्पारण छात्र संघ, खेल संघ, युवा संगठन, निमा, निमा टू, रेड क्रॉस सोसाइटी, बलुआ व्यवसायी संघ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कलवार जागृति मंच, प्राइवेट एसोसिएशन, लायंस क्लब, स्पोर्टस क्लब सहित कई अन्य सामाजिक संगठन के लोग भी शामिल हुए तथा शहर के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया. *– इंतेज़ारुल हक़*

पुस्तक मेला का आयोजन

सीतामढ़ी शहर के राजेंद्र भवन में आयोजित पुस्तक मेला आकर्षण का केंद्र बना है. 20 से 29 मार्च तक आयोजित मेला को लेकर मेला की संयोजिका सह लेखिका आशा प्रभात ने वृहद चर्चा की. कोट बाजार स्थित अपने आवास पर उन्होंने कहा कि पुस्तक मेला में देश के ख्याति प्राप्त राजकमल प्रकाशन, लोक भारती प्रकाशन, राधाकृष्ण प्रकाशन, संवाद, विप्लव समेत कई प्रकाशकों की पुस्तकें साहित्य साधकों की पसंद साबित होगी. कहा कि मेला अवधि में पुस्तकों की खरीदारी करने वालों को आकर्षक छूट की भी व्यवस्था की गयी है.■

– विम्मी कुमारी

मोतिहारी

दुधारू गाय बनी छात्रवृत्ति व साइकिल योजना

शिक्षा विभाग के अधिकारियों व विद्यालयों के प्राचार्यों के लिए दुधारू गाय बनी हुई हैं और इन योजनाओं की आड़ में लाखों का चूना लगाया जाता है. हद तो तब हो जाती है कि विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं द्वारा जब इसके लिए हंगामा किया जाता है और विभाग के आलाधिकारियों को इसकी सूचना दी जाती है तो दोषी प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई तक नहीं होती. मामला जिलाधिकारी के जनता दरबार में भी पहुंचता है. लेकिन जांच के लिए फिर इसे वहीं भेज दिया जाता है, जिस पर आरोप लगा होता है.

इन्तेजारुल हक

बिहार की सरकार भले ही विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने का दावा करती है और नामांकित छात्र-छात्राओं की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री बालक व बालिका साइकिल योजना चला रही है, लेकिन इन योजनाओं के क्रियान्वयन में किस तरह से मनमानी की जाती है और विभागीय आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए सरकार को चूना लगाया जाता है, इसकी खबर सरकार कभी नहीं लेती. इस कारण ये योजनाएं शिक्षा विभाग के अधिकारियों व विद्यालयों के प्राचार्यों के लिए दुधारू गाय बनी हुई हैं और इन योजनाओं की आड़ में लाखों का चूना लगाया जाता है. हद तो तब हो जाती है कि विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं द्वारा जब इसके लिए हंगामा किया जाता है और विभाग के आलाधिकारियों को इसकी सूचना दी जाती है तो दोषी प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई तक नहीं होती. मामला जिलाधिकारी के जनता दरबार में भी पहुंचता है, लेकिन जांच के लिए फिर इसे वहीं भेज दिया जाता है, जिस पर आरोप लगा होता है. पूर्वी चम्पारण के बंजरिया, घोड़ासहन, कोटवा, मोतिहारी नगर,ढाका, रामगढ़वा, छौड़ादानो आदि प्रखंडों में संचालित विद्यालयों में लगातार छात्रवृत्ति व साइकिल की राशि के लिए हो रहा हंगामा इसका ज्वलन्त उदाहरण है.

इसके अलावा मोतिहारी शहर के राजकीय मध्य विधालय तेलिया पट्टी की घटना किसी से छुपी नहीं है. जिस तरह से विद्यालय की छात्रा अजंली कुमारी, अरुण कुमार, सुभाष कुमार, सैफी आदि ने स्कूल शिक्षक जीतेन्द्र कुमार एवं सूरज कुमार पर मनमानी करने व उपस्थिति पंजी पर गड़बड़ी करने और छात्रवृत्ति की राशि हड़पने का आरोप लगाया और अभिभावकों ने विद्यालय प्रशासन की इस कार्यशैली के खिलाफ हंगामा किया, वह घटना वास्तविक स्थिति की पोल खोलने के लिए काफी है. जानकार बताते हैं कि विद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा जिस तरह से छात्रवृत्ति की राशि में फर्जीवाड़ा की गई है और लाखों का चूना लगाया गया है, इसकी गहनता से जांच की जाये तो अनेक चौंकाने वाले मामले सामने आयेगें. जानकार यह भी बताते हैं कि बंजरिया प्रखंड में संचालित कई ऐसे भी विद्यालय हैं, जहां कभी भी छात्रवृत्ति की राशि नही बंटती और उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेज दिया जाता है. यहां बतातें चलें कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में सामान्य कोटी के 67 हजार पांच सौ आठ छात्राओं के लिए 7 करोड़ 92 लाख 40 हजार आठ सौ रुपये मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना की राशि मिली थी. कमोबेश यही स्थिति मुख्यमंत्री बालक व बालिका साइकिल योजना की है. जानकार बताते हैं कि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी पावती बील खुलेआम दुकानों से ली जाती है और इस योजना की राशि का बंदरबांट किया जाता है. [illegible] इतना ही नहीं, विभागीय निर्देशों के अनुसार, पूरे वर्ष में 75 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज कराने वाले छात्र-छात्राओं को इस योजना का लाभ पहुंचाना है, जबकि ऐसा नहीं होता है और नामांकन के तीन या चार माह बाद ही 75 प्रतिशत निकालकर कार्रवाई पूरी कर ली जाती है. यहां बताते चलें कि 9वीं कक्षा में अध्ययनरत 63 हजार 8 सौ 99 छात्र-छात्राओं के लिए 15 करोड़ 97 लाख 72 हजार 5 सौ रुपये उच्च विद्यालयों को उपलब्ध कराया गया था. इनमें अन्य कोटि के 28 हजार 3 सौ 38 छात्रों के लिए 7 करोड़ 8 लाख 45 हजार, एससी/एसटी कोटि के 3 हजार 198 छात्रों के लिए 79 लाख 95 हजार, अन्य कोटि की 29 हजार 32 छात्राओं के लिए 7 करोड़ 25 लाख 80 हजार तथा एससी/एसटी कोटि की 3 हजार 341 छात्राओं के लिए 83 लाख 52 हजार 500 रुपये का आवंटन हुआ था, जिसका वितरण किया गया है. कुल मिलाकर ये योजनाएं विभागीय अधिकारियों व विद्यालयों के प्राचार्यों के लिए दुधारू गाय साबित हो रही है और इसकी जांच अगर निष्पक्ष ऐजेंसी से करायी जाये तो अनेक गड़बड़ घोटाले सामने तो आयेंगे ही, साथ ही कई चौंकाने वाला तथ्य भी सामने आयेगा. इस बीच जिला शिक्षा पदाधिकारी रामनन्दन प्रसाद से इनके मोबाइल पर सम्पर्क साधा गया, लेकिन इनसे बात नहीं हो सकी. इनके कार्यालय में भी पहुंचकर मामले की विस्तार से जानकारी लेने की कोशिश की गयी, लेकिन वे वहां भी नहीं मिल सके. नाम नहीं छापने की शर्त पर एक कर्मचारी ने बताया कि साहेब का कार्यालय आवास पर ही चलता है और जो भी लेन-देन की बातें होती हैं, वहीं हो जाती हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

हॉस्टल लाइफ खुशी भी, गम भी

राधिका

हॉस्टल के कई मतलब होते हैं. आज़ादी, रैगिंग, घरवालों की यादें, रूमानियत, अनुशासन और कुछ बंदिशें. इसमें यह बात भी मायने रखती है कि हॉस्टल लड़कों का है या फिर लड़कियों का. अगर बात लड़कियों की हो तो स्थितियां थोड़ी उलट होती हैं. लड़कियों के हॉस्टल में अनुशासन की लक्ष्मण रेखा लड़कों जैसी नहीं होती और उनकी ज़रूरतें भी अलग होती हैं. सुरक्षा के नाम पर लड़कियों को उन बंदिशों का सामना करना पड़ता है जो कई बार तो काल्पनिक लगती हैं. लड़कियां घर से दूर हॉस्टल में आ कर रहती हैं. हां, हॉस्टल में घर जैसा माहैल मिलना तो थोड़ा मुश्किल है पर फिर भी अगर हॉस्टल का माहौल और वॉर्डन ठीक हों तो थोड़ी सहूलियत तो ज़रूर मिल सकती है. घर से दूर रहना ही बहुत कठिन होता है. ऐसे में अगर आस-पास के लोग अच्छे न हों तो बात काफी बिगड़ जाती है. कुछ लड़कियां ऐसे हालात से जूझने में सफल हो जाती हैं तो कुछ में इतनी हिम्मत नहीं होती है और इन हालात को जो लड़कियां हैंडल नहीं कर पातीं, उनके लिए घर से दूर रहना और भी मुश्किल हो जाता है.

अगर पटना की बात की जाए तो यहां पर राज्य के कोने-कोने से लड़कियां अपना भविष्य बनाने आती हैं. कुछ नौकरी करने आती हैं. कुछ पढ़ाई करने, कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने आदि. हर लड़की का अपना सपना होता है. शहर में प्रवेश करते ही किसी भी लड़की की सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि उसे रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए. ऐसे में ज्यादातर लड़कियां हॉस्टल में ही रहती हैं. कुछ हॉस्टल्स सरकारी होते हैं कुछ गैर सरकारी. कई तो बिना रजिस्ट्रेशन के ही चल रहे हैं. पटना के बोरिंग रोड, नागेश्वर कॉलोनी आदि कई जगहों पर गर्ल्स हॉस्टल्स हैं. पर घर और हॉस्टल में तो अंतर होता ही है. इसी विषय में हमने हॉस्टल में रहने वाली कुछ लड़कियों और हॉस्टल वॉर्डन से बात की तो कई दिलचस्प बातें उभर कर सामने आईं.

नागेश्वर कॉलोनी स्थित एक निजी हॉस्टल में रह रहीं छात्रा पंखुड़ी प्रिया ने बताया की हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था तो ठीक है लेकिन जहां तक खाने की बात है तो मैं खाने से उतनी संतुष्ट नहीं हूं. हां, मैं मानती हूं कि हॉस्टल में घर जैसा खाना नहीं मिल सकता है लेकिन फिर भी जिस लेवल का खाना होना चाहिए, वैसा नहीं होता. इसके साथ हीं मेस में इतनी भीड़ होती है कि कभी-कभी तो खाना लेने तक का मन नहीं करता है. बाकी सारी फैसिलिटीज तो ठीक हैं बस मेरे लिए खाने की समस्या परेशानी का सबब है.

नागेश्वर कॉलोनी स्थित एक निजी हॉस्टल में रह रहीं छात्रा पंखुड़ी प्रिया ने बताया की हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था तो ठीक है लेकिन जहां तक खाने की बात है तो मैं खाने से उतनी संतुष्ट नहीं हूं. हां, मैं मानती हूं कि हॉस्टल में घर जैसा खाना नहीं मिल सकता है लेकिन फिर भी जिस लेवल का खाना होना चाहिए, वैसा नहीं होता. इसके साथ हीं मेस में इतनी भीड़ होती है कि कभी-कभी तो खाना लेने तक का मन नहीं करता है. बाकी सारी फैसिलिटीज तो ठीक हैं बस मेरे लिए खाने की समस्या परेशानी का सबब है.

घर के सुरक्षित माहौल से लड़कियां जब बाहर निकलती हैं तो उन्हें बस इस बात का डर लगा रहता है कि वो जहां भी रहें वहां के लोग अच्छे हों और साथ ही वो सुरक्षित भी रहें. इसी सिलसिले में पटना विमेंस कॉलेज की छात्रा सिप्पी, जो नागेश्व कॉलोनी में ही एक हॉस्टल में रहती हैं, ने बताया कि उनके पिछले हॉस्टल का, जो एसके पुरी में स्थित है, माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं था. हॉस्टल में मेल वॉर्डन थे. उनकी लैंग्वेज बहुत ही रफ थी. इसके अलावा भी कई वजहों से वह हॉस्टल ठीक नहीं था. मैंने वह हॉस्टल छोड़ दिया और यहां शिफ्ट हो गई. वहां न तो खाना अच्छा था और न ही सिक्योरिटी. हॉस्टल वॉर्डन के रवैये से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि वहां की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी?

इसी क्रम में हमें सीमेज की छात्रा रूही ने बताया कि उनका हॉस्टल बाकी सारे हॉस्टल्स से अच्छा है. वॉर्डन भी बहुत फ्रैंक हैं. इसके अलावा फैसिलिटीज भी अच्छी हैं. लेकिन खाने का बस एक ही फिक्स्ड टाइम है. उसके अलावा फिर खाना नहीं मिलता. भूख हो न हो उसी टाइम पर खाना खाना पड़ता है. इसके अवाला रूम काफी छोटे हैं. आने-जाने का भी टाइम फिक्स है अगर आप उससे देर में पहुंचते हैं तो हॉस्टल के अंदर पहुंचने में बहुत दिक्क्त होती है.

इसी सिलसिले में हमने नागेश्वर कॉलोनी स्थित वेदांता गर्ल्स हॉस्टल की वॉर्डन मधु से भी बातचीत की. उन्होंने बताया कि लड़कियों को संभालना आसान काम नहीं होता. एक जिम्मेदारी होती है, जिसे हमें पूरी निष्ठा से निभानी होता है. उन्होंने आगे बताया कि लड़कियां कब सच बोलती हैं और कब झूठ इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है. मधु आगे बताती हैं कि अभी हाल फिलहाल में एक लड़की यह कर कर गई कि वो हॉस्टल छोड़ कर अपने घर जा रही है लेकिन बाद में पता चला कि उस लड़की ने झूठ बोला था और उसने अपनी मर्जी से भागकर शादी कर ली थी. इसी वजह से हमें हॉस्टल में थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ती है. इसके अवाला मधु कहती हैं कि हमारे हॉस्टल में लड़कों का आना-जाना मना नहीं हैं. इस बात पर जब उनसे पूछा गया कि लड़कों के आने से लड़कियों को दिक्कत नहीं होती तो उन्होंने बताया कि लड़कों के लिए नीचे एक कॉमन रूम बना हुआ है. अगर कोई परिजन आता है तो उसी कमरे में बैठता है.

अब इन सारी बातों से तो यहीं पता चलता है कि अगर माहौल सुरक्षित हो तो लड़कियां अपने आप को सेफ महसूस करती हैं. अपने घर से दूर रहना, घर के सेफ माहौल से दूर रहना, घर पर मिल रहे प्यार और दुलार से दूर रहना बहुत हीं मुश्किल होता है. और ऐसे में अगर लड़कियों की रहने की जगह सही ना हो तो दिक्कतें और भी बढ़ जाती हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

सीतामढ़ी

क्यों नहीं मिल रहा हथियार का लाइसेंस

सीतामढ़ी जिला आपराधिक घटनाओं को लेकर चर्चा का केंद्र रहा है. रंगदारी व हत्या के दौर ने जिले में दहशत का माहौल कायम कर रखा है. दवा व्यवसायी यतींद्र हत्याकांड के बाद मचे बवाल ने तत्कालीन एसपी नवल किशोर सिंह का जिला से विदाई करा दी है. अब नये पुलिस कप्तान हरि प्रसाथ एस ने कमान संभालने के साथ ही अपराधियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है. कुल मिला कर जिले में दहशत का ऐसा आलम रहा है कि पंचायत प्रतिनिधि व व्यवसायी के अलावा हर कोई सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक दरबार में गुहार लगाते रहे है. सीतामढ़ी जिला प्रशासन पिछले तकरीबन एक दशक से इक्का-दुक्का को छोड़ हथियार का लाइसेंस देने से परहेज कर रही है. सैकडों आवेदन संबंधित कार्यालय में धूल फांक रहे है तो दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के दौरान जब्त लाइसेंसी हथियार धारक अपने हथियार वापसी में हो रहे विलंब को लेकर हलकान हैं. सरकारी फरमान के बाद भी लोगों को हथियार का लाइसेंस देने में बरती जा रही शिथिलता का आखिर कारण क्या है?

आरती प्रधान | गोपाल झा | हरिओम शरण नारायण | महेंद्र सिंह यादव | शशि शेखर | एसपी हरि प्रसाथ एस | विश्वजीत पाठक

वाल्मीकि कुमार

अमन व शांति की जमीन रही मां जानकी की पावन जन्मस्थली सीतामढ़ी अशांति व दहशत को लेकर चर्चाओं का केंद्र बना है. एक ओर अपराधी अपनी दबंगता का परचम लहरा रहे हैं तो दूसरी ओर आपराधिक घटनाओं के बाद जिला प्रशासन जनता व अपराधी दोनों का सामना करने को विवश है. इस बीच जिले के अलग-अलग स्थानों पर पंचायत प्रतिनिधियों से लेकर व्यवसायी तक अपराधियों के लगातार धमकी से हलकान हैं. बेखौफ अपराधियों के तांडव का आलम है कि प्रशासनिक सक्रियता के बाद भी रंगदारी की मांग व हत्या की धमकी का दौर थम नहीं रहा है. सरकारी स्तर पर सीतामढ़ी के तत्कालीन एसपी नवल किशोर सिंह को हटा कर हरि प्रसाथ एस को जिला का कमान सौंपा गया, परंतु अगले ही दिन स्थानीय अखबारों में रंगदारी की मांग की प्रकाशित खबर ने आम लोगों की नींद उड़ा दी. खबर थी कि अपराधियों ने नगर थाना के लक्ष्मणा नगर निवासी कबाड़ी व्यवसायी ललन प्रसाद साह, रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के बुलंदपुर निवासी कामेश्वर प्रसाद यादव व चक हुसैन निवासी नवल किशोर कुंवर से बतौर रंगदारी पांच-पांच लाख रुपये की मांग की है. साथ ही रंगदारी की राशि नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी गयी है. नव पदस्थापित एसपी हरि प्रसाथ एस ने कार्यभार संभालने के साथ ही कहा कि जिले में अपराध नियंत्रण पहली प्राथमिकता होगी. अपराधियों के खिलाफ रणनीति से पूर्व मामलों के अध्ययन के बाद ठोस कदम उठाया जायेगा. एसपी के इस घोषणा के बाद जिले के लोगों में विश्वास बढ़ा. एसपी ने कुशल रणनीति के तहत अब तक दर्जनों अपराधियों को सलाखों में डाल दिया है, जिसके कारण फिलहाल आम लोग खुले दिल से जिला पुलिस प्रशासन के कार्य की सराहना कर रहे हैं, परंतु पुलिस कप्तान अपराध पर पूर्ण लगाम लगाने में कितना सफल होते हैं, यह आने वाला वक्त ही बतायेगा. फिलहाल, सभी की नजर एसपी की सक्रियता पर है.

दूसरा पहलू यह है कि दहशतजदा लोगों को सुरक्षा किस स्तर पर मुहैया हो पायेगी? क्या सालों से लंबित शस्त्र अनुज्ञप्ति के आवेदकों को राहत मिलेगी? प्रशासनिक स्तर पर मुहैया सुरक्षा भरोसा के लायक है? जब किसी व्यवसायी, पंचायत प्रतिनिधि, चिकित्सक अथवा आम जनता को कोई अपराधी धमकी देता है तो सबसे पहले वह प्रशासनिक दरबार में फरियाद लेकर पहुंचता है. प्रशासनिक स्तर पर जांच प्रक्रिया का दौर शुरू होता है. आवेदन पर विचार के बाद सुरक्षा के सवाल पर प्रशासन समुचित निर्णय लेती है. अब तक जिले में प्रशासनिक सुरक्षा पर नजर डालें तो नजारा कुछ और ही सामने आता है. साल 2012 के मार्च महीना में जिले के मझौलिया गांव निवासी संघर्ष यात्रा के संयोजक शशि शेखर के आवास पर अपराधियों ने फायरिंग कर दहशत फैलाया था. तब प्रशासनिक स्तर पर एक अंगरक्षक समेत पांच सैप की प्रतिनियुक्ति इनके आवास पर कर दी गयी. बाद में कतिपय कारणों से सैप को हटा कर गृह रक्षकों की तैनाती कर दी गयी, जो अब तक तैनात है. इससे पूर्व जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सह चर्चित दवा व्यवसायी यतींद्र खेतान को साल 2008 में मिली धमकी के बाद एक अंगरक्षक मुहैया कराया गया, परंतु 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान इसे वापस ले लिया गया. चुनाव के तकरीबन आठ माह बाद भी इन्हें अंगरक्षक वापस नहीं किया गया. इसका लाभ उठा कर अपराधियों ने 31 दिसंबर, 2014 की रात दुकान से घर जाने के क्रम में गोली मार कर इनकी हत्या कर दी.

अब एक नजर आत्म रक्षा को लेकर हथियार का अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वालों पर डालना आवश्यक है. संघर्षयात्रा के संयोजक शशि शेखर ने वर्ष 2012 में एक राइफल व एक रिवाल्वर के अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन दिया, परंतु अब तक प्रशासनिक स्तर पर इनके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया गया है. दूसरा, जिले के डुमरा थाना क्षेत्र के बेली निवासी पंचायत समिति सदस्य हरिओम शरण नारायण उर्फ संतोष कुमार ने साल 2005 में आत्म रक्षार्थ एक दोनाली बंदूक का अनुज्ञप्ति को लेकर आवेदन किया था, लेकिन अब तक इनके आवेदन को भी यथावत रखा गया है. तीसरा मामला संवेदक सह भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य विश्वजीत पाठक का है. इन्होंने साल 2012 में ही एक राइफल की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया था, परंतु अब तक कोई विचार नहीं किया जा सका है. चौथा सोनबरसा मुखिया संजय कुमार का है. इनकी पत्नी सह जदयू नेत्री आरती प्रधान की मानें तो कई साल पूर्व मुखिया संजय ने अपने एवं पत्नी के नाम पर अलग-अलग आवेदन देकर एक राइफल व एक रिवाल्वर का लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, परंतु इनके आवेदन का भी अन्य की भांति हश्र हुआ. नतीजतन पिछले 13 जनवरी की सुबह घात लगाये कुछ हमलावरों ने मुखिया संजय को सोनबरसा में ही गोलियों से छलनी कर दिया. यह तो महज एक संयोग ही था कि समुचित चिकित्सा के बूते इनकी जान बच पायी है, जबकि जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष गोपाल झा तकरीबन पांच साल पूर्व अपने पिता बैजूकांत झा के नाम से जारी बंदूक का लाइसेंस अपने नाम स्थानांतरित करने को लेकर आवेदन दिया था, परंतु प्रशासनिक स्तर पर कोई विचार नहीं हुआ. तब फिर से करीब ढाई माह पूर्व आवेदन देकर लाइसेंस स्थानांतरित करने की गुहार लगायी है. बताते चलें कि अपराधियों ने गोपाल झा के मोबाइल पर मैसेज भेज कर सोनबरसा मुखिया संजय की तरह ही अंजाम की धमकी दी थी. उधर, जिला परिषद सदस्य सरिता यादव का पति महेंद्र सिंह यादव ने प्रशासनिक मनमानी पर रोष व्यक्त किया है. उनका कहना है कि वर्ष 2004 में सरिता यादव के नाम से एक राइफल की अनुज्ञप्ति दिया गया. 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान राइफल को जमा करा लिया गया, परंतु चुनाव के तकरीबन 9 माह बाद भी राइफल वापस नहीं किया गया है. जिले में प्रतिनिधियों पर जानलेवा हमला का दौर जारी है.

प्रशासनिक स्तर पर जांच प्रक्रिया का दौर शुरू होता है. आवेदन पर विचार के बाद सुरक्षा के सवाल पर प्रशासन समुचित निर्णय लेती है. अब तक जिले में प्रशासनिक सुरक्षा पर नजर डालें तो नजारा कुछ और ही सामने आता है. साल 2012 के मार्च महीना में जिले के मझौलिया गांव निवासी संघर्ष यात्रा के संयोजक शशि शेखर के आवास पर अपराधियों ने फायरिंग कर दहशत फैलाया था. तब प्रशासनिक स्तर पर एक अंगरक्षक समेत पांच सैप की प्रतिनियुक्ति इनके आवास पर कर दी गयी. बाद में कतिपय कारणों से सैप को हटा कर गृह रक्षकों की तैनाती कर दी गयी, जो अब तक तैनात है. इससे पूर्व जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सह चर्चित दवा व्यवसायी यतींद्र खेतान को साल 2008 में मिली धमकी के बाद एक अंगरक्षक मुहैया कराया गया, परंतु 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान इसे वापस ले लिया गया. चुनाव के तकरीबन आठ माह बाद भी इन्हें अंगरक्षक वापस नहीं किया गया. इसका लाभ उठा कर अपराधियों ने 31 दिसंबर, 2014 की रात दुकान से घर जाने के क्रम में गोली मार कर इनकी हत्या कर दी.

सरिता यादव ने मामले को लेकर जिला मुख्यालय स्थित अंबेदकर स्थल पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की थी, तब प्रशासनिक स्तर पर भरोसा के बाद कार्यक्रम को स्थगित किया गया था. उनका आरोप है कि जिला प्रशासन जाति-पार्टी के आधार पर आम लोगों को परेशान करने पर तूली है. इनके अलावा राजोपट्टी निवासी व्यवसायी आशीष सौरभ व सिनेमा रोड निवासी भरत प्रसाद भी है. उक्त दोनों ने साल 2012 में राइफल व रिवॉल्वर का लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था. लेकिन अब तक उनकी कोई सुनने वाला तक नहीं हुआ है. यह तो महज एक उदाहरण है. वैसे इस प्रकार के आवेदकों की संख्या सैकड़ों में होने की चर्चा है. बताया जाता है कि कागजी प्रक्रिया पूरा होने के बाद भी लाइसेंस निर्गत नहीं किया जा रहा है.

पिछले 5 दिसंबर, 2014 को पटना से प्रकाशित एक स्थानीय समाचार पत्र में 75 दिनों में दे हथियार का लाइसेंस, नहीं तो कार्रवाई शीर्षक से प्रकाशित खबर इन दिनों जिले में चर्चा का विषय बना है. लोगों का कहना है कि प्रशासनिक मनमानी का आलम है कि सरकारी फरमान भी फाइलों में बंध कर रह जा रही है. बताया जाता है कि प्रकाशित खबर में इस बात का उल्लेख किया गया है कि गृह विभाग ने राज्य के सभी डीएम व एसपी को हथियारों के लाइसेंस के आवेदनों पर 75 दिनों की निर्धारित अवधि में सभी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है. वरना इनके खिलाफ कार्रवाई होगी. खबर में प्रधान सचिव आमिर सुबहानी के हवाले से बताया गया है कि डीएम को आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर एसपी की जांच रिपोर्ट मिल जानी चाहिए. साथ ही लाइसेंस प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया 75 दिनों के अंदर पूरी कर ली जाये. ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ गृह मंत्रालय ने कार्रवाई का भी प्रावधान किया है. अब सवाल यह उठता है कि जिला पदाधिकारी गृह मंत्रालय के निर्देशों की अवहेलना कर अब तक लाइसेंस मामले में शिथिल कैसे है? चर्चा यह भी जोर पकड़ रही है कि परेशान लोग अब बड़े दरबार में भी लाइसेंस मामले को लेकर दस्तक देने का मन बनाने लगे हैं.

उधर जिले के सामाजिक कार्यकर्ताओं व आम लोगों ने भी बढ़ते अपराध से परेशानी महसूस करते हुए जिला प्रशासन व राज्य सरकार से सुरक्षा बंदोवस्त दुरुस्त करने की मांग की है. सामाजिक संगठन नागरिक मंच, दवा व्यवसायी संघ, व्यवसायी संघ, यूथ रेडक्रॉस, आइएमए, चैंबर ऑफ कॉमर्स व लायंस क्लब ने पिछले महीना संपन्न बैठक में शहर के प्रमुख चौक व चौराहा पर सीसीटीवी कैमरा लगाने, पुलिस पिकेट की स्थापना कराने, आत्मरक्षार्थ हथियार का लाइसेंस देने समेत अन्य मांग की थी, जबकि रालोसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन कुमार सिंह ने जिला मुख्यालय डुमरा में युवा रालोसपा के तत्वावधान में आयोजित धरना में साफ लहजे में कहा कि कानून नाम का कोई चीज नहीं रह गया है. अब देखना यह है कि जिले में नव पदस्थापित पुलिस कप्तान अपराधियों को सलाखों में डालने के साथ ही जिले में अमन कायम करने में कामयाब होते हैं अथवा नहीं. दूसरा यह कि परेशान लोगों को जिला प्रशासन किस स्तर पर सुरक्षा की गारंटी दे पाती है. हथियार लाइसेंस मांगने वालों को गृह मंत्रालय के निर्देश पर राहत मिलती अथवा पूर्ववत दौर लगाने की विवशता कायम रहती है. फिलहाल, जिला के लोग अमन व शांति का शासन मिलने की आस लगाये हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

विधायक उपवास पर

जदयू के राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में स्थानीय जदयू विधायक गुड्डी देवी व जदयू नेता राजेश चौधरी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उपवास में भागीदारी दी. केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र सिंह ने की. मौके पर पार्टी नेता रामाश्रय शरण, राम मनोहर सिंह, प्रहलाद महतो, विपिन कुमार, मो. मेराज आलम, फगुनी मांझी, महेंद्र भगत, राकेश चौधरी, काजल वर्मा, वासुदेव शर्मा, देव किशोर, रामचंद्र राम, नागेंद्र व विनोद समेत अन्य थे. *–विभा सिन्हा*

लोजपा की पकड़ मजबूत

सीतामढ़ी जिले में लोजपा की पकड़ काफी मजबूत होती जा रही है. विकास के नाम पर वोट की राजनीति करने वालों को आम जनता पहचान चुकी है. 2015 के विधानसभा चुनाव में जनता एक-एक से हिसाब लेने को तैयार है. डुमरा रोड स्थित अपने आवास पर लोजपा नेता सवीह अहमद ने उक्त बातों के अलावा कहा कि सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी व सुरसंड विधानसभा क्षेत्र में विकास का मतलब समझना आसान नहीं रह गया है. सड़क, चिकित्सा, पेयजल समेत अन्य सुविधाओं का घोर अभाव है. सरकार प्रायोजित योजनाओ का लाभ आम लोगों को मिलना मुश्किल हो गया है. आम आवाम अबकी बार लोजपा के पक्ष में गोलबंद होने लगी है. इसका नतीजा समय पर सामने आने की पूरी इम्मीद है. *– विकास*

जंगली जानवरों का आतंक

भारत – नेपाल सीमा पर अवस्थित सीतामढ़ी जिला पिछले कुछ महिनों से जानवरों के आतंक से त्रस्त है. हाल के महीना में नेपाल के जंगल से भटक कर आए एक हाथी ने कई लोगों की जान ले ली थी. लोग अभी इस घटना को भूले भी नहीं थे कि बेला थाना क्षेत्र के कन्हवा में एक शिव मंदिर में कुछ लोगों ने एक हिरण को देख कर परेशान हो गये. मंदिर में हिरण की सूचना पर थानाध्यक्ष संजीत कुमार ने रेंज आफिसर अभय कुमार को जानकारी दी. जानकारी के बाद वनरक्षी नथुनी पासवान व महेंद्र ठाकुर ने उक्त हिरण को पकड़ लिया. इधर, घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला जदयू उपाध्यक्ष सज्जन कुमार सुंदरका ने राज्य सरकार से जिला में जंगली जानवरों के प्रवेश पर निगरानी व धड़-पकड़ की व्यवस्था जनहित में करने की मांग की है. *– रूपा कुमारी*

मनोज अध्यक्ष, नीलम उपाध्यक्ष निर्वाचित

सीतामढ़ी जिले के पुपरी अनुमंडल कार्यालय में संपन्न चुनाव के दौरान मनोज कुमार यादव नगर पंचायत का अध्यक्ष तो नीलम देवी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई. वार्ड पार्षदों की एकता का नतीजा रहा कि दोनो निर्विरोध निर्वाचित हुए. दोनों के अलावा तमाम निर्वाचित वार्ड पार्षदों को पूर्व सांसद सीताराम यादव, पूर्व मुखिया मो. इसरारुल हक, पूर्व जिला पार्षद मो. अमजद अली, पूर्व इप प्रमुख मो. अब्दुल सकुर उजाले, पैक्स अध्यक्ष मो. शमीम उर्फ काले, सरपंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष रामू मिश्र, युवा जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सूरज कुमार, अभय सिंह, निर्भय सिंह व हैप्पी सिंह समेत अन्य ने बधाई दी है. *– गोविंद कुमार*

चित्रकला में माहिर है मेघा

सीतामढ़ी शहर के सिनेमा रोड निवासी डॉ रवींद्र प्रसाद की पुत्री मेघा के कला का जवाब नही है. स्थानीय लिटल एंगल एकेडमी के एलकेजी की छात्रा मेघा अब तक दर्जनो देवी-देवताओं का चित्र अपने हाथों बना चुकी है. इसके अलावा स्कूल द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमो में बेहतर कला प्रदर्शन कर पुरस्कार भी पा चुकी है. नन्ही मेघा स्कूल से आने के बाद अपनी मां ममता प्रसाद व नानी उषा देवी के मार्गदर्शन में नियमित चित्रकला में बेहतर करने की तैयारी में लगी रहती है. सीतामढ़ी जिला युवा रालोसपा छात्र संसद के अध्यक्ष विशाल कुमार सिंह ने मेघा को पुरस्कृत करने की घोषणा की है. *– ब्रजेश कुमार*

गोगरी में उपवास

गोगरी एवं परबत्ता प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित चबूतरा पर जदयू कार्यकर्ताओं ने प्रखंड अध्यक्ष नंदलाल मंडल की अध्यक्षता में शनिवार को उपवास रखा. पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून लाया था जो काफी लचीला था. जिसमें बंजर और परती भूमि को शामिल किया गया था. वासगीत भूमि को अलग रखा गया था. किन्तु केन्द्र की नरेन्द्र मोदी की सरकार ने जो कानून बनाया है वो अंग्रेजी शासन काल का है. मौके पर नन्दलाल मंडल, मणिभूषण राय, ध्रुव कुमार शर्मा, जर्नादन कुमार, श्रीकांत सिंह, मुकेश कुमार, मनोज कुमार भगत, विजय कुमार, जदयू के मीडिया प्रभारी बब्बु हजारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे. जदयू नेता व कार्यकर्ता एक जुट होकर उपवास कार्यक्रम के तहत प्रखंड कार्यालय समक्ष टेंट लगाकर इपवास के साथ धरना पर बैठे रहे. मौके पर उपस्थित जदयू किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव व शिक्षाविद राजकिशोर यादव ने बताया कि भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर राज्य स्तर पर कार्यक्रम आयोजित की गई है. जिसके तहत प्रखंड कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय उपवास व धरना कार्यक्रम आयोजित की गई है. इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष धर्मदेव पटेल, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष संजय कुमार उर्फ अनिल पोद्दार, प्रधान सचिव जय कुमार सिन्हा, महादलित प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष धनिकलाल दास, पंकज सिह, फणीभूषण यादव, लाल बिहारी चौरसिया, राजेश झा, फिरोज खान, आजाद खान, जर्नादन यादव, राजेश केशरी, राजीव कुमार, विरेन्द्र पटेल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे.

पेंशन राशि वितरित

गोगरी नगर पंचायत गोगरी-जमालपुर में पेंशन राशि वितरण कार्यक्रम के तहत शनिवार को नगर पंचायत के वार्ड संख्या 5 एवं 6 के वृद्ध पेंशन लाभुकों के बीच पेंशन राशि का वितरण किया गया. मौके पर दो सौ से अधिक लाभुकों के बीच पेंशन राशि का वितरण नप के टैक्स दरोगा मुन्ना पांडेय के द्वारा किया गया. पेंशन वितरण को लेकर नप कार्यालय में लाभुकों की भीड़ लगी रही. नप के टैक्स दरोगा ने बताया कि वृद्धा पेंशन के लाभुकों को पांच माह का पेंशन राशि दिया गया है. जो अक्टूबर से फरवरी तक की राशि है. प्रत्येक माह चार सौ रूपये की दर से दो हजार रूपये सभी लाभुकों को दिया जा रहा है. इन्होंने कहा कि बाद में सभी वार्ड के लाभुकों को यह राशि वितरित कर दिया जायेगा.■

– गीता कुमार

मेरे हिस्से आई चिट पर अशोक का नाम था

वैसे तो भारतीय समाज में परंपराएं मानव हित के लिए बनाई गईं लेकिन बदलते वक्त के साथ उनमें परिवर्तन नहीं हो सका. फलस्वरूप उन्होंने एक रूढ़ि का रूप धारण कर लिया. आधुनिक समाज में ऐसी किसी भी परंपरा के लिए कोई स्थान नहीं हैं जो रूढ़ीवादी हो. इन्हीं में से एक है जातिप्रथा, जो एक ऐसी व्यवस्था है जिसके आधार पर एक ही समाज में रहते हुए मनुष्यों को उसकी जाति के आधार पर ऊंची-नीची जैसी कई श्रेणियों में विभाजित किया जाता है. इस बार हम ऐसे ही जातिवाद के भंवर में फंसे एक जोड़े के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने अलग-अलग जातियों के होने के कारण काफी परेशानियां झेलीं.

राधिका

जब बरसों से चली आ रही परंपराएं वर्तमान को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक नहीं रहतीं तो उन्हें संशोधित करना ही एकमात्र विकल्प रह जाता है. शायद कोई भी जागरुक समाज, जो अपनी प्रगति को लेकर गंभीर रहता है, कभी इन खोखली और बेमानी मान्यताओं को नकारने में संकोच नहीं करता. भारत मूल रूप से एक ग्रहणशील और स्वभाव से लचीला राष्ट्र रहा है किंतु समय-समय पर झेले गए अनेक झंझावातों के कारण यहां पर कई सामाजिक नियमों व संस्थाओं में जटिलता आ गई है.

वैसे तो भारतीय समाज में परंपराएं मानव हित के लिए बनाई गईं लेकिन बदलते वक्त के साथ उनमें परिवर्तन नहीं हो सका. फलस्वरूप उन्होंने एक रूढ़ि का रूप धारण कर लिया. आधुनिक समाज में ऐसी किसी भी परंपरा के लिए कोई स्थान नहीं हैं जो रूढ़ीवादी हो. इन्हीं में से एक है जातिप्रथा, जो एक ऐसी व्यवस्था है जिसके आधार पर एक ही समाज में रहते हुए मनुष्यों को उसकी जाति के आधार पर ऊंची-नीची जैसी कई श्रेणियों में विभाजित किया जाता है.

इस बार हम ऐसे ही जातिवाद के भंवर में फंसे एक जोड़े के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने अलग-अलग जातियों के होने के कारण काफी परेशानियां झेलीं. आज भी हमारे समाज में ऐसे विवाह को आसानी से स्वीकारा नहीं जाता है. हम बात कर रहे हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक चौधरी और उनकी धर्मपत्नी नीता केसकर चौधरी की. नीता बताती हैं कि ये पहली नज़र का प्यार नहीं था बल्कि धीरे-धीरे समय के साथ परिपक्व हुआ प्यार था. साल 1990 में हम दोनों एक-दूसरे से एक डांस पार्टी में मिले थे, जहां अशोक अपने दोस्त के साथ आए हुए थे. उस डांस पार्टी में जब चिट्स निकाली गई और जो चिट मेरे हिस्से आई, उस पर अशोक का नाम था. ऐसे हुई थी हमारी पहली मुलाकात. फिर मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा. मुलाकातें कब प्यार में बदल गईं, पता ही नहीं चला. नीता आगे बताती हैं कि जाति के साथ-साथ एक और दिक्कत भी थी, वो थी कि

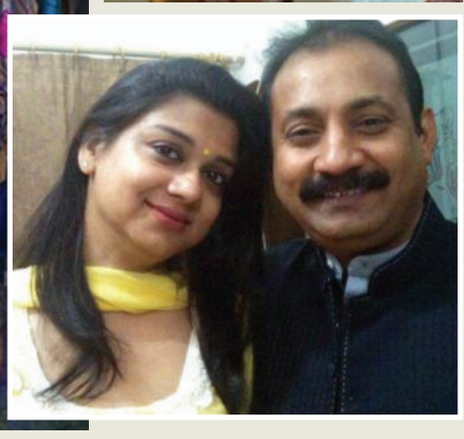

अशोक जॉब नहीं करना चाहते थे. शादी से पहले वो बिजनेस करते थे. और यही बात मेरी मां को पसंद नहीं थी. मेरी मां चाहती थी कि मेरा जो भी लाइफपार्टनर हो वो अच्छी जॉब करे और अच्छे से सेटल हो. उनका मानना था कि अशोक ठीक से सेटल नहीं है और शायद मुझे अच्छे से नहीं रख सकेंगे. हमने अपने घरवालों को मनाने की पूरी कोशिश की. लेकिन जब हम घर वालों को मनाने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए तब मैंने घर छोड़ने का फैसला लिया. घर छोड़ते ही हमने कोर्ट मैरेज कर ली. हमारी शादी 1996 में हुई थी. शादी के बाद हमें बहुत सारे लोगों की नाराज़गी झेलनी पड़ी. इस बात से सबसे ज्यादा नाराज़ मेरी मां ही थीं. हमें बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ीं. लेकिन शादी के करीब छह महीने बाद सब कुछ सामान्य होने लगा. लोगों ने हमें समझा. साथ ही हम दोनों को दिल से एक्सेप्ट भी कर लिया. नीता आगे बताती हैं कि अशोक बहुत ही साफ दिल के व्यक्ति हैं. उनका व्यक्तित्व ज़मीन से जुड़ा हुआ है या फिर यूं कह सकते हैं कि उनमें कभी भी किसी बात का घमंड नहीं आया. सबसे ख़ास बात कि अशोक रिश्तों की बहुत कद्र करते हैं. इसी बात ने मुझे उनकी तरफ आकर्षित किया था. इन दोनों ने कई दिक्कतें देखीं. कई लोगों का विरोध भी सहा. लेकिन इस दौरान उनका प्यार और एक-दूसरे के प्रति जो विश्वास था, वो बहुत मजबूत था. समाज के तानों से लेकर घरवालों की नाराज़गी, इन दोनों ने सबकुछ झेला. लेकिन जितनी भी दिक्कतें आईं, वो उनके प्यार की नींव को कमज़ोर नहीं कर सकीं. आखिर कार उनके प्यार के सामने समाज ने घुटने टेक दिए.

कहते हैं अंत भला तो सब भला. कुछ ऐसा ही इन दोनों के साथ भी हुआ. भले ही शादी से पहले कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो लेकिन आज सब कुछ ठीक है. दोनों का दांपत्य जीवन बहुत ही खुशनुमा है. इनकी तीन बेटियां हैं. तीनों ही बेटियां नॉट्रेडेम में पढ़ती हैं. बड़ी बेटी एलेवेन्थ में है, मंजली बेटी सेवेन्थ में और छोटी बेटी सिक्स्थ में है. इतना हीं नहीं नीता घर को संभालने के साथ-साथ अपना स्कूल भी चलाती हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

गुरुकुल महाविद्यालय

ऐतिहासिक धरोहर को समाप्त करने की साजिश

रणजीत झा

देवघर जिले के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय रच चुके गुरुकुल महाविद्यालय को जमींदोज़ कर समाप्त करने की साजिश हो रही है. आधुनिकता की अंधी दौड़ में इस गौरवमयी ऐतिहासिक, पुरातन धरोहर की महत्ता सरकार की नज़रों में कम हो गई है. वर्तमान में केंद्र में भाजपा की सरकार विराजमान है, जो हमेशा ही देश की गौरवपूर्ण धरोहरों एवं भारतीय संस्कृति की रक्षा करने की बात करती रही है, आज इसी भाजपा सरकार के रहते गुरुकुल महाविद्यालय का अस्तित्व समाप्त होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है. स्थानीय भाजपा सांसद निशिकांत दूबे की महत्वाकांक्षी योजनाओं में वर्तमान हवाई अड्डा विस्तारीकरण के तहत ऐतिहासिक गुरुकुल महाविद्यालय के मूल भवन सहित परिसर की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया प्रगति पर है. वैसे हवाई अड्डा क्षेत्र के लिए पूर्व में दो बार की मापी में गुरुकुल महाविद्यालय भवन एवं परिसर को मुक्त रखा गया था परन्तु बाद में किसी साजिश के तहत गुरुकुल महाविद्यालय भवन परिसर को शामिल किया गया. इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय खंडपीठ द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किया गया है कि किसी भी ऐतिहासिक गौरव के संस्थान एवं इसके स्वरूप को आधुनिक परियोजनाओं के विकासार्थ भी कदापि परिवर्तित नहीं किया जाय, जबतक कि इस मूल संस्था की स्वीकृति न हो.

गुरुकुल महाविद्यालय, वैद्यनाथधाम आर्य समाज द्वारा संचालित एक आदर्श आवासीय शिक्षण संस्था है, जहां सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर बालकों को उत्कृष्ट सामयिक शिक्षा देकर उनका शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आत्मिक उन्नयन कर उन्हें राष्ट्र और समाज का सच्चा उपासक तथा सुयोग्य विद्वान एवं चरित्रवान नागरिक बनाया जाता है. यह गुरुकुल महाविद्यालय अध्ययन और अध्यापन, चरित्र और संस्कृति, अवस्था और अनुशासन तथा उत्कृष्टता और दक्षता का प्रतीक माना जाता है. यह देश-विदेश के प्रख्यात विद्वान, सुयोग्य प्रशासक, सुविख्यात अधिवक्ता, चिकित्सक, अभियन्ता, प्राध्यापक, राजनेता, देश भक्त स्नातकों की कुलभूमि है. वर्तमान में उत्तर प्रदेश के शिक्षामंत्री के ओएसडी एम पी वर्मा, पर्यावरण मंत्रालय में सलाहकार ब्रह्मचारी सुरेश चन्द्र, पूर्व संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, बिहार सरकार ब्रह्मचारी भुवनेश्वर प्रसाद सिंह एवं पटना विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष ब्रह्मचारी श्याम नंदन शास्त्री इसी गुरुकुल के विद्यार्थी रहे है.

पूर्वी भारत के बेहतरीन शिक्षण संस्थाओं में शुमार इस गुरूकुल की स्थापना सन 1924 ई. में झारखंड प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी देवघर से पांच किलोमीटर दक्षिण प्रकृति के मनोरम, उन्मुक्त, स्वास्थ्यप्रद एवं शैक्षणिक वातावरण में विश्वविख्यात विद्वान साहित्यकार एवं वैदिक साहित्य के मर्मज्ञ आचार्य पं रामचंद्र द्विवेदी के कर कमलों द्वारा हुई थी. लगभग 66 एकड़ भूखंड में बने गुरुकुल महाविद्यालय परिसर में विद्यालय, छात्रावास, यज्ञशाला, भोजनालय एवं औषधालय आदि के भव्य भवन निर्मित हैं.

यहां प्रारंभिक काल से ही हरिजन, आदिवासी एवं अतिनिर्धन छात्रों को शिक्षण के साथ साथ मुफ्त आवासीय व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाती रही है.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कोर्ट, कौंसिल और कॉलेज के बहिष्कार के आह्वान के समय इस गुरुकुल ने देश के बालकों को संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान कर राष्ट्रभक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. स्वतंत्रता संग्राम के समय आस पास के स्वतंत्रता सेनानियों के कार्य संचालन का केन्द्र रहने के कारण उनके गुप्त आवासन, भोजन आदि की व्यवस्था भी करता था.

महामना मदन मोहन मालवीय, डॉ राजेन्द्र प्रसाद, आचार्य विनोभा भावे, श्रीकृष्ण सिंह, पं बिनोदानंद झा आदि अनेक महान विभूतियों का यहां पर रहना हुआ है. आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, मैथिली शरण गुप्त पं रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह

दिनकर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्री हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय आदि अनेक मूर्धन्य विद्वान साहित्यकारों की यह भूमि तीर्थस्थली रही है. वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदर मोदी द्वारा चलाए जा रहे स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम, जो आर्य समाज संगठन की मूल भावना है, के अनुरूप ही गुरुकुल महाविद्यालय भी इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कृतसंकल्पित एवं अग्रसर है.

आर्य समाज की शिरोमणि संस्था सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली ने यह योजना तैयार की है कि इस गुरुकुल को पूरे पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के केन्द्र के रूप में विकसित किया जाय. इसी क्रम में यह गुरुकुल स्वतंत्रता आन्दोलन के क्रांतिकारियों के मंदिर के रूप में विख्यात गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार की इकाई के रूप में उच्चशिक्षा में मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, आयुर्वेद तथा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलने के साथ साथ मानवाधिकार एवं वैश्विक शांति के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अग्रसर है जिसके लिए हमारे पास उपलब्ध जमीन यथेष्ट नहीं है. भारत की पहली आयुर्वेदिक फार्मेसी के रूप में विख्यात रही गुरूकुल कांगड़ी हरिद्वार की अनुशांगिक इकाई के रूप में इसके विभिन्न उत्पादों के निर्माण की योजना भी यहां है. साथ ही, प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र कुरुक्षेत्र हरियाणा एवं कालिकट केरल के सांगठनिक सहयोग से देवघर गुरुकुल में ही प्रकल्प के भव्य निर्माण की भी योजना है.

वृद्धाश्रम, गोसंवर्द्धन केन्द्र, इन्नत कृशि केन्द्र के साथ साथ रोजगारोन्मुखी व्यवसायिकी शिक्षा से स्थानीय जनता को लाभान्वित करने की योजना भी है.

गुरुकुल प्रबंधकाणिी समिति की दृढ़ इच्छा है कि लगभग सौ वर्ष पुरानी इस प्रतिष्ठित ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्था गुरुकुल महाविद्यालय की ज़मीन एवं मूल भवना के अस्तित्व को बिना छेड़ छाड़ किए इसके पूर्ण स्वरूप को रहने दिया जाय ताकि यह संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप मानव उत्थान, राष्ट्र निर्माण के साथ साथ संस्कारवान एवं चरित्रवान युवाओं का निर्माण करने की राह पर अबाधगति से अग्रसर रह सके. इसी क्रम में गुरुकुल महाविद्यालय की इकाई के रूप में कक्षा एक से पांचवीं तक के बच्चों हेतु स्वामी दयानंद गुरुकुल ग्लोबल ऐकेडमी का संचालन हो रहा है.■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

30 मार्च –05 अप्रैल 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

अखिलेश के तीन साल

हर मोर्चे पर असफल

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने तीन साल पूरे कर लिए और उत्तर प्रदेश पर 2.70 लाख करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ डाल दिया. बदहाल कानून व्यवस्था का बोझ तो इसके अतिरिक्त वाला है. अभी दो साल बाकी हैं, देखना यह है कि यह बोझ घटता है कि बढ़ता है. इस तीन साल के समाजवादी अनुभव ने कहीं से भी पांच साल के बहुजनी अनुभव से बेहतर महसूस नहीं कराया. सब एक ही थैली के चट्टेबट्टे साबित हो रहे हैं, बस सत्ता का स्वाद विभिन्न रंगों की बोतलों में भरे एक ही तरह के सड़ियल शरबत की तरह है. मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने भी प्रदेश पर कर्जे का बोझ डाल दिया था. कर्ज और ब्याज की अदायगी भी कर्ज से ही करनी पड़ रही है. हाल यह है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के सिर पर करीब 20 हजार रुपये का कर्ज है. मायावती के कार्यकाल में प्रति व्यक्ति कर्ज का बोझ करीब साढ़े बारह हजार रुपये था, जो लगातार बढ़ता जा रहा है, अखिलेश सरकार इसे कम करने की तो छोड़ें, काबू भी नहीं कर पाई. मायावती के कार्यकाल में सरकारी धन की फिजूलखर्ची और भ्रष्टाचार ने सारी हदें तोड़ डाली थीं. पार्कों, स्मारकों, मूर्तियों, पत्थरों और बेमानी के काम में सरकारी धन पानी की तरह बहाया गया और प्रदेश पर कर्ज का भारी बोझ लाद दिया. अखिलेश सरकार उन्हीं महान कृत्यों का अनुसरण कर रही है.

समाजवादी सरकार के मुखिया अखिलेश यादव को अपने तात्कालिक–पूर्वकालिक वरिष्ठ का अनुकरण करने में कोई संकोच नहीं हो रहा. मायावती की फिजूलखर्चियों पर दी जाने वाली समाजवादी प्रतिक्रियाएं फिजूल ही साबित हुईं और वही सब होने लगा जो पूर्ववर्ती सरकार ने किया था. सरकारी समारोहों, अनावश्यक योजनाओं, पार्कों, स्मारकों, विज्ञापनों, लैपटॉप, भत्तों और मुआवजों की भेदभावभरी रेवड़ी बांटने और समाजवादी वीवीआईपियों की सुरक्षा पर अखिलेश सरकार ने अब तक अरबों रुपये फूंक दिए हैं. तीन साल में ही अखिलेश यादव ने कर्जे लेने का भी रिकॉर्ड बनाया है. सरकार ने यह आधिकारिक तौर पर माना है कि प्रदेश पर लगभग 2.70 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है जिसके ब्याज के बतौर करीब 19 हजार करोड़ का भुगतान हर साल करना पड़ रहा है. फिर प्रदेश का विकास क्या हुआ और विकास के दावे किस पोपली जमीन पर खड़े हैं, इस बारे में आसानी से सोचा–समझा जा सकता है. भारी कुपोषण का शिकार प्रदेश के 42 प्रतिशत बच्चे समाजवादी सरकार के विकास का गवाह और प्रमाण हैं. अखिलेश सरकार यह मामूली बात भी नहीं समझ पा रही कि प्रदेश के एक लाख 12 हजार 845 स्कूलों में पढ़ रहे 76 लाख 29 हजार बच्चों को आयरन व फोलिक एसिड की गोलियां खिला देने से कुपोषण नहीं मिटने वाला. कुपोषण लगातार मिलने वाले भोजन से दूर होता है.

15 मार्च 2012 को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे. सरकार ने प्रदेश में एक लाख करोड़ रुपये के निवेश की व्यवस्था कराने का भरोसा दिया था. लेकिन सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि 2012–13 में प्रदेश में 11 हजार 872 करोड़ 58 लाख रुपये का निवेश हुआ और 2013–14 में 14 हजार 602 करोड़ 85 लाख रुपये का निवेश हो पाया. इस साल भी 50 हजार करोड़ रुपये के निवेश का सरकारी दावा मंच पर आया, लेकिन हुआ केवल 8 हजार 700 करोड़ रुपये का निवेश. वह भी अभी केवल प्रस्ताव के ही शक्ल में. निवेश में फेल होने की वजह अखिलेश सरकार का कानून व्यवस्था की परीक्षा में बुरी तरह फेल होना है. अखिलेश सरकार के तीन वर्ष के कामकाज पर ध्यान दें तो आपको एक बेसिरपैर का टाइमपास दिखाई देगा, जिसमें जनहित का तो कुछ नहीं, पर व्यक्तिहित और निज–हित के तमाम स्वार्थ सधते हुए दिखाई देंगे. इन तीन वर्षों में एक तरफ मुलायम का सामंती जन्मोत्सव, सैफई महोत्सव और राजशाही तिलकोत्सव दिखाई देगा तो दूसरी तरफ आपको किसानों की बदहाली दिखाई देगी, महिलाओं की त्रासदी दिखाई देगी, सार्वजनिक गुंडई दिखाई देगी, दंगे दिखाई देंगे और दिखाई देंगे हर तरह के अपराध और भ्रष्टाचार.

इन सब विद्रूप जमीनी–दृश्यों से लापरवाह समाजवादी पार्टी

15 मार्च 2012 को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे. सरकार ने प्रदेश में एक लाख करोड़ रुपये के निवेश की व्यवस्था कराने का भरोसा दिया था. लेकिन सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि 2012–13 में प्रदेश में 11 हजार 872 करोड़ 58 लाख रुपये का निवेश हुआ और 2013–14 में 14 हजार 602 करोड़ 85 लाख रुपये का निवेश हो पाया.

बीते तीन साल को गौरवशाली और ऐतिहासिक मानती है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते हैं कि उन्होंने तीन साल में मंत्रियों और अधिकारियों के सहयोग से तमाम वादे पूरे किए हैं. जबकि मुख्यमंत्री के पिता मुलायम सिंह यादव लगातार यह कहते रहे कि प्रदेश सरकार के कई मंत्री भ्रष्ट हैं और कई नौकरशाह अराजक हैं. मुलायम ने कई मंचों से कहा कि जो मंत्री और अफसर अपने गांव को नहीं बना पाए, वे उत्तर प्रदेश को क्या बनाएंगे, उन्हें कमीशनखोरी से ही फुर्सत नहीं है तो वे काम क्या करेंगे. मुलायम ने कई बार सरकार को आगाह किया कि सरकार के अच्छे कामों की रफ्तार बेहद सुस्त है. उन्होंने कहा भी कि वे खुद ही इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की कोई परियोजना पूरी हो और वे उसका उद्घाटन कर सकें, लेकिन उन्हें यह मौका नहीं मिल रहा. पार्टी के फोरम पर भी मंत्रियों को बुलाकर उनसे उनके उल्लेखनीय काम पूछे गए तो कोई मंत्री अपना एक काम नहीं बता पाया. इस पर नाराज मुलायम ने कहा कि उत्तर प्रदेश यदि पिछड़ा है तो ऐसे ही मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अफसरों के कारण. लेकिन अखिलेश ने मुलायम के वक्तव्यों की कोई परवाह नहीं की. दिलचस्प तो यह भी है कि सपा सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता भयमुक्त खुली हवा में सांस ले रही है. राजधानी लखनऊ से लेकर प्रदेशभर में जिस तरह दुस्साहसिक अपराध और सार्वजनिक गुंडई की घटनाएं हो रही हैं, उससे जनता त्रस्त है, उन वीभत्स घटनाओं के विवरण को दोहराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे लोगों के जेहन में ताजा हैं और नई–नई घटनाएं उसमें जुड़ती जा रही हैं. सपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी कहते हैं कि पिछले तीन साल में सरकार ने अपने चुनावी घोषणापत्र में किए गए ज्यादातर वादों को अमली जामा पहनाया है. समाज के हर वर्ग के लिए बुनियादी काम की शुरुआत हुई है और आने वाली पीढ़ियां इसकी वजह से सपा सरकार को हमेशा याद करेंगी. चौधरी ने कहा कि सरकार ने गरीबों, किसानों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों समेत समाज के सभी वर्गों के हितों के लिए काम किए हैं. मुख्यमंत्री ने लखनऊ मेट्रो, पुलिस सुधार, बुनियादी ढांचा विकास, अवस्थापना सुविधाओं, औद्योगिक निवेश तथा शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल की हैं जिनका फायदा पूरे प्रदेश को होगा. जबकि विपक्ष की राय चौधरी–रटंत से उल्टी है. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक कहते हैं कि अखिलेश सरकार ने जिस दिन शपथ ली थी उस दिन जो चुनौतियां थीं, वही आज भी बरकरार हैं. कानून–व्यवस्था चुनौती थी और आज भी है. औद्योगिक निवेश और विकास की चुनौतियां थीं, आज भी हैं. बड़ी–बड़ी बातें तो खूब हुईं, लेकिन कारगर कुछ नहीं हुआ. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने कहा कि सपा ने इन तीन वर्षों में जनता को सिर्फ ठगा है. पूर्व की सरकार की तरह अखिलेश सरकार में भी ऐश–मौज और लूट की रवायत पर चल रही है. प्रदेश में शासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है. कानून–व्यवस्था ध्वस्त है, महिलाएं असुरक्षित हैं. कत्ल, डकैती और राहजनी सरेआम है. राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि सपा ने अल्पसंख्यकों को 18 प्रतिशत का आरक्षण देने, सभी किसानों का 50 हजार रुपये तक का कर्ज माफ करने, गन्ने के दामों में बढ़ोत्तरी करने और किसान आयोग बनाने समेत अनेक वादे किए थे लेकिन वे पूरे नहीं हुए.

तीन साल के कामकाज की समीक्षा का निष्कर्ष यही है कि उत्तर प्रदेश का किसान जितनी तबाही की स्थिति में पहुंच गया, वह एक प्रतिमान ही है. सपा सरकार के कार्यकाल में चीनी मिल मालिकों के हाथों में किसानों की खुशहाली गिरवी रख दी गई. किसानों का करोड़ों का बकाया लम्बित रखने वाली चीनी मिलों को सरकार ने तरह–तरह की रियायतें दीं जबकि किसानों को अपने गन्ने का वास्तविक मूल्य भी नहीं मिल रहा. प्रदेश का गन्ना किसान तबाह हो गया. अनाज उपजाने वाले किसानों के साथ भी सरकार ने ऐसा ही किया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने चौथे बजट में आकर किसानों के हित की कई घोषणाएं कीं. 302867.32 करोड़ रुपये का बजट लाकर मुख्यमंत्री ने 2015–16 को किसान वर्ष घोषित किया, लेकिन प्रदेश को यह नहीं बताया कि पिछले बजट के 3152 करोड़ रुपये सरकार क्यों नहीं खर्च कर पाई. प्रदेश की सत्ता पर आने के बाद अखिलेश सरकार ने घोषणा की थी कि बसपा कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचारों की जांच के लिए आयोग का गठन किया जाएगा. लेकिन यह वादा उल्टा मायावती और उनके मंत्रिमंडल के भ्रष्ट सदस्यों को बचाने और संरक्षण देने में ही लग गया. फिर तो समाजवादी पार्टी के नेता और नौकरशाह भी इसी काम में लग गए. प्रदेश के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और नोएडा प्राधिकरण के चीफ इंजीनियर यादव सिंह के कारनामे सुर्खियों में हैं. सपा सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री और भ्रष्ट मंत्रियों को भी बचाया. जांच में ढिलाई बरतने के कारण ही लैकफेड (लेबर एंड कंस्ट्रक्शन को–ऑपरेटिव फेडरेशन) घोटाले के सारे सूत्रधार मायावती–काल के मंत्री और आला नौकरशाह बचा लिए गए.

feedback@chauthiduniya.com

पार्टी से लेकर सरकार तक अराजकता

उत्तर प्रदेश में पार्टी से लेकर सरकार तक अराजकता का सृजन हुआ है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव कहते-कहते थक गए कि अखिलेश सरकार के कई मंत्री भ्रष्ट हैं और उनके खिलाफ जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से शिकायती पत्र प्राप्त हो रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने पिता और राष्ट्रीय अध्यक्ष के विचारों की अनदेखी करते रहे. अराजकता का हाल यहां तक पहुंच गया कि मुलायम सिंह यादव ने प्रदेश कार्यकारिणी की एक लिस्ट जारी की तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक और लिस्ट जारी कर दी. मुख्यमंत्री के इस रुख से पार्टी में अराजकता ने पैर पसारे और इसका असर प्रदेश की नौकरशाही पर भी दिखना शुरू हुआ. अब तो आम बात है कि उत्तर प्रदेश को अखिलेश ही नहीं बल्कि उनके साथ कई समानान्तर मुख्यमंत्री और उन सबके अलग-अलग पसंद के नौकरशाह चला रहे हैं. इन समानान्तर मुख्यमंत्रियों में अखिलेश, मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव, आजम खान, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह की पत्नी साधना गुप्ता और मुख्यमंत्री की सचिव अनीता सिंह का नाम लिया जाता है. मुख्यमंत्री के अपने सचिवालय में तैनात अधिकारी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से सजे हुए हैं, लेकिन अखिलेश की प्राथमिकता में ऐसे ही लोग हैं. राज्य में भ्रष्ट अधिकारियों का मजबूत तंत्र बन गया है. मुख्यमंत्री सचिवालय में तैनात राकेश बहादुर मायावती सरकार में नोएडा के चेयरमैन होने के साथ-साथ यमुना एक्सप्रेस-वे इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रमुख भी रहे. इन पर भूमि आवंटन में 4 हज़ार करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले का आरोप है. इनकी गिरफ्तारी तक का फरमान कट चुका था. लेकिन सपा सरकार में राकेश बहादुर का सिक्का चल रहा है. वरिष्ठ आईएएस सदाकांत और प्रदीप शुक्ला पर सपा सरकार की मेहरबानियां किसी से छुपी नहीं हैं. मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रहे पंधारी यादव की करतूतें भी लोग भूले नहीं हैं. ऐसे स्वनामधन्य अधिकारियों की लंबी फेहरिस्त है जो अपने काम से नहीं बल्कि अकाम से विख्यात हैं. इनमें सचिव शंभू सिंह यादव, ओएसडी जगदेव सिंह यादव जैसे भी कई नाम हैं. ऐसे अधिकारियों के प्रति मुख्यमंत्री की चाहत का हाल यह है कि इन्हें रिटायर होने के बाद भी गैर कानूनी तरीके से सेवा विस्तार देकर नौकरी में बरकरार रखा गया है.

उत्तर प्रदेश की खबरें इंटरनेट पर पढ़ने के लिए www.up.chauthiduniya.com लॉगऑन करें.

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

कब तक मनरेगा घोटाले की जांच होगी!

वैष्णवी वंदना

उत्तर प्रदेश का मनरेगा घोटाला सीबीआई जांच के बावजूद किसी नतीजे पर पहुंचता नहीं दिख रहा है. यह हजारों करोड़ का घोटाला है, लेकिन यूपी पुलिस के अधिकारी जिस मामले की जांच करेंगे, उसका क्या नतीजा निकल सकता है? आपको यह सुन कर अटपटा लगेगा कि जब मामले की सीबीआई जांच हो रही है तो फिर यूपी पुलिस बीच में कहां से आ गई. यह सवाल वाजिब है. इसलिए बता दें कि मनरेगा घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों-कर्मचारियों को डेपुटेशन पर अपने साथ अटैच कर रखा है, लेकिन उनसे सीबीआई को सुविधा मिलने के बजाय मुश्किलें ही पेश आ रही हैं. यूपी पुलिस के अधिकारियों-कर्मचारियों का अंग्रेजी में हाथ तंग है, इसलिए अंग्रेजी में लिखे दस्तावेजों के समीक्षा में वे अगड़म का बगड़म कर रहे हैं. जांच में यूपी पुलिस के लोगों के अपने स्थानीय लगाव भी आड़े आ रहे हैं. आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के मनरेगा घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे रखा है. सीबीआई जांच टालने के लिए यूपी सरकार सुप्रीमकोर्ट तक गई, लेकिन जांच नहीं टली. प्रदेश के सात प्रमुख दागदार जिलों के अलावा कई और जिले जांच के दायरे में हैं.

मनरेगा घोटाले की जांच में तमाम सियासी-प्रशासनिक रुकावटों के साथ-साथ अंग्रेजी भी बाधा बन रही है. सीबीआई ने घोटाले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से यूपी पुलिस के कुछ लोग मांगे थे. उस समय तक शायद सीबीआई को यह भरोसा था कि यूपी पुलिस के अधिकारी-कर्मचारियों को अंग्रेजी का कुछ ज्ञान होगा. लेकिन अब पता चला कि वे अंग्रेजी में बिल्कुल पैदल हैं. अंग्रेजी के दस्तावेज व फाइलों की समीक्षा व लिखा-पढ़ी के लिए डेपुटेशन पर लाए गए यूपी पुलिस के ज्यादातर कर्मचारी औंधे मुंह गिर जा रहे हैं. पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार ही मामले की सीबीआई जांच में अड़ंगे डालती रही. जांच में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीधे हस्तक्षेप से घोटाले की जांच सीबीआई के पास पहुंची. लेकिन सीबीआई के पास काम का बोझ इतना है कि उसने यूपी पुलिस के ही अधिकारियों-कर्मचारियों को डेपुटेशन पर देने का प्रदेश सरकार से आग्रह कर डाला. सरकार ने सोच-समझ कर यूपी पुलिस के उन अधिकारियों-कर्मचारियों को सीबीआई से अटैच करा दिया, जो सीबीआई की जांच में ढिलाई बरतने की सारी योग्यता रखते हों. [illegible] चल रही है.

विडंबना यह है कि मनरेगा जैसी योजनाओं के लिए केंद्र से करोड़ों रुपये आते रहे, लेकिन उसके खर्च की देख-रेख के लिए कोई निगरानी व्यवस्था नहीं की गई. प्रदेश सरकार के नेता और नौकरशाह इस धन को बपौती समझ कर खाते रहे. प्रदेश के सभी जिलों में मनरेगा के तहत सम्पर्क मार्ग, बाढ़ नियंत्रण, जल संचय, छोटी बड़ी नहरों की सफाई, निर्माण, सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराने समेत दर्जनों अन्य काम होते रहे, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मनरेगा से जुड़े कार्यालय में इससे जुड़े खर्च का कोई हिसाब-किताब उपलब्ध नहीं है. सीबीआई राज्य सरकार से दस्तावेज मांगती है, लेकिन दस्तावेज दिया नहीं जा रहा. मनरेगा घोटाले की जांच में सपा सरकार के कई खास अफसरों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है. इस वजह से भी यूपी सरकार के अफसर मनरेगा घोटाले की जांच अटका रहे हैं.

सीबीआई ने सरकार से 40 लाख और उससे ऊपर के मनरेगा के तहत हुए सारे काम के दस्तावेज मांगे हैं. लेकिन अफसरों ने इसका पहले से जुगाड़ फिट कर रखा था. एक करोड़ के काम को तीन साल में अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया गया था. इससे कोई काम 35 लाख का हुआ तो कोई 37 लाख का तो कोई 28 लाख का. अब तकनीकी तौर पर कोई काम 40 लाख या उससे ऊपर का नहीं है, तो सीबीआई को दस्तावेज ही नहीं सौंपे गए. सीबीआई इसके लिए कई बार मुख्य सचिव व संबंधित विभाग से औपचारिक आग्रह कर चुकी है, लेकिन मामले को बुरी तरह उलझा कर रख दिया गया है.

जिलों की बात करें तो सीबीआई को कुशीनगर में मनरेगा में हुई अनियमितता के कुछ साक्ष्य मिले हैं. इसके बाद सोनभद्र, बलरामपुर, गोंडा, संतकबीर नगर, महोबा और मिर्जापुर में जांच तेज कर दी गई है. छोटे अफसर तो घेरे में आ रहे हैं, लेकिन बड़े मगरमच्छ बचे हुए हैं. कुशीनगर में मनरेगा योजना में घोटाला करने के आरोप में गिरफ्तार तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, अपर मुख्य अधिकारी प्रदीप कुमार और जिला पंचायत सदस्य विजय अग्रवाल से सीबीआई ने पूछताछ भी की है. हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा सात जिलों से बढ़ा कर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश कर दिया है. सात जिलों की जांच के बाद सीबीआई ने अब तक पांच मुकदमे दर्ज किए हैं. जिसमें दो दर्जन से अधिक आईएएस और सौ से अधिक पीसीएस अफसरों के साथ दर्जनों नेताओं के प्रधान जांच के दायरे में हैं. एनआरएचएम घोटाले के बाद यूपी में मनरेगा घोटाला भ्रष्टाचार का दूसरा सबसे बड़ा मामला बन रहा है. सीबीआई को यह भी संदेह है कि घोटाले से जुड़े सबूत और दस्तावेज नष्ट किए जा रहे हैं. तभी सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर यह हिदायत दी थी कि मनरेगा से जुड़े सारे दस्तावेज संभाल कर रखे जाएं. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सचिव रहे पंधारी यादव जब सोनभद्र के डीएम थे, तब उन्होंने मनरेगा के 250 करोड़ रुपये खर्च किए थे. इसमें सिंचाई के नाम पर फर्जी और अनुपयोगी चेक डैम बनवाए गए थे. घोरावल में एक ही तालाब तीन-तीन बार खुदवाया गया था. नजदीकी फर्मों से निर्माण सामग्री की खरीद की गई थी. पंधारी यादव को ही इंगित करते हुए तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा था कि पंचम तल पर तैनात एक अफसर सीबीआई जांच की राह का रोड़ा बना हुआ है.

यूपी के सात जिले दागदार

1. **सोनभद्र:** मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चहेते विशेष सचिव पंधारी यादव जब सोनभद्र के जिलाधिकारी थे, तब मनरेगा में दो सौ से तीन सौ करोड़ के बीच का घोटाला सामने आया था. उन पर अपनी जेबी संस्था छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शंस कम्पनी के जरिए सैकड़ों करोड़ का घपला करने का आरोप है. ईओडब्लू की जांच में भी पंधारी की संदेहास्पद भूमिका सामने आई थी. फिर लीपापोती की कोशिशें भी खूब हुईं. तब तक पंधारी मुख्यमंत्री सचिवालय में सुशोभित भी किए जा चुके थे. पंधारी के अलावा कई अन्य के खिलाफ भी जांच चल रही है.
2. **गोंडा:** मनरेगा घोटाले में तत्कालीन सीडीओ राम बहादुर और अधिकारी दुर्गेश कुमार, जीपी गौतम समेत कई अन्य अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई. यहां मजदूरों के बच्चों के लिए एक करोड़ के खिलौने, दो करोड़ के फावड़े और 50 लाख की पानी की टंकियां खरीदी गई थीं. इस खरीद में खूब घोटाला हुआ और ज्यादातर खरीद बिना टेंडर के ही कर ली गई.
3. **बलरामपुर:** तत्कालीन जिलाधिकारी एसएन दुबे का नाम यहां के मनरेगा घोटाले में खूब बजा. यहां सात लाख रुपये की फ्रस्ट एड किट, डेढ़ लाख के कैलेंडर, छह लाख की पानी की टंकी और 80 लाख के टेंट की खरीद दिखाई गई, लेकिन भौतिक जांच में यह सामान कहीं मिला ही नहीं.
4. **महोबा:** मनरेगा घोटाले में तत्कालीन सीडीओ जयराम लाल वर्मा और जिलाधिकारी विजय विश्वास पंत का नाम सुर्खियों में रहा. यहां 51 लाख के टेंट खरीदे गए थे जो भौतिक जांच में मौके पर नहीं मिले न अफसर उन फर्मों के नाम ही बता पाए जिनसे खरीद हुई. जिले की 140 ग्राम सभाओं पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की गई जो बाद में फर्जी पाई गई.
5. **मीरजापुर:** मनरेगा घोटाले में तत्कालीन जिलाधिकारी मधुकर द्विवेदी समेत रमाकांत शुक्ल, जसवंत सिंह, सीडीओ विजय प्रताप सिंह, भगेलू राम को आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा की जांच में दोषी करार दिया गया था. यहां चार करोड़ से अधिक राशि के सामान की खरीद में मानकों का कोई पालन नहीं किया गया.
6. **संत कबीर नगर:** यहां घोटाले का सारा आरोप एक जूनियर इंजीनियर गंगा प्रसाद श्रीवास्तव पर मढ़ने की कोशिश की गई. जूनियर इंजीनियर की एस्टिमेट रिपोर्ट के आधार पर ही सारा भुगतान दिखाया गया था. उसी जूनियर इंजीनियर ने जांच एजेंसियों को हलफनामा देकर कहा कि उसने कोई एस्टिमेट बनाया ही नहीं था. विभिन्न कामों में जो ईंटें इस्तेमाल की गईं वे स्थानीय बसपा विधायकों के या उनके रिश्तेदारों के ईंट भट्ठे से खरीदी गई थीं.
7. **कुशीनगर:** तत्कालीन जिलाधिकारी भुवनेश कुमार व सीडीओ केदारनाथ, कार्यवाहक सीडीओ बीपी मिश्र मनरेगा घोटाले में चर्चित रहे. यहां 60 लाख की लागत से खड्डा बाजार में रोहुआ पुल बनवाया गया जो दो ही महीने में ध्वस्त हो गया. मनरेगा के प्रदेश स्तर के मॉनिटर विनोद शंकर चौबे ने आपत्ति दर्ज की थी कि मनरेगा के धन से पुलिया बनवाई जा सकती है, उससे बड़ा पुल नहीं बनवाया जा सकता. लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई. यह भी पकड़ा गया कि राजेश नाम के एक ही व्यक्ति को 50 लाख का चेक दिया गया, 75 लाख के फावड़े खरीदे गए और 20 लाख रुपये फ्रस्ट एड किट में लगाए गए.

पंधारी सबसे बड़ा बंटाधारी

अपने कृत्यों से आईएएस पंधारी यादव ने सरकार की साख का बड़ा बंटाधार किया. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पंधारी को अपने सचिवालय में विशेष सचिव तैनात किया. पंधारी के कारण सरकार की छवि बहुत गिरी, लेकिन मुख्यमंत्री पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ा. पंधारी यादव समेत दो दर्जन से अधिक आईएएस अफसरों पर घोटाले के आरोप हैं. सीबीआई जांच के पहले मनरेगा घोटाले की जांच ईओडब्लू कर रहा था. प्रदेश के 17 जिलों में मनरेगा के तहत अनियमितताओं की जांच के दौरान आर्थिक अपराध शाखा के तत्कालीन एडीजी एएल बनर्जी ने मिर्जापुर जिले की जांच रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंपी थी. हाईकोर्ट ने ईओडब्लू की रिपोर्ट पर सवाल खड़ा किया था और पूछा था कि जिस पैमाने पर हुई धांधली में सिर्फ छोटे अफसरों को सामने लाकर बड़ों को क्यों बचाया गया? इसके बाद ही हाईकोर्ट ने घोटाले की जांच सीबीआई को दे दी थी. जांच के दायरे में मौजूदा नौकरशाहों के अलावा बसपा सरकार में ग्राम्य विकास मंत्री रहे दद्दू प्रसाद और कृषि शिक्षा व कृषि अनुसंधान मंत्री रहे राजपाल त्यागी भी हैं.

मुख्यमंत्री सचिवालय में तैनात होने के बाद भी पंधारी यादव पंचम तल से ही सोनभद्र जिले को संचालित करते रहे थे और वहां के जिलाधिकारी का पद महीनों खाली पड़ा रहा था. पंधारी यादव जब सोनभद्र के जिलाधिकारी थे, तब तमाम गांवों की सड़कें बनी ही नहीं, लेकिन बसपा सरकार के कुछ मंत्रियों को खुश रखने के लिए पंधारी यादव सड़कों के पूरे तार बन जाने की रिपोर्ट शासन को भेजते रहे और उसका भुगतान होता रहा. तत्कालीन मुख्यमंत्री के चहेते जेपी समूह को जब वन क्षेत्रों की जमीन दी जा रही थी, तब सोनभद्र के जिलाधिकारी पंधारी यादव ही थे. खनन अधिकारी विजय कुमार ने गैर कानूनी तरीके से हजारों एकड़ वन भूमि दे दी, तब भी जिलाधिकारी पंधारी यादव ही थे. राष्ट्रीय वन जन श्रमजीवी मंच की संयोजक रोमा ने तो स्पष्ट आरोप लगाया था कि सोनभद्र में आदिवासियों का सर्वाधिक उत्पीड़न पंधारी यादव के कार्यकाल में ही हुआ. वनाधिकार कानून की आड़ में वनवासियों का शोषण किया गया और अधिकार पत्र देने में खूब अनियमितताएं की गईं. ■

feedback@chauthiduniya.com

महिला दिवस के दिन भी नहीं रुका महिलाओं के खिलाफ अपराध

सेमिनार और अत्याचार साथ-साथ

चौथी दुनिया ब्यूरो

उत्तर प्रदेश में महिला दिवस के दिन लखनऊ समेत अन्य स्थानों पर तमाम संगोष्ठियां हो रही थीं और तमाम विद्वत विचार रखे जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं पर अपराध और अत्याचार की घटनाएं हो रही थीं. संयुक्त राष्ट्रसंघ ने 1974 में आठ मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी. तब से लेकर प्रति वर्ष आठ मार्च को महिला दिवस वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है. उत्तर प्रदेश में भी प्रत्येक वर्ष आठ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों और संगोष्ठियों में महिलाओं के उत्थान, उनके सम्मान, अधिकार और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विशेष परिचर्चा का आयोजन किया जाता है. महिलाओं से जुड़े मामलों जैसे महिलाओं की स्थिति, कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं की सुरक्षा और विशेष रूप से उनके खिलाफ होने वाले अपराध पर भरपूर भाषणबाजी होती है या यूं कहें परिचर्चा की औपचारिकता भर निभाई जाती है. लेकिन असलियत में जहां आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़-छाड़, एसिड अटैक और कन्या को गर्भ में मार देने की साजिश चल रही हो, वहां नारी सशक्तीकरण एवं उसके सम्मान की चर्चा करना बेमानी है.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि भारत में प्रतिदिन बलात्कार के करीब 50 मामले थानों में पंजीकृत होते हैं. इस प्रकार भारतभर में प्रत्येक घंटे दो महिलाएं बलात्कार का शिकार होती हैं. लेकिन ये आंकड़े पूरी तरह सच नहीं होते. बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट दर्ज ही नहीं की जाती. उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय है. पिछले तीन वर्षों में सपा सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश महिलाओं पर हो रहे आपराधिक मामलों में अव्वल रहा है. पिछले साल सिर्फ छह महीनों में ही राष्ट्रीय महिला आयोग को देशभर से महिलाओं के साथ हुए अपराधिक घटनाओं की कुल 3868 शिकायतें मिलीं, जिनमें सबसे ज्यादा 2079 शिकायतें उत्तर प्रदेश से थीं. आयोग को प्रदेश से महिलाओं पर एसिड अटैक की 12 शिकायतें, हत्या के प्रयास की 42 घटनाएं, बलात्कार की कोशिश की 206, जाति या समुदाय आधारित हिंसा की 123, घरेलू हिंसा की 1316 और बलात्कार की 308 शिकायतें मिलीं. महिला आयोग की रिपोर्ट के अलावा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े तो यूपी में महिला अत्याचारों की और ही भयावह रिपोर्ट पेश करते हैं. पिछले साल छह महीने में ही यूपी में रेप के 1689 मामले, दहेज हत्या के 1243 मामले, छेड़खानी के 381 और शील भंग के 3778 मामले सामने आए थे. आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा के अनुसार पिछली बसपा सरकार की तुलना में अखिलेश सरकार में महिलाओं उत्पीड़न के मामलों में बढ़ोतरी हुई है. इसकी पुष्टि आरटीआई से प्राप्त जानकारी से होती है. उर्वशी ने बताया कि उन्होंने आरटीआई के तहत यूपी महिला आयोग से इसकी जानकारी मांगी थी. प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सपा सरकार असंवेदनशील है. यदि मायावती सरकार से तुलना करें तो महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों में 42 फीसदी बढ़ोत्तरी हुई है. वहीं मामलों के निस्तारण में 45 फीसदी की कमी आई है. आयोग से मिली जानकारी के अनुसार मायावती शासनकाल में महिला उत्पीड़न के 55301 मामले दर्ज हुए थे. अखिलेश सरकार के शुरुआती ढाई साल में यह मामले बढ़कर 78483 हो गए. इन सारे आंकड़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं रह गई हैं. प्रशासन व्यवस्था दुरुस्त करने का दावा करने वाली सपा सरकार का महिलाओं की सुरक्षा के मामले में अबतक का प्रदर्शन बेअसर रहा है.

सरकार की अक्षमता के कारण उत्तरप्रदेश में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब वे घर में घुसकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं. सिरौली थाना क्षेत्र में एक महिला शिक्षक द्वारा छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसी के सहयोगी शिक्षक ने महिला के घर में घुस कर उसको तेल छिड़क कर जलाया. आरोपी अपने परिवार के साथ फरार है. पुलिस अभी तक उसको तलाश ही रही है. इसी तरह कानपुर के नौबस्ता एरिया में अकेली महिला के साथ टीटीई शिक्षक ने रेप किया. आरोप है कि महिला के पति के काम पर जाने के बाद उसी घर में ऊपर की मंजिल पर रहने वाला टीटीई जितेंद्र कुमार दोपहर को मौका देखकर महिला के घर में घुस गया और दुपट्टे से हाथ-पैर बांधकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद वह भाग निकला. मौके पर आई पुलिस ने टीटीई की तलाश में काफी दबिश दी, लेकिन अपराधी पकड़ा नहीं गया. इस तरह की कई घटनाएं हैं जो पुलिस की असफलता बयान करती हैं.

आजमगढ़ में किशोरी के साथ हुई सामूहिक दुराचार की घटना, बागपत जिले के छपरौली में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म, मुजफ्फरनगर के ककरौली में भी नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार, गजियाबाद के मोदी नगर में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म तथा बिजनौर के धामपुर में दुराचार और सीतापुर में तो महिला के साथ कार में दुराचार के बाद उसे बाहर फेंक देने की घटना से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में शासन और पुलिस व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है. अपराधी प्रदेश में फैली इस अराजकता का भरपूर लाभ उठाते हुए दुष्कर्मों को निर्भीकता से अंजाम दे रहे हैं. जनता की सेवा में समर्पित उत्तर प्रदेश की पुलिस भी महिलाओं के साथ छेड़खानी और बलात्कार में पीछे नहीं है. लखीमपुर खीरी में सिपाहियों द्वारा लड़की का अपहरण कर थाने लाकर उसके साथ दुष्कर्म करने और बाद में उसकी हत्या कर पेड़ से लटका दिए जाने की घटना के भी अधिक दिन नहीं बीते हैं.

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो जनवरी-फरवरी 2015 में महिलाओं के साथ रेप की 11 घटनाएं और छेड़छाड़ के 10 मामले सामने आए. ये आंकड़े प्रदेश में महिलाओं की स्थिति, शासन व्यवस्था और पुलिस के कार्यप्रणाली की दयनीय एवं वीभत्स तस्वीर पेश करती है.

राजधानी के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के बलसिंहखेड़ा गांव के प्राथमिक विद्यालय में महिला के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में यूपी पुलिस की कार्रवाई और दावों पर स्थाई सवाल खड़े हैं. तमाम तकनीकी जांच के बाद उक्त महिला के साथ रेप किए जाने की पुष्टि हुई थी, लेकिन महिला एडीजी सुतापा सान्याल का वह दावा कि महिला के साथ कोई रेप की घटना नहीं हुई, आज भी संजीदा लोगों के दिलो-दिमाग में करंट पैदा करता है. इस मामले को पीड़िता के परिवार वाले एवं राजनीतिक दलों और समाजिक संगठनों ने सीबीआई से जांच कराने की मांग की लेकिन प्रदेश सरकार ने यह मांग नहीं मानी.

लखनऊ के गणेशगंज में हाल ही गौरी श्रीवास्तव हत्याकांड ने तो क्रूरता की हदें पार कर दी हैं. किशोरी की हत्या के बाद लाश के टुकड़े-टुकड़े कर बोरे में कस कर फेंक दिया गया था. इस मामले में भी पुलिस की कार्रवाई संदिग्ध रही. पुलिस अलग राग आलापती रही और तथ्य कुछ और ही बताते रहे. इसी तरह इंदिरा नगर में बुजुर्ग महिला कृष्णा की हत्या उन्हीं के बाथरूम में सिर कुचल कर दी गई. पुलिस अभी तक इस हत्याकांड का सुराग नहीं तलाश पाई है. महिलाओं के साथ हुए अनेक आपराधिक घटनाएं घटी जिसका खुलासा पुलिस नहीं कर पाई है. प्रदेश भर में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं की सुरक्षा, उनके हितों की रक्षा और उसके सम्मान को लेकर आयोजन हो रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर महिलाओं पर हो रहे अपराध को रोका कैसे जाए. सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वैसे तो बहुत से प्लान तैयार किए हैं लेकिन उसके क्रियान्वयन पर कितना गंभीर है असका अंदाजा तो प्रदेश में बढ़ रहे अपराध से ही लगाया जा सकता है. प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वूमेन पावर लाइन-1090 शुरू की गई, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं के साथ हो रहे अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है. लखनऊ में वूमेन पावर लाइन होने के बावजूद महिलाओं के साथ अपराध और अत्याचार कैसे हो रहे हैं, यह सवाल सामने है. वूमन पावर लाइन होते हुए मोहनलालगंज में युवती के साथ बर्बर गैंगरेप हो जाता है. चिनहट और महानगर इलाके में दो-दो महिलाओं का कत्ल कर सार्वजनिक स्थानों पर फेंक दिया जाता है. ऐसी सिलसिलेवार हो रही घटनाएं वूमन पावर लाइन जैसी व्यवस्था के नाकारेपन की गाथा गाती हैं.

कुछ महिला खुद से साहस कर अपनी रक्षा करने के लिए आगे आती हैं तो उनको पुलिस और जनता से सहयोग नहीं मिल पता. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ही सरोजनी नगर की रेनू साहस कर लुटेरे से भिड़ गईं. अकेली और निहत्थी होने के बावजूद वह बिलकुल नहीं डरीं और इयर रिंग छीनकर भाग रहे बदमाश को दौड़ाकर पकड़ लिया. इसी बीच, वहां दुबग्गा चौकी इंचार्ज पहुंच गए और बदमाश को गिरफ्तार कर लिया. रेनू के अनुसार आसपास काफी लोग थे लेकिन सभी तमाशबीन बने रहे. किसी को मदद के लिए आगे आते न देख लुटेरे का दुस्साहस भी बढ़ा लेकिन रेनू ने लुटेरे के सामने हार नहीं मानी. ऐसे में अगर उसे तमाशबीनों से सहयोग मिल जाता तो उसे इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती.

सिर्फ वूमेन पावर लाइन-1090 की शुरुआत करने से ही अपराध नहीं थम सकता. इसके साथ ही पुलिस और आम जनता का सहयोग भी जरूरी है. अपराधी के मन में डर पैदा करना बहुत जरूरी है जिससे वे अपराध करने के पहले हजार पर सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा. इसके लिए सरकार को सख्त कानून व्यवस्था लाने और पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है. नहीं तो आए दिन हो रहे महिलाओं का उत्पीड़न कम होने के बजाय बढ़ता ही जाएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

रावत की बेमानी घोषणाओं पर उठ रहे हैं सवाल

राजकुमार शर्मा

पिछले वर्ष मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा की गई तमाम घोषणाएं अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाई हैं. इससे अब उनके द्वारा अंधाधुन किए जा रहे घोषणाओं पर सवाल खड़े होने लगे हैं. मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पिछले वर्ष अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक चमोली जिले के आगमन पर ढेर सारी घोषणाएं कर जनता की वाहवाही लूटी थी. इसके बावजूद, उनकी घोषणाओं के धरातल पर न उतर पाने के कारण लोग अपने को ठगा सा भी महसूस करने लगे हैं. 13 अक्टूबर को सीएम पोखरी मेले के उद्घाटन को पहुंचे थे तो तब उन्होंने कार्तिक स्वामी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा के साथ ही पोखरी में टैक्सी स्टैंड के निर्माण और नगर के विकास के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने की घोषणा की थी. यही नहीं, पोखरी में राजीव गांधी अभिनव स्कूल की स्थापना का भी उन्होंने ऐलान किया था. इसके बाद हरीश ने 4 नवंबर को गैरसैंण में आयोजित उद्यान, कृषि तथा विकास मेले के उद्घाटन को पहुंचे तो यहां उन्होंने भराड़ीसैंण में सचिवालय भवन निर्माण के अलावा गैरसैंण-भराड़ीसैंण को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं. इसी मौके पर थराली को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने का ऐलान भी किया था. बीते 14 नवंबर को गौचर मेले के उद्घाटन को पहुंचे मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यहां भी घोषणाओं की झड़ी लगाकर रख दी थी. गौचर तथा कर्णप्रयाग को नगर पालिकाओं का दर्जा दिए जाने के साथ ही घाट को नगर पंचायत का दर्जा देने का ऐलान तो मुख्यमंत्री ने किया ही, बल्कि नंदप्रयाग में तहसील स्थापना की घोषणा भी कर दी गई. इसी तरह सीएम के प्रतिनिधि के रूप में काबिना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने भी 5 दिसंबर को अनुसूया मेले के उद्घाटन के अवसर पर जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान मंडल को पुनर्जीवित करने के साथ ही एचआरडीआई में निदेशक की जल्द नियुक्ति, बैरागना में एएनएम सेंटर, बैरागना इंटर कॉलेज के नये भवन के निर्माण, बैरागना खेल मैदान को मिनी स्टेडियम, राजकीय एलोपेथिक चिकित्सालय मंडल के उच्चीकरण तथा मेले को राज्यस्तरीय मेला घोषित करने की घोषणा की थी. फिर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के बतौर ही काबिना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी 7 दिसंबर को शहीद सैनिक मेले सवाड़ तथा थराली महोत्सव में पहुंचे तो वहां भी इन्होंने सीएम की ओर से घोषणाओं की झड़ी लगाकर रख दी थी. इसके तहत उन्होंने थराली महोत्सव में देवाल में उप तहसील बनाए जाने, नन्दकेशरी से ग्वालदम पंपिंग पेयजल योजना बनाने, पैंतोली में वानिकी कृषि महाविद्यालय स्थापित करने समेत ग्वालदम में पर्यटन प्रबधंन प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने, वाण-वेदनी रोपवे निर्मित किए जाने का ऐलान किया था. इसी दिन सवाड़ मेले में डिग्री कालेज तलवाडी में भूगोल तथा अर्थशास्त्र विषयों की घोषणा करते हुए इन्होंने आली-बेदनी तक रोपवे तथा विभिन्न सड़कों के निर्माण किए जाने का ऐलान भी किया. 26 दिसंबर को पीपलकोटी के बंड मेले में पहुंचे मुख्यमंत्री रावत ने मुख्य रूप से बंड मेले के सांस्कृतिक मंच के लिए 10 लाख रुपये दिए जाने की घोषणा की. इसके साथ ही पीपलकोटी को नगर पंचायत का दर्जा देने का ऐलान भी किया. टीएचडीसी के माध्यम से उच्चस्तरीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने, जोशीमठ में ट्रामा सेंटर, पीपलकोटी व जोशीमठ के मध्य सीएचसी की स्थापना के साथ ही अन्य कई घोषणाएं की थी. राज्य के नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट जी मुख्यमंत्री रावत को डपोरशंखी मुख्यमंत्री मानते हैं. चमोली की जनता भी हरीश को घोषणा नाथ के नाम से समझने लगी है. स्थानीय लोग मानते हैं कि हरीश की कथनी-करनी में बदलती तो इससे चमोली का कायाकल्प हो जाता. फिर भी अभी तक घोषणाओं के धरातल पर न उतरने से लोग अपने को ठगा सा महसूस करने लगे हैं. अब लोगों को इंतजार यही है कि हरीश की घोषणाएं कब तक धरातल पर उतर पाएंगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

मोदी के सपनों को साकार करेंगे हरीश

उत्तराखंड की हरीश रावत की सरकार केदारनाथ पैदल मार्ग को जीरो प्लास्टिक जोन बना कर प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ केदार के सपनों को साकार बनाएगी. यात्रियों को यात्रा शुरू करते समय सरकार की ओर से एक थैला उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि इसमें कूड़ा-कचरा आदि रख सकें. बाद में कचरे से भरे थैले को कलेक्शन प्वॉइंट पर वापस ले लिया जाएगा. मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चारधाम व हेमकुंट साहिब यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान यह मंशा प्रकट की. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष यात्रा को शुरू किया गया था. इस वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ सकते हैं, इसलिए तैयारियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए. स्थानीय लोगों को भी यात्रा के माध्यम से अपनी आजीविका के पर्याप्त अवसर मिल सकें. इसीलिए सरकार का लक्ष्य है कि इस बार चारधाम यात्रा पहले से कम से कम 50 प्रतिशत यात्रियों को लाया जा सके. इन्होंने निर्देश दिए कि इसके लिए यात्रियों के रुकने, खाने, शौचालय व बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन की फुलप्रूफ व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. इन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के केंद्रों को जनरेटर व बैट्री का बैकअप दिया जाए. केदारनाथ पैदल मार्ग पर विशेष ध्यान दिया जाए. लेक्सी शौचालयों के स्थान पर स्थायी प्रकृति के प्रीफेब शौचालय बनाए जाएं. जानकी चट्टी, सोनप्रयाग व गोविंदघाट में अस्थायी गैस एजेंसी खोली जाए. यात्रियों के बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के चार केंद्र बनाए जा रहे हैं. केदारनाथ मार्ग पर सीतापुर में रुकने की कोई समस्या नहीं है, जबकि गौरीकुंड, जंगलचट्टी, भीमबली, लेनचोली, बड़ा लेनचोली, केदारनाथ बेस कैंप, केदारनाथ हेलीपैड क्षेत्र व केदारपुरी में कुल मिलाकर चार हजार लोगों के ठहरने की समुचित व्यवस्था है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि टेंट आदि में स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए. मंदिर समिति एक-दो जगह प्रसाद आदि नि:शुल्क उपलब्ध करवा सकती है. शेष स्थानों पर वाजिब दरों पर यात्रियों को भोजन उपलब्ध करवाया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि बदरीनाथ मार्ग पर भी विशेष ध्यान रखना होगा. गोविंदघाट, पुलना व पांडुकेश्वर में अतिरिक्त टेंट लगाए जाने के लिए भूमि चिन्हित कर ली जाए. चमोली जिले के जिलाधिकारी ने बताया कि बदरीनाथ में आठ से नौ हजार यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है. 12 स्थानों पर सुलभ द्वारा 400 नए शौचालय बनाए जा रहे हैं. गंगोत्री व यमुनोत्री मार्ग में निजी व सरकारी दोनों में 12 हजार यात्रियों के ठहरने की सुविधा है. इस अवसर पर, केदारनाथ-बदरीनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष गणोश गोदियाल, विधायक व संसदीय सचिव शैलारानी रावत, राजेंद्र भंडारी, विधायक सुबोध उनियाल, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने रावत सरकार की सराहना की. ■

feedback@chauthiduniya.com

हिमालयी काला तीतर के संरक्षण के लिए चौथी बर्ड सेंचुरी

चौथी दुनिया ब्यूरो

उत्तराखंड की सबसे बड़ी और चौथी बर्ड सेंचुरी या बर्ड कंजरवेशन रिजर्व जल्द ही वजूद में आ जाएगा. नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजरवेशन रिजर्व (एनडीएटबीसीआर) की घोषणा की तैयारी हो गई है. उत्तराखंड में तीन बर्ड कंजरवेशन रिजर्व पहले से हैं. देहरादून में आसन, हरिद्वार में झिलमिल व नैनीताल में पवलगढ़. नैनादेवी हिमालयन बर्ड कंजरवेशन रिजर्व उत्तराखंड का सबसे बड़ा बर्ड कंजरवेशन रिजर्व होगा. 112 वर्ग किलोमीटर में फैले इस बर्ड कंजरवेशन रिजर्व में 200 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी हैं. इस क्षेत्र में राज्य के सबसे बेहतर बांज के जंगल भी हैं. हिमालयी काला तीतर अब एक विलुप्त पक्षी प्रजाति है. नैनीताल के करीब होने के कारण इस रिजर्व में खूबसूरत जंगल हैं और इको टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक डीवीएस खाती का कहना है कि इस क्षेत्र में जानी-मानी बर्ड वाचिंग साइट्स किलबारी व पंगोट भी हैं. पर्यटन गतिविधियों की देखरेख के लिए कुमाऊं के मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में बनने वाली कार्यकारी समिति में एनजीओ, स्थानीय समुदाय के लोग व वन विभाग के अधिकारी होंगे. संभावित रिजर्व के करीब पंगोट गांव में राज्य का सबसे पुराना बर्ड वाचिंग लॉज है. मुख्य वन संरक्षक व पक्षी विशेषज्ञ डॉ. धनंजय मोहन का कहना है कि नैना देवी को एक कंजरवेशन रिजर्व बनाने का विचार सबसे पहले 2013 की राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में पेश हुआ था. नैनीताल की प्रभागीय वन अधिकारी तेजस्विनी पाटिल ने गांव वालों से विचार विमर्श के बाद राज्य वन्यजीव बोर्ड को अपनी रिपोर्ट पेश की थी. यह रिपोर्ट केंद्र व राज्य सरकार को सौंपी गई थी, जिसमें अब इस क्षेत्र को कंजरवेशन रिजर्व घोषित करने का फैसला लिया है. धनंजय मोहन का कहना है कि कंजरवेशन रिजर्व घोषित होने से इस इलाके के लिए राज्य सरकार से ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्डलाइफ हैबिटेट स्कीम के तहत वित्तीय सहायता मिल सकेगी. उनका कहना है कि कंजरवेशन रिजर्व घोषित होने से क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा तथा स्थानीय लोग वन संरक्षण व पर्यटन गतिविधियों से अपनी आर्थिकी और मजबूत कर सकेंगे. इस इलाके में बहुत सी संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियां मिसाल के तौर पर चीड़ फीजेंट आदि पाई जाती हैं. यही वह इलाका है जहां 1876 में अंतिम बार हिमालयी काला तीतर (हिमालयन क्वेल) देखा गया था. ■

feedback@chauthiduniya.com

मोदी के खिलाफ कांग्रेस अमर्यादित बयानबाजी कर रही है

चौथी दुनिया ब्यूरो

कांग्रेस के दिग्गज इन दिनों चर्चा में रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति अर्नगल बयानबाजी का सहारा ले रहे है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसा बयान दिया है जिससे राजनीति में उबाल आ गया है. सूबे में जगह जगह सड़क पर उतर कर भाजपाई किशोर का पुतला फूक रहे है. किशारे ने न सिर्फ विवादास्पद बयान दे डाला बल्कि हद तो यह है कि वह इस पर अड़े भी हैं. उपाध्याय का कहना है कि प्रधानमंत्री को न तो अपनी मां की चिंता है और न ही गंगा की सुध है. गंगा की दुर्दशा सुधारने को लेकर वह राज्य की उपेक्षा कर रहे हैं. राज्य की उपेक्षा और गंगा के अपमान को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी का भी जवाब में पुतला दहन कर जवाबी कार्यवाही किया. कांग्रेस अध्यक्ष के विवादित बयान को लेकर भाजपा के अनेक दिग्गजों ने विधानसभा के अन्दर और बाहर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है. भाजपा के नेताप्रतिपक्ष अजय भट्ट इसे कांग्रेस की तुक्ष्य मानसिकता बताते हुए कहते है कि इसके लिए सूबे के मुख्यमंत्री को क्षमायाचना मांगना चाहिए. कई भाजपा नेता किशोर को मानसिक रूप से बीमार बताने से नही चूक रहे हैं. किशोर का कहना है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है. गंगा उत्तराखंड की पुत्री हैं और मोदी ने गंगा रक्षा का आह्वान कर सत्ता हासिल की है. झूठ बोल गंगा की दुर्दशा सुधारने को लेकर वह राज्य की उपेक्षा कर रहे हैं. मोदी और उनकी माता को लेकर बीते रोज की गई टिप्पणी पर अडिग रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय इन दिनों एक तो चोरी, दूजे सीनाजोरी पर अमादा हैं. उन्होंने भाजपा को रावण करार दिया. लोकसभा चुनाव में भाजपा के हाथों करारी शिकस्त से तिलमिलाई प्रदेश कांग्रेस को केंद्रीय मदद में उत्तराखंड की उपेक्षा के रूप में भाजपा ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सियासी वार करने का मौका मिल गया है. केंद्रीय सहायता और केंद्रीय योजनाओं में कटौती के विरोध में प्रदेश कांग्रेस 24 मार्च को प्रधानमंत्री आवास पर सत्याग्रह का ऐलान कर चुकी है. उपाध्याय की टिप्पणी को भले ही जुबान फिसलना करार दिया जाए, वह अपने बयान पर अडिग हैं. साथ ही इन्होंने फिर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से मुखातिब किशोर उपाध्याय ने इसी अंदाज में भाजपा पर प्रहार किया. उन्होंने कहा कि भाजपा ने भगवान राम को धोखा दिया. वह रावण है. प्रदेश कांग्रेस की टिप्पणी ने सियासी बवाल का रूप ले लिया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

भूरा के फरार होने के सौ दिन बाद भी उत्तराखंड पुलिस खाली हाथ

रेनु शर्मा

पुलिस की कस्टडी से 15 दिसंबर, 2014 से फरार गैंगस्टर अमित मलिक उर्फ भूरा फरारी की घटना के सौ दिन व्यतीत होने के बावजूद भी उत्तराखंड पुलिस के लिए एक अबुझ पहेली बना हुआ है. भूरा की फरारी घटना ने तीन राज्यों की पुलिस को नाकों चने चबवा दिए हैं. रुड़की जेल कांड के आरोपी भूरा की फरारी के मामले में दून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय रौतेला को कुर्सी गंवानी पड़ी थी. इसके बाद हरकत में आए पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड ने उत्तराखंड, दिल्ली और यूपी पुलिस के साथ ऑपरेशन भूरा की कामयाबी के बड़े दावे किए थे, जो अब तक हवा हवाई ही सिद्ध हुए हैं.

नोएडा में कंट्रोल रूम बनाने के साथ डीआईजी, एसटीएफ और एसएसपी दून को वहां कैंप कराया गया. उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड पुलिस ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए भूरा पर पांच-पांच लाख का इनाम घोषित किया था. कुछ दिन तो ठीक चला. श्रेय लेने की होड़ में तीनों राज्यों की पुलिस की राह बदल गई. पुलिस के दिग्गज सर्विलांस से लेकर सौदेबाजी तक का फंडा अपना चुके हैं, लेकिन भूरा को पकड़ना तो दूर उसकी लोकेशन तक का पता नहीं चल पाया है. भूरा मामले में जो कामयाबी हाथ लगी भी, वह मैनेजमेंट का हिस्सा रही है. पुलिस कितना भी दावा करे, सच तो यही है कि भूरा गैंग ने ही दबाव कम करने के लिए पुलिस को अपनी भूल-भूलैया में फंसाए रखने के लिए तथाकथित कामयाबी की राह दिखाई, जो अन्तत: ढाक के तीन पात सिद्ध हुए.

> "ऑपरेशन भूरा में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती गई है. प्रयासों का ही नतीजा रहा है कि उसे छुड़ाने वाले अधिकतर गुर्गे पकड़े गए हैं. अमित उर्फ भूरा और उसका साथी सचिन खोखर पर कार्रवाई चल रही है. हाल में ही सचिन पुलिस को चकमा दे गया. भूरा भी ज्यादा दिन नहीं भाग पाएगा."
>
> *- बीएस सिद्धू, पुलिस महानिदेशक*

पहली कड़ी में सरकारी असलहा लौटाए गए हैं और फिर एक-एक 11 मददगार कानून की गिरफ्त में आते चले गए. भूरा का सुराग नहीं मिल पाया. भूरा के मामले में यूपी पुलिस से कामयाबी की ज्यादा उम्मीद थी. पश्चिमी यूपी की पुलिस और एसटीएफ उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी. इस नाकामयाबी का असर यह है कि ऑपरेशन भूरा को लेकर अब न तो सरकार और न ही पुलिस गंभीर नजर आ रही है. पुलिस की माथापच्ची का नतीजा कम से कम यही इशारा कर रहा है. फरार होने के बाद भूरा दिल्ली-एनसीआर से बाहर नहीं गया है. दिल्ली पुलिस के लिए काफी समय चुनौती बने एक लाख रुपये के इनामी नीरज बवाना और भूरा के साथ होने के कयास भी पुलिस लगा रही है. तमाम ऑफर के बाद भी इस गैंग में सेंधमारी करने में पुलिस विफल रही है. इसी बीच मुकीम गैंग की ताबड़तोड़ घटनाओं ने वेस्ट यूपी पुलिस की प्राथमिकता बदल दी है. अब हर किसी की निगाह मुकीम गैंग पर टिकी है. ऑपरेशन भूरा में जुटी उत्तराखंड पुलिस की टीम बिखर गई है. डीआईजी और एसएसपी भूरा को दरकिनार कर अपने कामकाज में जुट गए हैं. अपर पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर को हटाकर कुंभ मेला ड्यूटी में भेज दिया गया है. ऑपरेशन की कमान संभालने वाले आईपीएस सदानंद दांते अब एसटीएफ से हट गए हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

सरकार पर भ्रष्टाचार के छींटे

अखिलेश सीबीआई से क्यों बच रहे हैं

दीनबंधु कबीर

बेपनाह काली सम्पत्ति के स्वामी यादव सिंह को बचाने में उत्तर प्रदेश सरकार जी-जान से लगी है. दरअसल, यादव सिंह को बचा कर अखिलेश यादव की सरकार खुद का बचाव कर रही है, क्योंकि यादव सिंह की काली सम्पत्ति का ब्यौरा खुला तो समाजवादी सरकार के कई धुले-पुते चेहरों की असलियत सामने दिखने लगेगी. यही वजह है कि यादव सिंह प्रकरण में उत्तर प्रदेश सरकार कभी गलत हलफनामा दाखिल करती है तो कभी मामले की सीबीआई जांच के आदेश को ताक पर रखने की गैर-कानूनी कोशिश करती है. जानकार कहते हैं कि यादव सिंह प्रकरण की जांच के लिए कथित न्यायिक आयोग का गठन भी मामले की लीपापोती के ही सरकारी इरादे की अभिव्यक्ति है.

यादव सिंह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने उत्तर प्रदेश सरकार पर तथ्यों को छिपाने और हाईकोर्ट के सामने गलतबयानी करने का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्रालय ने 24 फरवरी को ही उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को पत्र भेज कर यादव सिंह प्रकरण से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र के इस निर्देश पर कोई कार्रवाई नहीं की, यहां तक कि केंद्र के इस पत्र का हाईकोर्ट के समक्ष जिक्र भी नहीं किया. उन्होंने पूरक हलफनामा दाखिल कर वित्त मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजे गए आदेश की प्रति प्रस्तुत की जिसमें भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से कालेधन पर बने एसआईटी के आदेशों पर यादव सिंह मामले के सभी अभिलेख सीबीआई को देने के निर्देश दिए थे.

सीबीआई जांच से बचने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्मा आयोग की अधिसूचना जारी कर दी, जो पहले से लंबित थी. अधिसूचना के मुताबिक एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस-वे के निलंबित मुख्य अभियन्ता यादव सिंह द्वारा अपने पद पर कार्यरत रहते हुए निर्माण कार्य के ठेकों में संगठित एवं व्यापक रूप से की गई अनियमितताओं, पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की जांच करेगा. जांच आयोग के अध्यक्ष अवकाशप्राप्त जज अमरनाथ वर्मा ने मामले की जांच की औपचारिकताएं शुरू भी कर दी.

यादव सिंह मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गृह विभाग और नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल किया गया हलफनामा सरकार के लिए ही मुसीबत बन गया है. दोनों हलफनामे से सीबीसीआईडी जांच और नोएडा विकास प्राधिकरण पर कई सवाल खड़े हो गए हैं. हलफनामे से खुलासा हुआ है कि आरोपी की मांग पर सरकार ने मामले की जांच सीबीसीआईडी को ट्रांसफर कर दी थी. नोएडा प्राधिकरण के आरपी सिंह ने 13 जून 2012 को सेक्टर-39 में जो एफआईआर दर्ज कराई थी, उसमें यादव सिंह के साथ परियोजना इंजीनियर रामेन्द्र को भी कमीशनखोरी में अभियुक्त बनाया गया था. रामेंद्र 28 नवम्बर 2014 को आयकर विभाग के छापे में यादव सिंह के घर पर मिले थे और उन्होंने स्वीकारा था कि प्रत्येक अनुबंध (अवॉर्ड) में अवैध कमिशन लिया जाता था. इसी आधार पर नोएडा प्राधिकरण ने आठ दिसंबर 2014 को रामेन्द्र को निलंबित कर दिया था. इससे दो साल पहले जब यादव सिंह समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर में जिन तथ्यों के आधार पर आरोप लगाया गया था, इनकम टैक्स के छापे के बाद वही तथ्य सही साबित हुए. लेकिन सीबीसीआईडी ने उन्हीं आरोपों को नकारते हुए मामले में अंतिम रिपोर्ट लगा दी.

सरकार ने यादव सिंह के साथ 954 करोड़ के घोटाले के अभियुक्त जेएसपी कंस्ट्रक्शन के संजय जैन के अनुरोध पर जांच को नोएडा पुलिस से लेकर सीबीसीआईडी की क्राइम ब्रांच को दे दिया था. सीबीसीआईडी ने तीन जनवरी 2014 को फाइनल रिपोर्ट लगा दी. बाद में तीन सितंबर 2014 को मुकदमे का वादी आरपी सिंह भी एफआईआर से मुकर गया. इससे साफ जाहिर हुआ कि यादव सिंह और अन्य आरोपियों को बचाने का नियोजित कार्यक्रम चल रहा था. इसके तहत पहले आरोपी के कहने पर जांच सीबीसीआईडी को दी गई और बाद में वादी को मुकरने का निर्देश दे दिया गया. नोएडा की स्पेशल कोर्ट (एससी/एसटी) ने 21 नवंबर 2014 को सीबीसीआईडी की फाइनल रिपोर्ट स्वीकार कर ली. सीबीसीआईडी की जांच को ही अदालत में चुनौती दी गई है.

गृह विभाग के प्रमुख सचिव देवाशीष पंडा के हलफनामे से भी सीबीसीआईडी जांच की सच्चाई सामने आ जाती है. तथ्य बताते हैं कि यादव सिंह और रामेन्द्र ने 8 दिनों में 954.38 करोड़ के बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए. 08 दिसंबर 2011 को तिरुपति कंस्ट्रक्शन और जेएसपी कंस्ट्रक्शन को भूमिगत 33/11 केवी केबल का 92.06 करोड़ का ठेका मिला. जबकि ठेका मिलने के पहले ही 60 फीसदी काम पूरा दिखा दिया गया. गुणवत्ता जांचने वाली कंपनी राइट्स ने भी आपत्ति जताई. यह भी भेद खुला कि गड्ढों को भरने के तीन अनुबंधों के पेमेंट काम से पहले ही हो गए. लेकिन गृह विभाग के प्रमुख सचिव देवाशीष पंडा का हलफनामा इन सब आरोपों को बेबुनियाद बताता है और कहता है कि इनके कोई साक्ष्य नहीं पाए गए. हलफनामे में राइट्स को ही दोषी ठहराते हुए सीबीसीआईडी जांच को पूरी तरह सही करार दिया गया है. विडंबना यह है कि मुकदमा लिखाने वाला आरपी सिंह ही अदालत के सामने पलट गया और उसके अनुरोध पर गौतमबुद्ध नगर के स्पेशल जज ने सीबीसीआईडी की रिपोर्ट स्वीकार भी कर ली.

उल्लेखनीय है कि विदेशों में जमा कालेधन की जांच करने वाली एसआईटी ने ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के मुख्य इंजीनियर रहे यादव सिंह के घोटालों की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश कर रखी है. एसआईटी को उम्मीद है यादव सिंह का पैसा कालेधन के रूप में निवेश किया गया है. सीबीआई की जांच शुरू होने के बाद यादव सिंह के कुकृत्य प्रवर्तन निदेशालय के दायरे में भी आ जाएंगे. एसआईटी की सिफारिश के मद्देनजर ही केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को मामले से सम्बन्धित दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का निर्देश भेजा था. लेकिन यूपी सरकार ने केंद्र की बात नहीं मानी. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित एसआईटी ने पहले यह भी कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार लोकायुक्त से यादव सिंह के भ्रष्टाचार की जांच कराए, लेकिन सरकार इसे भी कानूनी गुत्थियों में उलझाने की कोशिश करती रही. सरकार का कहना था कि मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए इस पर अभी इंतजार किया जाए. राज्य सरकार के इस टालू रुख को देखते हुए ही एसआईटी ने अपनी औपचारिक बैठक के बाद सीबीआई को निर्देश दिया कि यादव सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया जाए. लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी कीमत पर इस मामले की सीबीआई से जांच नहीं होने देना चाहती. उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट से कहा है कि यादव सिंह मामले की सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है. इसके लिए प्रदेश सरकार ने न्यायिक आयोग की जांच को ढाल बनाया है. यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में बाकायदा याचिका दाखिल कर यह बात कही है. भ्रष्टाचार के ऐसे गंभीर प्रकरण पर अखिलेश सरकार के रवैये पर विपक्ष में भी खासी नाराजगी है. विपक्ष का आरोप है कि कुछ तो ऐसा है जिसे अखिलेश सरकार सामने नहीं लाना चाहती. भाजपा नेता विनय कटियार ने कहा कि यादव सिंह के भ्रष्टाचार मामले की सीबीआई से जांच होनी ही चाहिए. यादव सिंह का मसला भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है. सरकार इस मामले की सीबीआई जांच क्यों नहीं चाहती, यह सबको पता है. कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी भी कहते हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों रुपये के घपले का मामला है. उन्होंने कहा, मैं नहीं समझ पा रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सीबीआई जांच का विरोध क्यों कर रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सीबीआई जांच से बचने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्मा आयोग की अधिसूचना जारी कर दी, जो पहले से लंबित थी. अधिसूचना के मुताबिक एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस-वे के निलंबित मुख्य अभियन्ता यादव सिंह द्वारा अपने पद पर कार्यरत रहते हुए निर्माण कार्य के ठेकों में संगठित एवं व्यापक रूप से की गई अनियमितताओं, पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की जांच करेगा.

बर्थ-डे पर तो नहीं खर्च हुआ था यादव सिंह का पैसा!

रामपुर में मुलायम सिंह यादव का भव्य जन्म दिवस समारोह मनाने पर हुए आलीशान खर्च पर सवाल उठने से नाराज मंत्री आजम खान ने कहा था कि माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम और अबु सलेम के अलावा आतंकी संगठन तालिबान ने मुलायम का बर्थ-डे मनाने के लिए पैसे दिए हैं. आजम खान ने 22 नवम्बर 2014 को रामपुर में मुलायम का जन्मदिन शाहंशाहाना अंदाज में मनाया था. मुलायम भी लंदन से मंगवाई गई शाही विक्टोरिया बग्घी पर सवार होकर और 75 फुट का केक काट कर गदगद हो गए थे.

आलीशान बर्थ-डे के शाही खर्चे पर आजम खान के बेचैन जवाब की समीक्षा करते हुए सपा के एक नेता भुनभुनाए, दाऊद और सलेम का तो नहीं, पर यादव सिंह का पैसा जरूर लगा है. हालांकि सपा नेता के उक्त वक्तव्य का कोई आधिकारिक तथ्य नहीं, लेकिन सपा नेताओं से होते हुए सपा कार्यकर्ताओं के बीच चली इस चर्चा की गंभीरता तो है ही. सपा नेताओं का ही कहना था कि आजम ने दाऊद और सलेम का नाम लेकर यादव सिंह के काले धन के इस्तेमाल की चर्चा को थामने की कोशिश की थी. बहरहाल, मामले की सीबीआई जांच हो, तभी इन तथ्यों का खुलासा हो पाएगा.

यादव सिंह की भ्रष्ट कमाई का पैसा सबने बांट कर खाया

उत्तर प्रदेश सरकार के कई सफेदपोश चेहरों की कलई उन बोरों में छुपी है जो यादव सिंह के विभिन्न ठिकानों से बरामद हुए थे. यादव सिंह का असली खजाना वो कुछ सौ करोड़ रुपया नहीं है जो छापों में मिला. असली खजाना बेनामी संपत्तियों और निवेश के उन कागजातों में है, जो दर्जनों बोरे में भरे बरामद किए गए थे. इन बोरों में यूरोप समेत कई देशों में निवेश किए जाने के दस्तावेजों के अलावा नेताओं और नौकरशाहों की सम्पत्ति में हिस्सेदारी के भी सुराग बंद हैं. यही वजह है कि प्रवर्तन निदेशालय ने भी आयकर विभाग से पूरी रिपोर्ट मांगी और कालेधन की जांच करने वाली एसआईटी ने भी इसे सीबीआई से जांच कराने लायक समझा. यादव सिंह के पास से जो अरबों रुपए बरामद हुए, आखिर वह धन किसका था? सीबीआई जांच से ही इसकी गुत्थियां खुल सकती हैं. यादव सिंह की 60 कंपनियों का ब्यौरा भी खंगाला जा रहा है. 12 बोरे कागजात जमीन और पूंजी निवेश से जुड़े हैं. इनमें कुछ नेताओं-मंत्रियों के भी पूंजी-रहस्य छुपे हैं. यादव सिंह की पहुंच सीधे सत्ता तक रही है, यह बात किसी से छुपी नहीं है. मायावती की सरपरस्ती में रहे यादव सिंह को अखिलेश सरकार का भी संरक्षण कैसे मिल गया, यह सीबीआई जांच से ही पता चल पाएगा. लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि यादव सिंह के भ्रष्टाचार की कमाई का क्रीम बसपा नेताओं ने भी खाया और सपा नेताओं ने भी.